हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

28.03.2026/1100/RKS/AS-1

अध्यक्ष : प्रश्नकाल आरम्भ।

प्रश्न संख्याः 4135

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जोगिन्द्रनगर में जो मिनी सचिवालय स्थापित किया गया है उसमें काफी कमरे खाली पड़े हैं। जोगिन्द्रनगर में रेवेन्यू सेटलमेंट, एक्साइज और कई अन्य विभागों के कार्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इन सरकारी कार्यालयों को मिनी सचिवालय में शिफ्ट किया जाए। दूसरा, वहां थाना पलौन प्रोजैक्ट का कार्य शुरू होने वाला है। जोगिन्द्रनगर में ऊहल तृतीय चरण की एकोमोडेशन और कार्यालय का एक बड़ा कंपाउंड खाली पड़ा हुआ है। वहां पर जो थाना पलौन प्रोजैक्ट लग रहा है उसके अंतर्गत आसपास की चार पंचायतें, द्रुब्बल, पीपली, नौहली और ब्यूंह आ रही हैं। जहां पर ऊहल तृतीय चरण की एकोमोडेशन बनी है वहां से इस प्रोजैक्ट की दूरी लगभग 15-20 किलोमीटर है। मैं चाहूंगा कि ऊहल तृतीय चरण का जो यह इतना बड़ा कंपाउंड जिसमें पर्याप्त एकोमोडेशन और कार्यालय खाली पड़े हैं में थाना पलौन प्रोजैक्ट के कार्यालय को शिफ्ट किया।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी अच्छी बात उठाई है कि जोगिन्द्रनगर के मिनी सचिवालय में एकोमोडेशन खाली पड़ी है। इन्होंने कहा कि जोगिन्द्रनगर में दो ऑफिस निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं। **मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर वहां जगह खाली होगी तो उन दफ्तरों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने थाना पलौन प्रोजैक्ट से संबंधित कही है। अगर वहां एकोमोडेशन उपलब्ध होगी तो जब थाना पलौन प्रोजैक्ट का कार्यालय आएगा तो उसके कुछ भाग वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा।** क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस प्रोजैक्ट का एफ0सी0ए0 हो रहा है। यह अच्छी बात है कि जो सरकारी दफ्तर निजी भवनों में चल रहे हैं उन्हें खाली सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में काफी सरकारी भवन खाली पड़े हैं। मैंने इस विषय पर मुख्य सचिव और सचिव, जी0ए0डी0 से बात की है कि हम इन भवनों को जी0ए0डी0 के अधीन लेकर आगे डिप्टी कमिश्नर को आबंटित करने के

लिए अधिकृत कर देंगे ताकि जो सरकारी कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं उन्हें वहां शिफ्ट किया जा सके।

28.03.2026/1100/RKS/AS-2

प्रश्न संख्याः 4136

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वहां पर जो पहले पंचायत घर था, क्या सरकार द्वारा उसे टेक-ओवर किया जा रहा है?

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.03.2025/1105/बी.एस./ए.एस.-1

प्रश्न संख्याः 4136 क्रमांगत....

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुनिहार को इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2026 को नगर पंचायत द्वारा दर्ज किया गया है, वर्तमान में नगर पंचायत, कुनिहार प्रदेश के अन्य नवगठित नगर पंचायत की तरह कार्य कर रही है। नगर पंचायत कुनिहार के कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए नगर पंचायत कुनिहार के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार नगर पंचायत कण्डाघाट के सचिव को तथा कनिष्ठ अभियंता व लिपिक का अतिरिक्त कार्यभार नगर पंचायत अर्की के कनिष्ठ अभियंता तथा लिपिक को दिया गया है

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मंत्री जी ने दिया है वह सही है और मैं इससे संतुष्ट हूं लेकिन मेरा सप्लीमेंट्री यह है कि वहां पर अभी नगर पंचायत का अपना कोई कार्यालय, भवन नहीं है। पूर्व में जो पंचायत घर हुआ करता था, वह वर्तमान में खाली है। तो क्या विभाग द्वारा अपना जो कार्यालय उस पंचायत घर में शिफ्ट करने की कोई योजना है? माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं।

Speaker : Hon'ble PWD Minister, if you have the information you may give it to the Hon'ble Member otherwise.

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्षक्ष महोदय, इसमें जो रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया चली हुई है और जो नया भवन बनना है उसके लिए भी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही उसको पूर्ण किया जाएगा।

28.03.2025/1105/बी.एस./ए.एस.-2

प्रश्न संख्याः 4137

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बलघार में 3 साल से टेंडर नहीं लग रहा है और उसके लिए 1.4 करोड़ रुपये अवेलेबल है और जो टोटल राशि चाहिए वह 3.59 करोड़ रुपये चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह चौपाल का एक बहुत ही जरूरी हॉस्पिटल है और यह मेन रोड में पड़ता है। क्या मंत्री महोदय इसके लिए फंड के प्रावधान का आश्वासन देंगे कि दो-तीन महीने के अंदर इसके लिए आने वाले समय में फंड अवेलेबल करके इसका टेंडर लग जाएगा? यह जो कम्युनिटी हॉस्पिटल है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं ठियोग से चौपाल तक हमारा टोटल लेंथ 80 किलोमीटर के करीब है और एक्सीडेंट के लिए या फिर किसी 28.03.2025/1105/बी.एस./ए.एस.-2

भी चीज के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है। क्या सरकार दो-तीन महीने के अंदर इसके लिए बजट का प्रावधान करेंगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन में उठाया है when I was Member of Parliament, I remember at that time I had visited Baghar. कई बार इनको भी पता है, इनका प्रश्न बिल्कुल ठीक है जो फॉरेस्ट क्लीयरेंस है उसे वर्ष 2022 में देने के बावजूद और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद 1198.79 लाख राशि के विरुद्ध इनको 1.4 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग को जमा करवा दी गई है। Site Plan of this CHC is now with Chief Architect of PWD and PWD needs 30 per cent of the approved amount against the administrative

approval and i.e. 359.63 lakhs, which is required. The work of this project will start soon because all the formalities connected with the CHC and its construction, are over and I assured the Hon'ble Member that it will start soon.

28.03.2025/1105/बी.एस./ए.एस.-3

प्रश्न संख्याः 4138

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) : अध्यक्ष महोदय, मैं जाना चाहता हूं कि थानाकलां को हमने जो आदर्श हॉस्पिटल बना दिया था मगर बंगाणा का जो क्षेत्र है वह उसके आसपास का काफी क्षेत्र पड़ता है तो क्या दूसरे चरण में बंगाणा को आदर्श हॉस्पिटल बनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है, या नहीं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान थानाकलां मानकों के अनुसार वहां

श्री डी0टी0द्वारा जारी.....

28.03.2026/1110/DT/DC-1

प्रश्न संख्याः 4138 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी...

विशेषज्ञ डाक्टर्ज भी तैनात किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ व नर्सिंग स्टॉफ तैनात किया जा रहा है। जैसे 6 विशेषज्ञ डाक्टर व 6 स्टॉफ नर्सिज हैं, वह सभी दिए जा रहे हैं। फिलहाल वहां पर एक रेडियोलोजिस्ट और सर्जन की कमी है। उस कमी को भी शीघ्र पुरा कर दिया जायेगा। जैसा आप जानते हैं कि डाक्टर्ज जब अपनी एस0आर0शीप पूरी करते हैं उनको वैसे ही तैनाती दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में अल्ट्रासाउंड, एम0आर0आई0, सीटी स्कैन इत्यादी की बात है, हम आशा करते हैं कि जल्द ही ये मशीनें भी वहां उपलब्ध करवा दी जायेगी, it may take more time.

अध्यक्ष महोदय, जिला ऊना के तहसील थानाकलां में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान प्रस्तावित है। परंतु मैं समझता हूं कि एक विधान सभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान पहले

स्थापित हो जाए उसके उपरांत फिर दूसरे फेज में अन्य आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला जायेगा। इस समय प्रदेश में कुल ऐसे 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान प्रस्तावित हैं और जब यह पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएंगे उसके बाद इस पर भी विचार अवश्य किया जायेगा।

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से पूछना चाहुंगा कि यदि बंगाणा में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित नहीं किया जा सकता तो जो वर्तमान में वहां स्टॉफ की बहुत कमी है। वहां पर डाक्टर्ज के पांच पद स्वीकृत हैं जबकि केवल दो ही पद भरे हुए हैं। एक डाक्टर हमनें प्रतिनियुक्ति के आधार पर थानाकलां से वहां तैनात किया गया है। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आश्वासन चाहुंगा कि वहां पर डाक्टर्ज के पड़े रिक्त पदों को क्या ये शीघ्र भरेंगे ताकि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकते?

28.03.2026/1110/DT/DC-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, I assure the Hon'ble Member कि इन्होंने जो डाक्टर्ज की कमी बंगाणा स्वास्थ्य संस्थान में बताई है इसके अतिरिक्त और भी जो कमियां हैं, उन्हें पूरा किया जायेगा। Bangana will be properly equipped and I also assure the Hon'ble Member that so far as the matter of establising Adarsh Sawasth Santhan in his Constitutency is concerend, later on, in the second phase this matter will be taken up with the Cabinet. **फिलहाल जो प्रदेश में 70 आदर्श स्वास्थ्य जो खोले जा रहे हैं उनके कार्य को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन बंगाणा होस्पिटल की जो भी कमियां हैं उसको पूर्ण कर देंगे।**

28.03.2026/1110/DT/DC-3

प्रश्न संख्या 4139

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न श्री विपिन सिंह परमार जी व श्री केवल सिंह पठानिया जी के द्वारा भी पूछा गया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहुंगा कि सोमवार को इस प्रश्न से संबंधित सूचना की पूरी डिटेल आपको उपलब्ध

करवा दी जायेगी। अभी इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोमवार को पूरी सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

28.03.2026/1110/DT/DC-4

प्रश्न संख्या 4140

श्री चंद्र शेखर : माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं की धर्मपूर विधान सभा क्षेत्र में लगभग जो अंकडा मौजुदा दिया गया है मैं उसके संदर्भ यही कहना चाहता हूं कि वहां पर अढाई सौ से तीन सौ ऐसे टेंक बने हैं जिनकी क्षमता 1 लाख लीटर या इससे भी अधिक है। ये दो प्रकार के टेंक हैं एक वे हैं जो अभी कनैक्ट ही नहीं हो पाए हैं और वे फट रहे हैं जिससे की जनता गाढ़ी कमाई बेकार होती नजर आ रही है। दुसरे, ऐसे टेंक हैं जो लोगों की नीजि भूमि में बना दिए गये और इसके एवज में लोगों को सरकारी नौकरी देने के आश्वासन दिये गये। उस समय 1500 लोक मेरी विधान सभा के अंदर नौकरी में रखे भी गये हैं। लेकिन फिर लोगों का यह इश्यू एड्रेस नहीं हो पाया। क्योंकि प्रदेश में पिछले साल और 2024 में बहुत अधिक बरसात हुई थी जिसके कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के 10 से 15 गांव ऐसे हैं जो उस समय की बाढ़ की जद में आए। इसलिए डेढ़ लाख या दो लाख पानी के क्षमता वाले टेंक अगर फटते हैं तो उनके आस-पास के गांवों को खतरा हो सकता है। हम पी0डी0एन0ए0 में भी जो उस समय नुकसान हुआ था उसके लिए भी धनराशि उपलबध नहीं हो पा रही है। इससे दुविधाजनक परिस्थितयां पैदा हुई हैं। उसमें मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा और इसमें मुख्य मंत्री जी का भी हस्तक्षेप चाहूंगा कि पब्लिक युटीलिटी के लिए जो टेंक बने हैं इनके कारण भविष्य में जनता का कोई नुकसान न हो और इसके कारण सरकार को प्रभावित लोगों को इन टेंकों की लागत से कई गुणाा मुआवजा न देना पड़ जाए, उसके लिए समय रहते कोई योजना या बजट का एलोकेशन हो जाता ताकि उन टेंकों को हम बचा सकते।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो टेंक अभी अन-यूटिलाइज पड़े हैं और फट रह हैं उसके लिए भी एक कमेटी गठित करके उनकी जांच कर ली जाए और उन टेंकों में भी पानी भरवाने की व्यवस्था की जाए। मेरे यह दो इश्यू है।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र में 550 टेंक बने हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

28.03.2026/1115/डी.सी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-4140.....जारी

उप-मुख्य मंत्री..... जारी

इसमें से 215 टैंक्स 50 हज़ार से एक लाख की क्षमता के हैं और 49 टैंक्स एक लाख व ज्यादा की क्षमता के हैं। 296 टैंक्स 50 हज़ार से कम की क्षमता वाले हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र में टैंक्स की बहुत बड़ी कतार/संख्या है और कुल 550 टैंक्स हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्र में कुल 225 स्कीम्ज़ हैं जिनके लिए 731 करोड़ रुपये निर्धारित हुए हैं। इनमें से 178 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 47 योजनाएं निर्माणाधीण हैं। इन योजनाओं पर 407 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं तथा 259 करोड़ रुपये और चाहिएं। इसमें से जल जीवन मिशन का पैसा 50 करोड़ रुपये से ज्यादा है और शेष अन्य मदों के पैसे हैं। जब हमारे पास 259 करोड़ रुपये आएंगे तभी हम काम करवा पाएंगे। हमारे पास पैसे की उपलब्ध्ता नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत हमारा पैसा केन्द्र सरकार के पास लटका हुआ है और मैंने माननीय सदन में भी कई बार बताया है कि 1227 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से आना है। इनमें से 400 करोड़ रुपये की तो देनदारियां लम्बित पड़ी हैं क्योंकि काम हो चुका है और ठेकेदार हमसे पैसे मांगते हैं। एक-दो दिन पहले भी जल जीवन मिशन के लिए केन्द्र सरकार का फरमान आया और उसमें हमें 50 पेज की गाइडलाइन्ज़ भेज दी गई हैं कि आप ये-ये करो तब हम पैसा जारी करने के बारे में सोचेंगे। हम यह पैसा लम्बे अर्से से मांग रहे हैं और हमें पैसा नहीं मिल रहा है जिस कारण हमारी सारी योजनाएं लटकी हुई हैं। **माननीय सदस्य जो टैंकों की गुणवत्ता की बात कह रहे हैं, वह तो हम चैक करवा लेंगे कि कौन-कौन से टैंक्स फट रहे हैं या जिनके कनैक्शन नहीं हुए हैं।** जब तक

हमें 259 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे तब तक यह काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह बहुत बड़ा अमाऊंट है और जब केन्द्र सरकार इस अमाऊंट को देगी तभी आगे काम हो पाएगा।

28.03.2026/1115/डी.सी.-एन.जी./2

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्य मंत्री ने जो-जो बातें कहीं हैं वे शत-प्रतिशत सही हैं। लेकिन मेरा जो कंसर्न है, वह उन जगहों को लेकर है जिनके कारण कम्यूनिटी पर खतरा बन गया है। हम अब बजट का इंतज़ार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि प्रदेश की ओर से हमें थोड़ी राहत मिल जाए ताकि उन टैंकों के नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनको बचाया जा सके क्योंकि वे टैंक खिसक रहे हैं। बरसात से पहले हमें उन टैंकों को रिटेन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसके लिए थोड़ी टोकन मनी आदि मिल जाए और जब बड़े धन की व्यवस्था होगी तब बात देखी जाएगी। वर्तमान में स्थानीय जनता के लिए वे खतरा बन गए हैं क्योंकि मेरे क्षेत्र में दो आपदाएं बड़ी खतरनाक आई हैं। बरसात आने के डर से लोग सहमे हुए हैं और मैं यह चाहता हूं कि तुरंत कार्रवाई के लिए थोड़ा-सा फंड दे दिया जाए, चाहे स्पेसिफिक बड़े खतरों के लिए मिल जाए नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा और मुझे इस माननीय सदन में उस नुकसान को न बताना पड़े उससे पहले ही मैं उस नुकसान को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह काम बहुत बड़ा है और 259 करोड़ रुपये का काम है। माननीय सदस्य का थोड़े-से क्या अभिप्राय है, वह मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री चन्द्र शेखर : उप-मुख्य मंत्री जी, 10 प्रतिशत ही दे दो। (अपने स्थान से बिना अनुमति के बैठे-बैठे कहा गया)

उप- मुख्य मंत्री : वह आप माननीय मुख्य मंत्री जोकि वित्त मंत्री भी हैं, उनसे मिल कर अपनी बात रख सकते हैं और यदि मुख्य मंत्री जी स्टेट हैड से कुछ दे पाते हैं तो अलग बात है। अन्यथा 259 करोड़ रुपये देने के लिए हमारा विभाग अभी इस स्थिति में नहीं है। जब तक केन्द्र सरकार से पैसा नहीं आता तब तक हम इतना बड़ा अमाऊंट नहीं दे पाएंगे।यदि कोई 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये का काम होगा तो उसके लिए हम इन्हें

पैसा दे देंगे। माननीय सदस्य जैसे 10 प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो 259 करोड़ रुपये का 10 प्रतिशत लगभग 26 करोड़ रुपये बनता है तो यह बहुत ज्यादा पैसा है और इसके लिए माननीय सदस्य को माननीय वित्त मंत्री (माननीय मुख्य मंत्री के लिए कहा) से मिल लें।

28.03.2026/1115/डी.सी.-एन.जी./3

प्रश्न संख्या : 4141

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैंने जल शक्ति विभाग से संबंधित प्रश्न किया है और वैसे यह प्रश्न सभी विभागों से संबंधित है। मैंने पूछा था कि दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति काफी लम्बे समय से रुकी हुई है, लगभग 2016 से रुकी हुई है,

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

28.03.2026/1120/एच0के0/ए0पी0/-01

प्रश्न संख्या 4141 जारी .....

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी .....

उसके बाद दिव्यांग कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में गए थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 6-07-2022 को सरकार को पत्र लिखकर भेजा है और उस पर यह फैसला हुआ है कि जो 4 प्रतिशत इनका कोटा है उसके आधार पर इनकी पदोन्नति की जाए, यानी प्रमोशन दिया जाए। जिस तरह से उत्तर में बताया है कि एक कमेटी का गठन किया है ताकि 4 प्रतिशत कोटे में जो दिव्यांग कर्मचारी है उनकी पहचान की जा सके ताकि उसके माध्यम से हम इसे लागू कर सकें। इसके अंतर्गत 25 विभिन्न श्रेणियों का आपने निरीक्षण भी कर लिया गया है, जैसा आपने अपने उत्तर में बताया है। अंत में आपने यह जवाब दिया है कि इस पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु शीघ्र ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शीघ्र कर दी जाएगी। इसमें शीघ्रता का कोई पैमाना है या इसकी कोई समय-सीमा है उसके बारे में बताया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। यह केवल एक विभाग का प्रश्न नहीं है। मेरा

प्रश्न यह भी है कि प्रत्येक विभाग चाहे शिक्षा विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो सभी में इस तरह से पदोन्नति रुकी हुई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि सरकार हर विभाग के अंदर इसकी समीक्षा करवाकर सभी दिव्यांगजनों को प्रमोशन का लाभ देगी? यह मेरा माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने उत्तर में कहा है कि हम जल्दी ही अधिसूचना जारी कर देंगे। इसमें केवल यह है कि जो यह कैटेगरी हैं जिसमें बेलदार, ड्राइवर, पंप ऑपरेटर या इलेक्ट्रिशियन लगाने है ऐसी कुछ कैटेगरी थीं, जिन्हें हमें हटाना है। यह प्रक्रिया पूरी करके हम हर हालत में 15 अप्रैल से पहले नोटिफिकेशन जारी कर देंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : सर, शेष विभागों का विषय भी यहीं है क्योंकि बार-बार अलग-अलग विभागों के प्रश्न आते रहेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी भी अभी सदन में है तो मेरा प्रश्न है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जलशक्ति विभाग के लोग गए थें, लेकिन ऐसी स्थिति अलग-अलग विभागों में भी है। बार-बार सभी को कोर्ट में न जाना पड़े। क्या सरकार इस पर कोई सामूहिक निर्णय लेगी,ताकि सभी विभागों में दिव्यांगजनों के प्रमोशन कोटे को बहाल कर उन्हें प्रमोशन दिया जा सके?

28.03.2026/1120/एच0के0/ए0पी0/-02

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे पास यह प्रश्न सीमित है। लेकिन सरकार स्तर पर और माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या करना है। इसके अलावा पिछली कैबिनेट में भी इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन जलशक्ति विभाग की अधिसूचना हम 15 अप्रैल से पहले जारी कर देंगे।

28.03.2026/1120/एच0के0/ए0पी0/-03

प्रश्न संख्या : 4142

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत संक्षिप्त जवाब आया है कि अभी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं आपकी मार्फत ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये अस्थायी चौकियां वर्षों से चल रही हैं। जिस तरह से नशे का

प्रचलन बढ़ रहा है और लगातार कोई-न-कोई व्यक्ति इसमें पकड़े जा रहे हैं तो हमें अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है। हालांकि ठियोग में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि लोगों की मांग को देखते हुए, क्या भविष्य में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भविष्य में इस चौकी को स्थायी करने की बात की है। भविष्य में जब भी ऐसा कार्य किया जाएगा तो इसे ध्यान में रखा जाएगा। मैं यह आश्वासन आपको देना चाहूंगा।

श्री बलवीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि छैला चौकी में कोटखाई, ठियोग और चौपाल, इन तीनों विधान सभा क्षेत्र का हब है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

28.03.2026/1125/AT/HK /01

प्रश्न संख्या 4142 जारी .....

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी ....

और छैला इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां हिमाचल की सबसे बड़ी मंडी, प्राला मंडी है सेब सीजन में पुलिस की कमी के कारण हमारे जिले और चौपाल की बसें कई बार अगले दिन सुबह पहुंचती हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि छैला की जो चौकी है वह बहुत जरूरी है। यह तीनों क्विंटालसी को फीड करती है और इस चौकी के अंतर्गत पूरा तीन क्विंटालसी क्षेत्र आता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में इस चौकी को रेगुलराइज किया जाए।

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी पहले ही इस पर जवाब दे चुके हैं।

28.03.2026/1125/AT/HK /02

प्रश्न संख्या-4143

श्री सुख राम चौधरीः अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बोर्ड ने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से 994 मीटर रीडर रखे थे। बाद में उन्हें मेंटेनेंस गैंग बनाकर विभाग में एडजस्ट किया गया, लेकिन कई जगह पिक एंड चूज किया गया है उसमें कुछ को रखा गया और कुछ को हटा दिया गया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि एचपीएससीबी के सर्कल नाहन में कुल कितने आउटसोर्स मीटर रीडर थे उनमें से कितनों को फिर से एंगेज किया गया है और कितने अभी एंगेज नहीं किए गए हैं। कृपया इसकी सूचना दें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटर रीडर रखे गये थे उसकी रीडींग की सेवाए को हमने आउटसोर्स किया था और आउटसोर्स सेवाओं में कर्मचारी वेंडर के माध्यम से रखे जाते हैं। अभी सरकार की कोई नई आउटसोर्स पॉलिसी नहीं आई है लेकिन सरकार का हमेशा से विचार रहा है कि आउटसोर्स को कम किया जाए और जो लोग आउटसोर्स पर लगे हैं उनके लिए नीतिगत तरीके से सोचा जाए। इसमें कानूनी पहलुओं सहित कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कुछ लोग टेस्ट के माध्यम से आए होते हैं। इस पर विस्तृत विचार-विमर्श चल रहा है और भविष्य में कोई निर्णय लिया जा सकता है लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री संजय रतनः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर केन्द्र सरकार द्वारा धोंपे गये हैं, क्या वे प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों हैं या केवल प्रीपेड हैं? अगर ये केवल प्रीपेड हैं तो इससे आईपीएच की स्कीमें, स्ट्रीट लाइट्स और दफ्तरों का काम भी प्रभावित होगा है। प्रीपेड में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहले रिचार्ज करना पड़ता है। क्या इसमें पोस्टपेड का विकल्प है या नहीं? यदि नहीं है, तो क्या इसे पोस्टपेड किया जाएगा?

मुख्य मंत्री : माननीय महोदय, यह प्रश्न मीटर रीडिंग से संबंधित था लेकिन माननीय सदस्य के सवाल ने एक नया विषय उठाया है। आपने जो बात कही है, मैं उस पर विचार करूंगा और आपको उत्तर दूंगा।

28.03.2026/1125/AT/HK /03

श्री सुख राम चौधरी : सर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री से यह इसलिए पूछा क्योंकि कुछ लोगों को मेंटेनेंस गैंग में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से एडजस्ट किया गया है और कुछ को बाहर कर दिया गया है। इसमें पिक एंड चूज हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि सर्कल नाहन में कितने लोगों को दोबारा एंगेज किया गया और कितनों को बाहर निकाला गया। कृपया डिविजन वार जानकारी दें।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यदि सूचना उपलब्ध है तो दें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक लेबर गैंग में किसी को एडजस्ट नहीं किया गया है। जहां तक प्रीपेड मीटर की बात है भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा कि यह पोस्टपेड होगा या नहीं। यह मोबाइल की तरह काम करता है। स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत लगाए जा रहे हैं। इससे हर उपभोक्ता को रोज़ की बिजली खपत की जानकारी उसके मोबाइल पर मिल जाएगी। उसे अपने बिल का भी रोज़ाना पता रहेगा और यह भी पता चल जाएगा कि बिजली कटने वाली है या नहीं और हमारे पास किसने यूनिट बचे हैं अगर आप प्रीपेड करते है तो आप उसमें पहले से पैसा जमा कर सकते हैं। **श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....**

28.03.2026/1130/**केएस/वाईके**/1

प्रश्न संख्या : 4143 जारी -- **मुख्य मंत्री जारी** ---

और क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होगी। पोस्ट पेड की एक ऑफ्शन जो आपने बताया, यह बात सही है। क्या हो सकता है इसके बारे में तो टैक्नोलॉजी के आधार पर ही आगे बात की जा सकती है।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, फिर तो पानी की स्कीमें बंद हो जाएंगी।

मुख्य मंत्री : नहीं, पानी की स्कीमें तो निश्चित तौर पर ऊपर हैं। वह तो हम सबसे पहले फेज़ में कर रहे हैं।

28.03.2026/1130/केएस/वाईके/2

प्रश्न संख्या : 4144

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री डी0एस0 ठाकुर (अनुपस्थित) रीना कश्यप जी यह आपका भी प्रश्न है अतः आप पूछिए।

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके अनुसार जो चौकीदार दैनिक वेतनभोगी बन चुके हैं, सरकार उन्हें नियमित करने का कोई विचार नहीं रखती। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि दैनिक वेतनभोगी बनने के कितने समय के बाद पंचायत चौकीदार को नियमित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पंचायत चौकीदार जिला परिषद का काडर है। वे गवर्नमैंट के अंडर नहीं आते इसलिए उनके लिए अभी कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार की दैनिक भोगियों को रैगुलराइज़ करने की पॉलिसी है परंतु ये गवर्नमैंट के अंडर नहीं आते। **अभी तो कोई विचार नहीं है परंतु आने वाले समय में कैबिनेट इनको रैगुलर करने का विचार कर सकती है।**

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, मैंने भी यह प्रश्न रखा था और 31.08.2022 को लास्ट बैच दैनिक वेतनभागी बना था। उसके बाद अभी तक लगभग तीन साल हो गए हैं। दूसरा बैच लगभग 650 लोगों का है जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी दैनिक वेतनभोगी बनाया जाए। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि ये जिला परिषद काडर में आते हैं और इनके लिए कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पंचायती राज में यह एक ऐसी श्रेणी है जो लेफ्ट आउट है। कई सरकारें आईं, हालांकि यह जो 12 साल की नीति भी है, यह भी कांग्रेस सरकार में ही इनके लिए बनी थी। इनको नियमित करना या दैनिक वेतनभागी से

कॉंट्रेक्ट पर लाना तो भविष्य की बात है परंतु जो अभी 31 अगस्त, 2022 के बाद लगभग 650 लोग लेफ्ट आउट हैं, उन्हें दैनिक वेतनभोगी किया जाए, यह मेरी प्रार्थना है।

28.03.2026/1130/केएस/वाईके/3

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 31 अगस्त, 2022 के उपरांत जिन्होंने 12 साल पूरे कर लिए थे, अभी तक लगभग 2912 चौकीदार हैं जिनमें से डेलीवेजर में 1518 ले लिए गए हैं और 1394 लेफ्ट आउट हैं। 31 अगस्त, 2022 के उपरांत लगभग 474 लोगों ने इनमें 12 साल पूरे कर लिए हैं। **जिन्होंने इस श्रेणी में 12 साल पूरे कर लिए होंगे, उनको 31 मार्च, 2026 तक हम दैनिक वेतनभोगी बना सकते हैं और हम बनाएंगे।** जो लेफ्ट आउट रह जाएंगे, पॉलिसी की बात है जो कि कैबिनेट डिसाइड करेगी। जैसे माननीय सदस्या श्रीमती रीना कश्यप जी ने भी इनकी रैगुलराइजेशन के बारे में पूछा था, वह फैसला तो सरकार के लैवल पर होगा।

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही यह सही है परंतु 31.08.2022 के बाद का लेफ्ट आउट का आंकड़ा 650 है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्हें डेलीवेजर कर दिया।

अध्यक्ष : यह मंत्री जी ने बोल तो दिया है। मंत्री जी, फिर से बोल दो।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य 650 की बात कर रहे हैं, मेरी सूचना के अनुसार वे अभी तक 474 हैं। लेकिन जितने भी होंगे, कई बार क्लैरिकल एरर भी हो सकता है। **अगर बाय चांस कोई रह गए होंगे तो उनको भी इन्क्लूड करके 31 मार्च, 2026 तक उनको दैनिक वेतनभागी पर लाया जाएगा।**

अगला प्रश्न श्रीमती अ0व0 की बारी में--

28.03.2026/1135/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 4145

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न के 'ख' भाग के उत्तर में बताया गया है कि प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी, 2023 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक 2513.65 करोड़ रुपये 331 परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से स्वीकृत हुआ है। मैं देख रहा था कि नदौन में 10, ज्वाली 10, सुजानपुर 10, जुब्बल-कोटखाई 10, कसुम्पट्टी 11, शिलाई 10, नाहन 11, अर्की 11 यानी इन विधान सभा क्षेत्रों में इतनी-इतनी स्कीम्ज स्वीकृत की गई हैं। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र नाचन में नाबार्ड के तहत मात्र 2 स्कीम्ज ही स्वीकृत की गई हैं। मैं सिराज़ विधान सभा क्षेत्र के बारे में भी देख रहा था तो वहां पर भी पिछले तीन वर्षों में केवलमात्र 1 स्कीम और दरंग विधान सभा क्षेत्र का तो इसमें जिक्र ही नहीं किया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी विपक्ष के विधायक होने के नाते नाबार्ड से कम परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं? जबकि इसमें सत्ता पक्ष के लगभग सभी विधायकों की 7, 8, 10 या 11-11 स्कीम्ज नाबार्ड के तहत स्वीकृत करवाई जा रही हैं। अतः जिन-जिन विधान सभा क्षेत्रों की पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में 1, 2 या 3 स्कीम्ज ही स्वीकृत हुई हैं, क्या उनके लिए आप यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जितनी भी परियोजनाएं नाबार्ड के तहत गई हैं उनको आप इस वर्ष स्वीकृत करवाएंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश के एक समान विकास के लिए पहले से ही कार्य कर रही है। कई जगह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कर दी जाती हैं और हमने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत अधिकतम सड़कों को स्वीकृत करवाने में सफलता प्राप्त की है। कई जगह सी0आर0एफ0 के तहत कर दी जाती है जैसे कि यहां पर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री की सड़क के बारे में कहा गया। हमने इनकी चैल चौक से छतरी तक सड़क को स्वीकृत करवाया है और कई जगह हम नाबार्ड के थ्रू करते हैं। लेकिन नाबार्ड में हमारी एक लिमिट है और अगर श्री जय राम ठाकुर जी की लिमिट एग्जोस्ट हो चुकी है तो आप लोग जितनी मर्जी सड़कें दे

दीजिए, मगर जब तक वह लिमिट एक्सटेंड नहीं कर दी जाती जैसे इस बजट में 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये की है। उसमें

28.03.2026/1135/av/yk/2

जितनी भी सड़कें आएंगी इनको वे दी जाएंगी। इसलिए ये जिस-जिस सड़क को प्राथमिकता पर देंगे उनको इस लिमिट के अंदर स्वीकृत कर दिया जाएगा। हम इसमें किसी विशेष विधान सभा का ख्याल नहीं रखते। कई जगह पी0एम0जी0एस0वाई0 नहीं है जैसे नदौन विधान सभा क्षेत्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 बहुत कम है। इसलिए उन रोड्ज की अपग्रेडेशन तथा उनको पक्का करने के लिए हम नाबार्ड की स्कीम्ज सैंक्शन करते हैं। कई जगह पी0एम0जी0एस0वाई0 में सौ-सौ करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हो रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत भी छोटी-छोटी पगडंडियों को जोड़ने का कार्य करती है। हम कुछ प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत प्राप्त होने वाले 50 वर्षों के लिए इन्टरस्ट फ्री लोन से भी पैसा देते हैं। हम हर तरह से स्थिति को देखकर पैसा देते हैं और कई बार हम नेशनल हाईवे के लिए भी पैसा देते हैं। अगर आपकी दो सौ करोड़ रुपये के भीतर लिमिट शेष रहती होगी तो आप प्राथमिकता के आधार पर पहली, दूसरी और तीसरी नम्बर डालकर सड़क का नाम दे देना, **फिर उस पर विचार किया जा सकता है।**

टी सी द्वारा जारी

28.03.2025/1140/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्या :..4145 क्रमागत

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कोई भी सड़क न तो सी0आर0आई0एफ0 में स्वीकृत हुई और न ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत हुई है। नाबार्ड के तहत पिछले 3 वर्ष से मेरे विधान सभा क्षेत्र की 5 स्कीमें विचाराधीन हैं । क्या यह सच नहीं है कि मुख्य मंत्री द्वारा

प्रायोरिटी तय करके नाबार्ड को सड़कें स्वीकृति हेतु भेजी जाती हैं? हमारी लिमिट बची है और कम-से-कम 70 करोड़ रुपये लिमिट बची है। फिर भी 3 वर्ष से कोई सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो सड़कें नाबार्ड में पिछले 2-3 वर्ष से स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं, क्या आगामी समय में जब नाबार्ड में पैसा आएगा तो उन्हें स्वीकृत करने पर विचार किया जाएगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि इनकी लिमिट बची है लेकिन हमें कुछ चीजों का आकलन करना पड़ता है। जैसे पहले वर्ष हमारे पास नाबार्ड में काफी पैसा था। इस बार बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान था। उसमें स्कीमों की प्रायोरिटी तय की जाती है। आपने कहा कि आपकी 70 करोड़ रुपये की लिमिट बची है। आपकी जो सड़क प्रायोरिटी में होगी, अगले वित्तीय वर्ष में यदि हमने नाबार्ड का लोन लिया तो उस आधार पर आपकी एक सड़क को प्रायोरिटी में अवश्य डाला जाएगा। वैसे 600 करोड़ रुपये की लिमिट में पूरे प्रदेश की सड़कें आती हैं। आपने एक सड़क की बात की है और आपकी लिमिट भी बची है, इसलिए उसे प्रमुखता से ध्यान में रखा जाएगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रश्न के 'क' और 'ख' भाग को विस्तार से देखा जाए तो इसमें दो बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक तो मुख्य मंत्री या पूरी सरकार के मंत्रियों और उस पक्ष के नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है जबकि केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश के डवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है और इसमें कई हैड अभी भी मिसिंग हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने उत्तर दिया है उसके अनुसार वर्ष 2023-24 में केंद्र से 16,592 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष 2024-25 में 16,192 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और वर्ष

2025-26 में 11,735 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यदि इन तीनों को मिलाया जाए तो यह कुल राशि 47,519 करोड़ रुपये बनती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो आरोप लगाये जा रहे हैं वे निराधार हैं। केंद्र सरकार हिमाचल जैसे छोटे राज्य को भी विभिन्न योजनाओं के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान कर रही है। केंद्र से प्राप्त इस सहायता में से कई हेड मिसिंग हैं,

क्या आप उनका भी उल्लेख करेंगे? आपने केवल 4 हैड का ही जिक्र किया है जबकि हैल्थ सैक्टर का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही ई0ए0पी0 में भी सलैक्टिवली जानकारी दी गई है। यह सूचना पूर्ण नहीं है, क्या आप पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएं?

दूसरा, मेरा प्रदेश सरकार के ऊपर गंभीर आरोप है कि सरकार राजनीतिक आधार पर और प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है। केंद्र का पैसा होने के बावजूद उसका आबंटन केवल सत्ता पक्ष के विधायकों को किया जा रहा है यानी उन्हीं विधान सभा क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं। 'ख' भाग में सीरियल नंबर 26 से आगे नादौन का बार-बार उल्लेख है यानी लगातार नादौन विधान सभा क्षेत्र को ही प्राथमिकता दी गई है। 11 स्कीमें एक ही विधान सभा क्षेत्र को दी गई हैं क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व मुख्य मंत्री जी आप करते हैं।

एन0एस0 द्वारा ..... जारी

28-3-2026/1145/NS-AG/1

प्रश्न संख्या : 4145 -----क्रमागत श्री जय राम ठाकुर------जारी

यहां पर सड़क की जो बात कह रहे हैं तो वह नाबार्ड की बात कह रहे हैं। आपको इस बात को भी देखना है कि जहां जिसकी किटी बची है, जिसकी लिमिट बची है उसके लिए भी पैसा देना है। यह बात समझ में आती है लेकिन आपको उस एरिया की भौगोलिक परिस्थिति को भी देखना है और यह भी एक क्राइटेरिया है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमीरपुर, भोरंज और सुजानपुर को कई सड़कों के लिए बजट दे दिया। मेरा मुख्य मंत्री जी के ऊपर गंभीर आरोप है। यह पैसा सिर्फ और सिर्फ मुख्य मंत्री जी के जिला और विधान सभा क्षेत्र को ही दिया गया है।

अध्यक्ष : यह सूचना माननीय सदन में उपलब्ध है। आप सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन में यह बोलना है क्योंकि यह गलत हो रहा है। ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि आपने मण्डी में काम किया और सिराज विधान सभा क्षेत्र में काम किया।

अध्यक्ष : आप इस सूचना के आधार पर क्या पूछना चाह रहे हैं? यह सूचना तो आ चुकी है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने दें। ऐसा नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष : आप सप्लीमेंटरी पूछिए, यहां पर कोई डिबेट नहीं हो रही है।

श्री जय राम ठाकुर : इन्होंने आगे बड़सर के लिए भी पैसा दिया।

Speaker: This information is there on the Table of the House. You ask the supplementary question. What do you want to know from the Chief Minister?

Shri Jai Ram Thakur: I know. Let me speak. अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे भी नहीं रोक सकते कि आप बोलने ही नहीं देंगे। ...(व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री जी के जिले की बात कर रहा हूं।

Speaker: Question is not this. When the information is on the Table of the House, you can ask the supplementary arising out of this information from the Hon'ble Chief Minister. This information is with the Press and with every Member of this House.

28-3-2026/1145/NS-AG/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं। जिला हमीरपुर के बड़सर को भी 3 सड़कें दी गई हैं। उसके बाद इसमें वही इलाके हैं जहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं। क्या यह सरकार सिर्फ उन्हीं विधान सभा क्षेत्रों की है? क्या आपने विपक्ष के विधायक जिन क्षेत्रों से जीत कर आए हैं उन क्षेत्रों को हिमाचल के नक्शे से निकाल दिया है? मुख्य मंत्री जी, आप इस बात को स्पष्ट करें। दूसरा, अभी अगला जो केंद्र सरकार से बजट आएगा, क्या आप इस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश करेंगे? अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र का बहुत जिक्र करते हैं कि सिराज विधान सभा क्षेत्र को हमने सी0आर0एफ0 के अंतर्गत 138 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग का लगभग 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस बारे में लोक निर्माण मंत्री, मुख्य मंत्री जी और सब लोग जानते हैं।

अध्यक्ष : माननीय जय राम ठाकुर जी आप सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री जय राम ठाकुर : उसमें क्या गुनाह कर दिया और उसमें हमने भी सहयोग किया है। मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी से मिला और मैंने उनसे आग्रह किया। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। हम उस तरह से नाशुक्रे नहीं हैं। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे? ...(व्यवधान) हम नाशुक्रे नहीं हैं, वे हैं।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, चलिए-चलिए, आप अपनी बात रखें।

श्री जय राम ठाकुर : क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र सरकार से विभिन्न मदों के तहत जो अगले बजट की अलॉटमैंट होगी तो उसमें आप विपक्ष के विधान सभा क्षेत्रों के विकास के लिए बजट एलोकेट करेंगे? नाबार्ड और दूसरी भी कई प्रकार की योजनाएं हैं। चाहे सी0आर0आई0एफ, नाबार्ड या वर्ल्ड बैंक का पैसा है तो क्या उसके अंतर्गत आप कोशिश करेंगे कि बजट ऐलोकेशन का संतुलन बनाया जाएगा?

मुख्य मंत्री -----आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

28.03.2026/1150/RKS/AS-1

प्रश्न संख्याः 4145 जारी....

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री के पास वित्त विभाग भी था। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 और आयुष्मान भारत केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं...(व्यवधान) आप सब जानते हैं परंतु आप टालते हैं। आप इन योजनाओं का पैसा जोड़कर कहते हैं कि हमें 47 हजार करोड़ रुपये मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह केंद्रीय टैक्स का एक हिस्सा है। आप बड़े-बड़े जोर से चीख रहे थे कि इस बजट में नदौन को ज्यादा वेटेज दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नदौन विधान सभा की जो लिमिट थी, उसमें योजनाएं आबंटित की गई हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में 45 करोड़ रुपये की 10 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं...(व्यवधान) आप इसे पढ़िए...(व्यवधान) आप कह रहे थे कि नदौन का पूरा ख्याल रखा गया है। जसवां-प्रागपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए इन तीन वर्षों में 75 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं...(व्यवधान) 38 करोड़ रुपये की तो बल्ह की एक योजना स्वीकृत की गई है...(व्यवधान) सड़कों के अलावा जल शक्ति विभाग

में पानी की स्कीमों के पैसे भी नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत होते हैं। क्या बड़सर में किसी और पार्टी के विधायक हैं?...(व्यवधान) आप मेरी विधान सभा क्षेत्र और जसवां-प्रागपुर विधान सभा क्षेत्र की स्कीमों का जोड़ कर लीजिए...(व्यवधान) आजकल ये राजनीतिक भाषण बहुत देने लग गए हैं। आप आंकड़ों पर बात करें। नदौन में 45 करोड़ रुपये की 10 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जबकि जसवां-प्रागपुर में 75 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। बल्ह में तो एक ही योजना 38 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई है। आप पूरे जिला का आंकड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। हम चाहते हैं कि प्रदेश का संपूर्ण विकास हो और इसमें सिराज विधान सभा क्षेत्र भी सम्मिलित है। पहले सिराज और धर्मपुर विधान सभा क्षेत्रों के लिए ही ज्यादातर योजनाएं स्वीकृत होती थीं। श्री चंद्र शेखर जी कह रहे हैं कि जो वहां 500 टैंक बने हैं जिनके रख-रखाव के लिए कुछ पैसा जारी किया जाए। मैंने अपनी लिमिट के अनुसार ये योजनाएं स्वीकृत की हैं। हमने वहां के लोगों की समस्याओं को देखकर ये योजनाएं स्वीकृत की हैं। अगर 1-1 करोड़ रुपये की 15 योजनाएं भी होंगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में समान विकास हो। हमने मण्डी और सरकारघाट विधान सभा क्षेत्रों के लिए भी योजनाएं स्वीकृत की हैं। हमने कांगड़ा विधान सभा के लिए भी कोई कमी नहीं रखी है जबकि वहां से कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं है। जब आप दिल्ली जाते हैं और

28.03.2026/1150/RKS/AS-2

वहां कहते हैं कि इन्हें पैसा न दिया जाए तो तब आपकी स्कीमों में कट लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं सबके साथ न्याय करता हूं...(व्यवधान) चौपाल क्षेत्र मेरे दिल में है। मैं चौपाल भी जा रहा हूं। शिमला जिला का चौपाल विधान सभा क्षेत्र मेरे दिल में है। शिमला जिला में चौपाल के कुपवी क्षेत्र की महिलाओं को सबसे पहले इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं।...(व्यवधान) संपूर्ण प्रदेश के विकास के लिए हमारा दिल और दिमाग खुला है। श्री बलबीर सिंह वर्मा जी बैठे-बैठे बोल रहे हैं। आप 10 साल से विधायक हैं और इन 10 सालों में आपके साथ अन्याय हुआ है। हम देखेंगे कि आपके साथ अब कितना न्याय करना है। हम आपके साथ निश्चित तौर पर न्याय करेंगे। पूर्व मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा आपदा राहत राशि जारी की गई। आप यह नहीं कह सकते कि मैंने आपके क्षेत्र की अनदेखी की है...(व्यवधान) आप

सीट से बार-बार क्यों उठते हैं? क्या आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो खा लेना। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं...(व्यवधान) यह अच्छी बात है, दवाई खानी चाहिए...(व्यवधान) हमें सी0आर0एफ0 के अंतर्गत एक रोड स्वीकृत हुआ। हमारे पास छैला, सैंज, नेरीपुल रोड की प्रायोरिटी थी। इस संदर्भ में मेरी आपके साथ भी बात हुई थी।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.03.2025/1155/बी.एस./ए.एस.-1

प्रश्न संख्याः 4145 क्रमांगत... मुख्य मंत्री जारी...

हमारी प्राथमिकता छैला-सैंज, नेरी पुल वाले रोड की थी। इनसे मेरी बात हुई, ये भी गडकरी जी के पास गए, यह मैं नहीं कहता हमने 140 करोड़ रुपये इनके क्षेत्र सिराज में जो नुकसान हुआ था उनके लिए दे दिया। अब यह कहना कि हमारे सड़कें नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सभी की सड़कों का ख्याल रखा जाएगा। बेशक आप आर0डी0जी0 में हमारे साथ नहीं गए। आप यहां नारे लगाते रहे। आप यह भी सोचा करो कि प्रदेश का और प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा था तब तो आप सोचते नहीं हैं। अब सोच रहे हैं लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सभी चुनकर आए हुए माननीय विधायक हैं और चुनकर आए विधायकों का जो भी कार्य होगा उसको हम पूरा करेंगे और जो नाबार्ड की किटी है उसे इसलिए कई विधान सभा क्षेत्रों में 200 से 225 करोड़ रुपये कर दी जाए। एक आदरणीय सुख राम जी की सड़क आ जाएगी। मैं आदरणीय सुख राम जी से कहना चाहता हूं जो पुल बना हुआ है उसके लिए भी हम आपको इस विधान सभा पटल पर कहना चाहते हैं कि उस पुल के लिए जो उत्तराखंड वालों ने बना दिया है, **बंगाणी पुल उसकी लैंड एक्विजिशन के लिए भी पैसे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।**

28.03.2025/1155/बी.एस./ए.एस.-2

प्रश्न संख्याः 4146

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जो प्रश्न मैंने पूछा था कि पिछले तीन सालों से एक्सग्रेशया के कितने केसिज रोहडू विधान सभा क्षेत्र के निपटाए गए? मुझे इसके उत्तर में मिला कि 107 केसिज निपटा दिए गए हैं और 18 केसिज लंबित हैं। मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि जो 18 केसिज बचे हैं इन्हें प्राथमिकता के तौर पर निपटाने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से 18 लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों को अभी राशि जारी करने की जरूरत है तो इसको शीघ्र कर देंगे।

28.03.2025/1155/बी.एस./ए.एस.-3

प्रश्न संख्याः 4147

श्री इंद्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो सूचना यहां सदन के पटल पर रखी गई है यह काफी लंबी-चौड़ी सूचना है और इसमें पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 150 करोड़ 19 लाख 71 हजार 939 रुपये की जो धोखाधड़ी हुई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं भविष्य में इस प्रकार की जो धोखाधड़ियां हो रही हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी के युग में नए-नए तरह के जो फ्रॉड करने वाले हैं, तरीके अपना रहे हैं। ए0आई0 के दौर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे 146 पुलिस स्टेशन हैं उसमें साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं और 8 साइबर कमांडो को पुलिस में प्रशिक्षित किया गया है और 29 को अन्य साइबर अपराधों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साइबर अपराध को रोकने के लिए वर्ष 2025 में एच0पी0 पुलिस द्वारा स्कूलों, कॉलेज, संस्थाओं और पंचायत में 100 से अधिक साइबर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। स्टेट सी0आई0डी0 एच0पी0 हर दो सप्ताह में सभी साइबर हेल्प डेस्क अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रही है। जो यह टेक्नोलॉजी है अभी तो सिर्फ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है लेकिन निश्चित रूप से कई ऐसे केसिज होंगे जो दर्ज ही नहीं होते होंगे।

अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए और भविष्य की टेक्नोलॉजी में बदलाव को देखते हुए हमें और अपग्रेड अपने आप को करना है। इस बात का सरकार ध्यान रखेगी कि भविष्य में किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिस द्वारा दिया जाए और क्या उसमें नई नियुक्तियां की जाए जो ए0 आई0 को जानने वाले हो। इन सब चीजों की दृष्टिकोण से हमारी सरकार भविष्य में आने वाले समय में क्या कर सकती है उसको देखेगी।

प्रश्न काल समाप्त।

अध्यक्ष : अब जीरो अवर के माध्यम से विषय उठाए जाएंगे।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

28.03.2026/1200/DT/DC-1

अध्यक्ष : अब शून्य काल के माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने विषय रखे जाएंगे। पिछले कल भी लगभग 10 विषय मान्य सदन के ध्यान में आए थे जिसमें से तीन पर चर्चा हो गई थी अब 7 विषय शेष हैं। पहले मैं पिछले कल की लिस्ट लूंगा। आज भी लगभग चार या पांच विषय शून्य काल में मान्य सदन के ध्यान में आए हैं।

मैं सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी से कहूंगा कि वह अपना विषय शून्य काल में रखें। माननीय सदस्य आपके दो विषय है एक कॉलेज का है और एक स्कूल से संबंधित है।

श्री सुरेन्द्र शौरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस शून्य काल में अपने क्षेत्र के दो महाविद्यालय, बंजार और सैंज से संबंधित विषय उठाना चाहता हूं।

इन कॉलेजिज में प्राध्यपक के पद रिक्त हैं। बड़े हैरानी की बात है कि पूरा कॉलेज में पूरा सैशन खत्म होने को है लेकिन अंग्रेजी, केमिस्ट्री, बॉयोलोजी, जूलॉजी और संस्कृत, यानी इन विषयों के प्रध्यापक बंजार कालेज में नहीं हैं जिसके कारण वहां पढ़ने वले विद्यार्थियों

को बहुत परेशानी आ रही है। इस कॉलेज में स्टुडेंटस की जो कुल स्टुडेंटस जो एनरोलमेंट हैं वह 599 हैं और उक्त छः विषयों के प्राध्यापक वहां नहीं है।

सैंज महाविद्यालय में भी समाज शास्त्र, संगीत, हिंदी के प्राध्यपक नहीं है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जहां कुल्लू कॉलेज में केमिस्ट्री में सात प्राध्यपक हैं वहीं बंजार में एक भी प्राध्यापक नहीं है। ऐसा अभी नहीं हुआ पिछले तीन सालों से वहां पर यही स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बंजार और सैंज कॉलेजिज में जो प्राध्यपकों के पद रिक्त हैं उनको तुरन्त भरा जाए क्योंकि अभी जो स्टुडेंट की असेसमेंट होनी थी उसके लिए भी वहां पर प्राध्यापक कभी मंडी से, कभी कुल्लू से बुलाए गए। मुझे लगता है कि वहां पढ़ रहे छात्राओं के भविष्य से यह एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस गंभीर समस्या को देखते हुए वहां प्रध्यापकों की नियुक्ति की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जहां पर सरप्लस टीचर्ज हैं या जहां पर एक विषय के दो अध्यपाक हैं, उन्हें वहां से तुरंत स्थानानतरित कर सैंज और बंजार कॉलेजिज में भेजा जाए।

28.03.2026/1200/DT/DC-2

अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी ने विषय अपनी विधान सभा क्षेत्र बंजार व सैंज के कॉलेजिज में प्रध्यापकों के रिक्त पदों के संबंध में उठाए हैं। उनके द्वारा इन पदों को भरने के बारे में आग्रह किया गया है। इसमें कोई दोराय नहीं कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 600 के आस-पास ए0पीज0 के पद खाली हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और केबिनेट के अन्य साथियों का धन्यवाद करता हूं कि प्रदेश में 400 पदों को भरने की स्वीकृति केबिनेट ने दे दी है। अप्रैल माह में यह प्रक्रिया आरम्भ होगी और उसमें हम अपने दूर-दराज के क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन वर्तमान में युक्तिकरण के माध्यम से, जैसे माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र शौरी ने भी सरप्लस स्टॉफ का सुझाव दिया

है, इस ओर भी विभाग प्रयास करेगा कि जहां पर सरप्लस स्टॉफ है उसके माध्यम से इन पदों को भरा जाए।

अध्यक्ष : अगला विषय माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी के द्वारा इस मान्य सदन में उठाया जायेगा।

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यमस से इस शून्य काल में सरकार का ध्यान कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर निवासी, जो मूल रूप से वहां के पलेटा गांव निवासी थे, स्वर्गीय हरीश राणा जी के अत्यंत संवेदनशील और मानवीय मामले की आरे आकृष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हरीश राणा जी लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और उन्होंने असहनीय पीड़ा के कारण इच्छामृत्यु की मांग की थी। यह मामला न केवल एक व्यक्ति की पीड़ा का विषय है बल्कि ये मानव गरीमा, सादे रोगों से पीड़ित लोगों की देखभाल, पैलिएटिव केयर और कानूनी व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा सामाजिक और मानवीय मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसे असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों का कोई डेटा है जो इच्छामृत्यु की मांग करते हैं।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

28.03.2026/1205/डी.सी.-एन.जी./1

श्री मलेन्द्र राजन..... जारी

जो इच्छामृत्यु की मांग करते हैं? क्या प्रदेश सरकार पॉलिएटिव केयर और असाध्य रोगियों की देखभाल के लिए कोई विशेष नीति बनाने पर विचार कर रही है? क्या ऐसे मरीजों और उनके परिवारों को मानसिक, आर्थिक और चिकित्सा सहायता देने के लिए कोई योजना है? क्या सरकार इस विषय पर केंद्र सरकार से स्पष्ट नीति या कानून बनाने के लिए आग्रह करेगी?

अध्यक्ष महोदय, यह केवल कानून का नहीं बल्कि मानवता, संवेदना और गरिमा के साथ जीने और मरने के अधिकार का विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीर नीति बनाने पर विचार करे। धन्यवाद।

Speaker: Hon'ble Health & Family Welfare Minister would you like to intervene? This is very different kind of issue which the Hon'ble Member has brought.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और संवेदनशील भी है। **सरकार इस पर विचार करेगी कि इस प्रकार के असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों के लिए किस प्रकार की नीति बनाई जाए। यदि ऐसा कोई डेटा उपलब्ध हो, तो उसे भी एकत्रित करने का प्रयास किया जाएगा।**

28.03.2026/1205/डी.सी.-एन.जी./2

Speaker: Next issue is of Hon'ble Member Lokender Kumar. He is absent.

(माननीय सदस्य, श्री सुदर्शन सिंह बबलू द्वारा शून्य काल के दौरान बिजली विभाग के अंतर्गत पंचयतों को शिफ्ट करने और बिजली विभाग के एक अधिकारी के व्यवहार से हो रही समस्याओं के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

Speaker: अब अगला विषय माननीय सदस्य, श्री सुदर्शन सिंह बबलू का है और वे अपना विषय रख सकते हैं।

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय बिजली विभाग से संबंधित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की काफी पंचायतें गगरेट विधान सभा के साथ लगती हैं, जिनका एस0डी0ओ0 ऑफिस मुबारिकपुर में पड़ता है। मैंने विधान सभा व माननीय मुख्य मंत्री के सामने यह मुद्दा रखा था कि मेरे क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधा होती है, क्योंकि उन

पंचायतों के लोगों को अम्ब नजदीक पड़ता है। अम्ब के आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं, उनका एक्सई0एन0 व एस0डी0ओ अम्ब में ही है और मैंने उन पंचायतों को भी अम्ब के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। अध्यक्ष महोदय, अभी तक मुझे इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है कि उस प्रस्ताव पर क्या कार्य हुआ है। इसलिए मैं माननीय सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली विभाग के अंतर्गत जो पंचायतें मुबारिकपुर के साथ जुड़ी हैं, उन्हें अम्ब के साथ जोड़ा जाए ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही, वहां पर एक एस0डी0ओ0 है और उसका व्यवहार लोगों के प्रति ठीक नहीं है। उसका व्यवहार काफी अनुचित है और वह लोगों से गुंडों जैसी भाषा में बात करता है। हमने उसे कई बार मीटिंग में बुलाया, लेकिन उसने कभी मीटिंग में आना भी सही नहीं समझा। जब हमारी शिकायत निवारण समिति की मीटिंग होती है, तब भी वह उपस्थित नहीं होता।

28.03.2026/1205/डी.सी.-एन.जी./3

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ लोगों ने काफी शिकायतें भी की हैं। कई पंचायतों के लोगों ने हस्ताक्षर करके उनके खिलाफ शिकायत दी है। लोगों का कहना है कि वह अधिकारी धमकी भरे शब्दों का भी इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं मर्डर हूं, मैंने मर्डर किया हुआ है और मुझे किसी का डर नहीं है। हमारी जनता के प्रति उसकी भाषा इस प्रकार की है और इसके लिए स्थानीय लोगों ने मुझसे भी अनेक आर शिकायत की है। इसलिए मैं माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जो अधिकारी जनता के साथ सही व्यवहार नहीं करता, मीटिंग में नहीं आता और फोन करने पर फोन तक नहीं उठाता, ऐसे एस0डी0ओ0 का वहां बने रहना उचित नहीं है। मैंने पहले भी अपने विधान सभा क्षेत्र से उसकी ट्रांसफर कहीं और करवाई थी, लेकिन बाद में उसने फिर से अपनी एडजस्टमैंट वहीं करवा ली है। हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है। This is with regard to the reorganization of area from your Constituency to the other Division. The Vidhan Sabha has taken cognizance of this issue. You have also brought into the notice of Vidhan Sabha that some employee's conduct is not proper, Vidhan Sabha Secretariat has taken cognizance of this and we will ask the concerned Department to take action in this behalf and whatever the action will be taken, both the Vidhan Sabha Secretariat and Hon'ble Member will be informed accordingly. Next issue is of Hon'ble Member Shri Suresh Kumar ji.

28.03.2026/1205/डी.सी.-एन.जी./4

(माननीय सदस्य, श्री सुरेश कुमार द्वारा शून्य काल के दौरान कोरोना काल में बंद हुए बस रूटों में से कुछ रूट्स के पुनः शुरू न होने से हो रही समस्याओं के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय भोरंज क्षेत्र में बंद पड़े एच0आर0टी0सी0 के रूटों के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय, कोरोना के समय कुछ बसों के रूट बंद किए गए थे। उनमें से कुछ रूट बाद में दोबारा चलाए गए, लेकिन बहुत से रूट ऐसे हैं जो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बस रूट हैं, जो लोगों की सुविधा

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

28.03.2026/1210/एच0के0/ए0पी0/-01

शून्य काल जारी ..... श्री सुरेश कुमार जारी ....

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बस रूट्स हैं जो लोगों की सुविधा के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन उन रूटों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इनमें हमीरपुर-शिमला बस (बाया कैरवी बस्सी), हमीरपुर-बस्सी-कंजयाण-जाहू और हमीरपुर-जाहू (बाया लदरौर) जैसे रूट शामिल हैं। इन बसों में कर्मचारी, स्कूल के बच्चे और कॉलेज के छात्र-छात्राएं आते-जाते थे। लेकिन बसें बंद होने की वजह से क्षेत्र में काफी असुविधा हो रही है। इसलिए मैं उप-मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन रूटों को दोबारा चलाने की सरकार की कोई योजना है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही, एक अन्य बस से संबंधित समस्या है। चंडीगढ़-से-लदरौर तक एक बस चलती है। यह बस शाम को लदरौर में खड़ी हो जाती है। यदि इस बस को थोड़ा आगे बढ़ाकर टौणी देवी तक कर दिया जाए तो हमारे विधान सभा क्षेत्र के कई गांव इसमें कवर हो जाएंगे और इससे लोगों को सुविधा भी मिलेगी। यह बस भोरंज, जनिकर, टौणी देवी होते हुए जाए तो इससे कॉलेज के छात्रों और आम जनता दोनों को सुविधा मिलेगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बंद पड़े रूटों को दोबारा शुरू करेगी, और जो बस लदरौर तक आती है उसके रूट को आगे बढ़ाने पर भी सरकार से आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र में बस सेवा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन में उठाया है। माननीय सदन ने इसका संज्ञान लिया है और हम विभाग तथा सरकार से कहेंगे कि आपके क्षेत्र में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जो कठिनाइयों हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से आपको और माननीय सदन को सूचित किया जाए।

28.03.2026/1210/एच0के0/ए0पी0/-02

बाहरी व्यापारियों के कारण स्थानीय व्यापार और पारंपरिक मेलों पर पड़ता नकारात्मक प्रभाव।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं की भूमि कहलाता है और यहां की पारंपरिक प्रथाएं तथा देवी-देवताओं से जुड़े छोटे-छोटे मेले हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र करसोग में भी ऐसे मेले होते हैं। लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों से एक समस्या सामने आ रही है कि हिमाचल प्रदेश से बाहर के व्यापारी हमारे विधान सभा क्षेत्रों में आकर निजी जमीन लेकर वहां कई दुकानें खोल लेते हैं। इससे स्थिति यह बन रही है कि हमारे क्षेत्र के पुराने और लंबे समय से व्यापार कर रहे व्यापारी, जो दुकानों का किराया देते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स और जी0एस0टी0 भी भरते हैं और समय-समय पर लोगों को उधार भी देते हैं। ऐसे में बाहरी व्यापारी मेलों के नाम पर दुकाने खोल कर दो-तीन महिनों तक लगातार बैठे रहते हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग भी अधिकतर हिमाचल से बाहर के होते हैं। वे बाहर से सस्ता सेकेंड-हैंड सामान लाकर उसे बहुत कम कीमत पर बेचते हैं। इससे हमारे स्थानीय व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके अलावा, हमारे पारंपरिक और सांस्कृतिक मेले जैसे तत्तापानी, महूनाग, नलवाड़ मेला (करसोग), सेरी भंजो जैसे मेलों की प्राथमिकता भी कम हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग सालभर की जरूरत का सामान, जैसे कपड़े और बर्तन इन मेलों से खरीदना पसंद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए ताकि बाहर से आने वाले व्यापारी जो न तो कोई टैक्स भरते हैं, न ही वे फायर सेफ्टी और अन्य नियमों का पालन करतें है और किसी तरह से एन0ओ0सी0 ले लेते हैं। साथ ही, इन मेलों से प्रदेश की आय भी बाहर जा रही है, धन्यवाद।

अध्यक्ष : निश्चिततौर पर आपने एक बहुत ही गंभीर विषय सदन के ध्यान में लाया है जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश की आय और उसके स्त्रोतों से भी है। माननीय सदन ने इसका संज्ञान लिया है और सदन यह चाहेगा कि सरकार द्वारा इस पर एक स्पष्ट नीति बनाई जाए ताकि व्यवस्था को ठीक किया जा सके। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से हम आपको और माननीय सदन को सूचित करेंगे। अगला विषय माननीय श्री त्रिलोक जम्वाल जी। **श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

28.03.2026/1215 /AT/HK /01

श्री त्रिलोक जम्वालः माननीय अध्यक्ष जी, जीरो आवर में मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2023 में जो आपदा आई थी उससे 41 की 41 पंचायतों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उस आपदा के बाद मेरी कई सड़कें खराब हो गई थीं। अब वर्ष-2025 में केंद्र सरकार के सहयोग से पीडीएनए के तहत इन पंचायतों के लिए 25.41 करोड़ रुपये मिले हैं।

लेकिन पीडीएनए के तहत जो डंगे लगाए जा रहे हैं,उनमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जबकि दो-तीन कॉन्ट्रैक्टर बहुत खराब काम कर रहे हैं और उनकी गुणवत्ता लगभग जीरो है। यह पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है और इस तरह से बड़ा नुकसान हो रहा है। कई जगह डंगे सड़क से हटकर दो-तीन मीटर दूर लगाए गए हैं जबकि उन्हें सड़क के पास लगना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में कोठी, भरेड़ी, बलसुवाय, रंगलोऊ, बैरी की सड़क, कोठी-भरेड़ी-घलयाना और बलवुरल की सड़कों पर एक जगह डंगा सड़क से लगभग डेढ़ से दो मीटर दूर लगाया गया है। अब उसे कवर करने के लिए या तो एक और डंगा लगाना पड़ेगा नहीं तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसी तरह कुडेड़ा से हरलोग, बनोहा से कुलवाड़ी रोड, गनेड, बढ़ियाना, फंदेर रोड और हवान-भद्रौन रोड पर भी क्वालिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। जब मैंने इस पर प्रश्न उठाया तो उसके बाद लोगों ने किसी प्राइवेट एजेंसी से क्वालिटी का सर्टिफिकेट ले लिया जबकि हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के पास अपनी लैब है।

अध्यक्ष महोदय, घुमारवीं से मोरसिंगी, हरलोग-कूजा, त्रिफाड़ाघाट, पनौह, हरलोग-स्मैला रोड, लिंक रोड, भरोटी से मंदरी घाट, पड़ेलला से बडैहर, मंद्रीघाट कूघाट, बासा लुसान, मुझवाड़, जबरियाना, सोहर रोड, नोक से कंडेला, अपर सुंगल, लोअर सुंगल, घलेयाना, जोड़ प्लाखी रोड और भगेट टैर रोड इन सभी पर पीडीएनए के तहत काम चल रहा है। लगभग 25 करोड़ रुपये के डंगे और मेटलिंग का काम हो रहा है लेकिन यदि क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो अगली बारिश में यह सब बह जाएगा। मैं केवल

आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि इन डंगों की क्वालिटी की जांच करवाई जाए। कुछ कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर। अध्यक्ष महोदय यदि आप

28.03.2026/1215 /AT/HK /02

अनुमति दें तो मैं कुछ सड़को की सूची भी दे दूंगा, जरूरत पड़े तो मैं अपनी विधायक निधि से भी खर्च देने को तैयार हूं उनका सैंपल दोबारा करवाया जाए। जब मैं खुद वहां गया तो है वहां पर कच्चे और कमजोर पत्थर डाले जा रहे थे, जो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। यही बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः आपने क्वालिटी से जुड़ा एक बहुत गंभीर विषय सदन के ध्यान में लाया है। हम विभाग से कहेंगे कि पीडीएनए के तहत आपके क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उनकी क्वालिटी बनाए रखी जाए और काम सही तरीके से किया जाए। की गई कार्रवाई की जानकारी आपको और सदन को विभाग सूचित करेगा। अब माननीय श्री केवल सिंह पठानिया जी।

श्री केवल **सिंह पठानियाः** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांगड़ा जिले के धर्मशाला और शाहपुर विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं। वहां आंखन खोला और सुधेड़ रोड है जो बाइपास का भी काम करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैंने पिछली बार जब यह मामला उठाया गया था तब ये रोड लगभग एक महीना 29 दिन से बंद था तब माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री के हस्तक्षेप से यह सड़क फिर से खोल दी गई।

इसके साथ एक अल्टरनेट रूट भी है जो मैकलोडगंज के लिए सबसे छोटा रास्ता है आंखन खोला और सुधेड़ रोड। उस रोड से आप भी मैकलोडगंज से विधान सभा आते थे इस बार आपदा के दौरान,बारिश के कारण यह सड़क फिर से बंद हो गई है। आजकल वहां हिज होलीनेस की टीचिंग भी चल रही है और बहुत से विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। कल 9 फ्लाइट आईं, 7 फ्लाइट आईं काफी लोग यहां पहुंच रहे हैं। इसलिए मैंने जीरो आवर में यह मुद्दा उठाया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि आंखन खोला और सुधेड़ रोड को जल्द से जल्द ठीक किया

जाए। क्योंकि यही वह समय है जब मैकलोडगंज, नड्डी और सतोबरी के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं और यह सड़क उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने कल देखा कि अमर उजाला ने भी यह छापा

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

28.03.2026/1220/केएस/वाईके/1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी ----

"आंखनखोला-सुधेड़ रोड वाहनों के लिए बंद।"अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसमें माननीय मंत्री जी की इंटरवेंशन चाहता हूं।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया ने अपनी शाहपुर विधान सभा की जिस सड़क का ज़िक्र किया है, जो मैकलोड गंज को जोड़ती है, पीछे भारी वर्षा के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। इस विषय **में मैं विभाग से तुरंत बात करुंगा और इसे बहाल करने का हर सम्भव प्रयास करवाया जाएगा।**

इसके साथ ही आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी ने अपने बिलासपुर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के बारे में, खासकर उनकी गुणवत्ता के बारे में जो विषय उठाया, हालांकि मैंने इस बार विधान सभा सत्र में कहा भी है कि इस बार हमने लोक निर्माण विभाग में एक स्पैसिफिक रेन ड्रेनेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। हमने जो पीछे सबक सीखे हैं, जिस तरीके से बरसात में पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों को नुकसान हुआ उसके मध्यनज़र हर जगह, खासकर हमारे नालों में इस ड्रेनेज पॉलिसी को अपनाया जा रहा है जिसमें अब डिपार्टमैंट ने हर जगह बॉक्स कल्वट्र्स लगाने का निर्णय लिया है और खासकर जो troublesome areas हैं, वहां पर पाइपों की ड्रेनेज पहाड़ों के ऊपर करवाई जाएगी और उसमें पी0वी0सी0 की पाइप्स लगवाने का हमने प्रस्ताव रखा है ताकि जो पानी है वह एक मुश्त सड़क के ऊपर ना आए उसका डाइवर्जन दो साइड्स में हो जाए जिससे सड़कों का कम से कम नुकसान हो। बाकी इन्होंने अपने डिविज़न की कुछ स्पेसिफिक सड़कों का ज़िक्र किया है। **अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से वह लिस्ट प्रोक्योर कर लेंगे और आज ही**

बिलासपुर के एस0ई0 और इनके डिविजन के एक्सिअन से चर्चा करके उसको हल करने का हर सम्भव प्रयास करवाया जाएगा।

28.03.2026/1220/केएस/वाईके/2

अध्यक्ष : अब कुमारी अनुरोध राणा इस चर्चा में भाग लेंगी।

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, ज़ीरो आवर के माध्यम से मैं शिक्षा व्यवस्था में न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में बात रखना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बहुत से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं जिनमें माननीय मुख्य मंत्री जी का अहम रोल है परंतु न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कई प्रकार के इशूज़ सामने आ रहे हैं और प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल हमसे भी मिला था। उन्होंने आग्रह किया था कि उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए इसलिए मैं अपनी बात यहां पर रख रही हूं। इसमें पहला प्वाइंट यह आ रहा है कि एक प्रिंसिपल के अधीन 15 से 20 स्कूल कर दिए गए हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि जब एक प्रिंसिपल के अधीन एडिशनल चार्ज के तौर पर दूसरा स्कूल होता है, जब उस स्कूल में स्टाफ की दिक्कत रहती है तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि एक प्रिंसिपल के अधीन 15 से 20 स्कूल रहेंगे तो मैनेजमेंट संचालन या प्रशासन में बहुत दिक्कत आएगी और इससे सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। दूसरा जो जे0बी0टी0 प्रोमोट हो कर एच0टी0, सी0एच0टी0 या बी0ओ0 बनते हैं इसमें उनकी शक्तियों को भी सीमित किया गया है। उनका भी आग्रह है कि इससे उनका मनोबल गिरेगा और उससे कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मल्टी टास्क के जो स्टाफ हैं उनमें भी इसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है। इस पर पुनर्विचार किया जाए। इसमें जो पहली अधिसूचना जारी की गई थी कि जो इसमें नई व्यवस्था है, रिसोर्स शेयरिंग तक इसको सीमित किया जाए, यह मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह रहेगा। उनका जो पूरे प्रदेश में प्रतिनिधि मंडल है वह मुख्य मंत्री जी से भी दो बार मिल चुका है और शिक्षा मंत्री जी से भी अपनी बात रख चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा ज़ीरो आवर के माध्यम से निवेदन रहेगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और उनकी डिमांड पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और इसका हल निकाला जाए। धन्यवाद।

28.03.2026/1220/केएस/वाईके/3

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो यहां पर बात रखी है वह कॉम्प्लेक्स सिस्टम से सम्बन्धित है और विभाग की बेहतरी के लिए, अच्छी शिक्षा हो, हमारे बच्चों को बैस्ट एजुकेशन मिले, उस सोच के साथ जो भी सार्थक विचार होंगे चाहे वह पी0टी0एफ0 की बात है या आपकी अन्य संस्थाओं की बात है, उस ओर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

अगले वक्ता श्रीमती अ0व0 की बारी में---

28.03.2026/1225/av/yk/1

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राम कुमार अपना विषय उठाएंगे।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नई सब-डिवीजन खोली है जिसका अभी भवन नहीं बना है, हालांकि उसका मुख्य मंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है। मैं चाहता हूं कि उसका कार्य जल्दी शुरू किया जाए। अतः मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस वित्तीय वर्ष में उसका कार्य शुरू हो जाएगा?

अध्यक्ष : माननीय सदन ने आपके इस विषय का संज्ञान लिया है और **हम सरकार को इस विषय के संदर्भ में तुरंत कार्रवाई करने हेतु कहेंगे तथा की गई कार्रवाई से आपको सूचित भी करेंगे।**

28.03.2026/1225/av/yk/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा अपना विषय उठाएंगे।

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र के मुद्दे को उठाने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं माननीय सदन का ध्यान नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में वर्ष 2023 व वर्ष 2025 के दौरान आई त्रासदी के कारण गिरे हुए पेड़ों तथा वर्ष 2024 में जंगल में हुई आगजनी की वजह से आंशिक रूप से जले पेड़ों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में वहां पर बहुत संख्या में पेड़ गिरे हुए हैं जिनसे वन सम्पदा को नुकसान होने के साथ-साथ आग व अन्य जोखिम की सम्भावना भी बनी हुई है। मेरे विधान सभा का जो क्षेत्र बिलासपुर के स्वारघाट के साथ लगता है, वहां ग्राम पंचायत जोखाड़ी, गड़ैच, बहा, लुनस, नंद या जगनी है और रामशहर से साईं चलोग तक वर्ष 2023 की त्रासदी के दौरान बहुत पेड़ गिर गए थे और वे पेड़ अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 में जो आग लगी थी उसके कारण वहां पर सूखे पेड़ गिरे हुए हैं। मैं यह चाहता हूं कि वन निगम इन पेड़ों की मार्किंग करके इन्हें अपने कब्जे में ले। वे चाहे शामलात में हैं या वन तथा मलकियत में हैं, उनकी मार्किंग की जाए। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पेड़ों की चोरी भी हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वन निगम उन पेड़ों को अपने कब्जे में ले। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदन के अंदर आदरणीय सदस्य द्वारा निश्चित तौर पर एक गम्भीर विषय उठाया गया है। आपने जिस विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है उसमें वन निगम गिरे हुए पेड़ों को लॉट लगाकर कंवर्ट करती है। **हम विभाग को वहां पर जल्दी से लॉट लगाने व उसके निष्पादन हेतु निर्देश देंगे तथा की गई कार्रवाई से आपको भी अवगत करवाया जाएगा।**

28.03.2026/1225/av/yk/3

अब अगला मुद्दा माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल उठाएंगे।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री से भाघछाल पुल पर एक अस्थाई पुलिस चौकी हेतु अनुरोध किया था जोकि वहां पर स्थापित भी कर दी थी। मैंने यह अनुरोध इसलिए किया था क्योंकि वहां से कीर्तपुर की ओर से शाहतलाई, बड़सर, हमीरपुर और कांगड़ा के लिए लगभग 60 किलोमीटर्ज का शॉर्ट पैसेज मिलता है। इस पुल का उद्घाटन पिछले वर्ष 24 मार्च को हुआ था इसलिए अब वहां से यात्रियों का आना-जाना बहुत बढ़ गया है। जिसके कारण वहां से चिट्टा व दूसरा नशा बहुत सुगम तरीके से चल रहा है। उस चौकी के बारे में मैंने लिखकर भी दिया था और वह वहां पर स्थापित भी की गई। लेकिन उसमें केवल दो पुलिस वाले नियुक्त किए गए जिसमें से कभी एक छुट्टी पर चला जाता है तो कभी दूसरा छुट्टी भेज दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में थोड़ी सीरियसनैस दिखाई जाए। मेरे हिसाब से यह पुलिस चौकी प्रिवेंटिव मैयर्ज का काम कर सकती है क्योंकि वहां से नशे का कारोबार बहुत ही सेफ तरीके से चल रहा है। मैंने इस संदर्भ में महोदय से पहले भी चर्चा की थी कि कोई इस प्रकार का केस हो जाए, वह बाद की बात है। परंतु उससे पहले प्रिवेंटिव मैयर्ज लेने जरूरी हैं। वहां पर एक पुलिस वाला आता है और दूसरा छुट्टी चला जाता है इसलिए वहां पर केवल दो व्यक्तियों की नियुक्ति से वह चौकी न के बराबर है।

टी सी द्वारा जारी

28.03.2025/1230/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
श्री जीत राम कटवाल... जारी

दूसरा मैं इसको सप्लीमेंट करना चाहूंगा। मैंने पहले भी नशे से संबंधित विषय उठाया था, उसमें मेरी एक सजेशन है कि जिस प्रकार से जिला योजना विकास समिति कार्य करती है, उसी प्रकार सरकार ने उपमण्डल स्तरीय प्लानिंग मॉनिटरिंग डवलपमेंट कमेटी भी अधिसूचित की है। मेरा दिनांक 24 मार्च को प्रश्न संख्या : 4040 लगा था उसमें जो उत्तर दिया गया है वह पुलिस या सरकार का वर्जन है कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं।

जबकि असली इश्यू प्रिवेंटिव और एजुकेटिव मैयर्ज का है और उसे देखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद तथा नगर निगम के जो प्रतिनिधि आने वाले समय में चुनकर आएंगे और जो अन्य लोकल बॉडीज के प्रतिनिधि होंगे, उनके लिए भी उपमण्डल और जिला स्तर पर वर्कशॉप्स आयोजित की जाएं। जिला स्तर की जो मीटिंग होती है, उसमें अधिकारियों का वर्जन तो सामने आ जाता है कि हमने यह किया और वह किया लेकिन जो प्रिवेंटिव और एजुकेटिव पहलू है, उस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे एक एजेंडा आइटम के रूप में शामिल किया जाए और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

वैसे तो सब-डिवीजन में एम0एल0ए0 को कन्सर्न कर दिया है परंतु जहां मंत्री नहीं है वहां जिले में सीनियर विधायक की अध्यक्षता में इसके ऊपर कार्रवाई करें। यह समाज के लिए हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि इस नशे की कुरीति को दूर किया जाए। इसके कारण झगड़े होते हैं, गोलियां चलती है और भी बहुत कुछ होता है लेकिन यह सब बाद की स्थिति है, पहले प्रिवेंटिव मैयर्ज पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

Speaker: An important issue has been brought to the notice of this House by the Hon'ble Member, Shri Jeet Ram Katwal ji. There are two issues: one is establishment of a Police Post, and the second is to nominate the local MLAs in the 20-Point Planning and Development Committees. Definitely, the House has taken cognizance of it. We will request the Government to take further necessary action in this behalf. Whatever action is taken will be informed to the Hon'ble Member, and the House will also be informed accordingly.

28.03.2025/1230/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब मुख्य मंत्री जी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित का 46वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें तथा तुलन-पत्र, वर्ष 2019-20 (विलम्ब ककारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित का 46वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें तथा तुलन-पत्र, वर्ष 2019-20 (विलम्ब ककारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब कृषि मन्त्री जी हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा-62 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट वैटनरी कांऊसिल का वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा-62 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट वैटनरी कांऊसिल का वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कुछेक दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जिला परिषदों के लेखाओं का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 ।

28.03.2025/1230/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार पंचायत के लेखों की सपंरीक्षा रिपोर्ट (जिला परिषद्, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत), वर्ष 2024-25।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2025-26), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से , लोक लेखा समिति, (वर्ष 2025-26), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

1. समिति का 28वां मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 154वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

2. समिति का प्रथम मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) पर बने 103वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर

3. सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है;

4. समिति का 50वां मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 115वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों

पर सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा गृह विभाग से सम्बन्धित है; और

28.03.2025/1230/टी0सी0वी0/ए0जी0-4

5. समिति का 196वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 36वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2025-26), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगेः-

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से , लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2025-26), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

1. समिति का 33वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 39वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का 28वाँ मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) पर बने 77वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री संजय रत्न, सभापति, स्थानीय निधि लेखा समिति, (वर्ष 2025-26), समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन जोकि स्थानीय शहरी निकायों द्वारा डबल एंट्री लेखांकन पद्धति को लागू न करने की संवीक्षा पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

28.03.2025/1230/टी0सी0वी0/ए0जी0-5

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि लेखा समिति, (वर्ष 2025-26), समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन जोकि स्थानीय शहरी निकायों द्वारा डबल एंट्री लेखांकन पद्धति को लागू न करने की संवीक्षा पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष जारी एन0एस0 द्वारा ..... जारी

28-3-2026/1235/NS-AG/1

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान होगा। दिनांक 27-3-2026 यानी पिछले कल प्रस्तुत मांग संख्या : 9, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर आगे चर्चा होगी और पिछले कल नेता प्रतिपक्ष इसमें अपना अभिभाषण दे रहे थे। जिन-जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिए हैं और जो-जो माननीय सदस्य उपस्थित होंगे केवल उन्हीं के ही कट मोशन टेकअप होंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी पहले से ही चर्चा कर रहे थे और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने रीमेनिंग वक्तव्य को इस माननीय सदन में रखें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले कल कुछ बातों का जिक्र किया है। मांग संख्या: 9, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कटौती प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया गया है। मैं कुछ बातों का जिक्र आज कर लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे साथी इसके ऊपर बोलने वाले हैं जिस नाते मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि

सरकार ने मंशा जाहिर की है कि हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए हिमकेयर योजना जो पूर्व सरकार ने शुरू की थी उसको बंद करके नई हैल्थ इंश्यारैंस स्कीम लाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी योजना के काम में कोई खामी या त्रुटि रह जाती है तो उसमें सुधार की सदैव गुंजाइश रहती है। यह कतई भी उचित नहीं है कि छोटी-सी गलती के कारण आप उस योजना को ही बंद कर दें। अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार कीजिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि आदमी के जीवन में भी हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। किसी योजना को चाहे जितना भी अच्छा बनाया गया हो लेकिन perfection can never be achieved. उसके बावजूद भी अगर इसमें सुधार करना है तो आप कीजिए लेकिन भाजपा सरकार या पूर्व की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है इसलिए इसको बंद करना है, यह कतई भी उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक तो हमारी मुश्किल यह है कि मुख्य मंत्री जी इस माननीय सदन में बहुत कम बैठते हैं। इस माननीय सदन में जब ऐसे गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही हो तो उस वक्त उनकी उपस्थिति होना लाजमी होनी चाहिए और उनको इस चर्चा को सुनना

28-3-2026/1235/NS-AG/2

चाहिए। मेरी बात अभी तक अधूरी है। मुख्य मंत्री जी ने पहले 1100 करोड़ रुपये के घोटाले के बारे में कहा और उसके बाद कहा कि 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है तथा पिछले कल 120 करोड़ रुपये बता दिया। इन्होंने इस तरह के तीन वक्तव्य दिए और ये तीनों वक्तव्य मीडिया में चले गए तथा मीडिया ने इनको अलग-अलग तरह से छापा है। मैंने कहा था कि अगर गलती हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। गलती आदमी से ही होती है। कहा भी जाता है कि मनुष्य गलती का पुतला है। आप उसमें सुधार कीजिए और माफी मांगे। लेकिन माफी मांगने में तौहीन होती है। अध्यक्ष महोदय, यह सोच का विषय है। मुझे लगता है कि आदमी माफी मांग कर छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। अच्छा होता, अगर प्रदेश के सामने इस बात का जिक्र आ जाता कि जो मेरे मुंह से शब्द निकल गया है वह उस तरह का नहीं है। उसको अखबार ने कैरी किया और छाप दिया। मीडिया के छापने के बाद यह शब्द पूरे प्रदेश के सोशल मीडिया में घूम रहा है

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

28.03.2026/1240/RKS/AS-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्य मंत्री जी ने इसकी विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं परंतु यह जांच इसलिए करवाई जा रही है ताकि इस योजना को बंद किया जाए। हिमकेयर योजना को बदनाम करके इसे बंद करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। मेरा मीडिया के मित्रों के प्रति बहुत सम्मान है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। एक दौर होता था जब इस सदन के भीतर कोई बात कही जाती थी तो मीडिया के लोग उस पर रिसर्च करते थे और जो नेता अपना वक्तव्य देते थे उसे हूबहू नहीं छापते थे। उसमें यह पक्ष होता था कि हमने क्या कहा लेकिन तथ्यों में जाने की आवश्यकता होती थी। इस योजना को बदनाम करने की दिशा में यह भी खबर छपी है क्योंकि यह बात मुख्य मंत्री जी ने कही है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत पुरुष की बच्चेदानी के ऑपरेशन और एक्सपायरी डेट के लेंस लगाने के बिल थमा दिए गए लेकिन यह बात सत्य नहीं है। अगर मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित होते तो अच्छा होता लेकिन वे इस सदन में अधिक समय गैर मौजूद रहते हैं। अगर मुख्य मंत्री जी ने एडवाइजर रखे हैं तो उन्हें सही सलाह देनी चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि एक अभिषेक नाम का एडवाइजर हैल्थ से जानकारी लेता है। वह व्यक्ति इनके विधान सभा क्षेत्र से संबंध रखता है। वह इन सारी चीजों को नीचे से खोजने में रुचि ले रहा है ताकि भाजपा को गाली देने का मौका मिले। अगर वे एडवाइजर हैं तो उन्हें कम-से-कम तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। उन्हें मुख्य मंत्री जी को सही सलाह देनी चाहिए। सच्चाई यह है कि हिमकेयर योजना के तहत 4 हजार बीमारियों के पैकेज हैं। लेकिन कई बीमारियां ऐसी भी हैं जो उस रूप में पैकेज के अंदर शामिल नहीं हो पाई हैं। यदि पैकेज में कुछ एडिशन करना हो तो उसमें यह गुंजाइश है। डॉ0 जनक राज जी इस माननीय सदन के सदस्य हैं और ये इस विषय के एक्सपर्ट हैं। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रहे हैं और ये इस विषय को बेहतर ढंग से स्पष्ट करेंगे। एक पैकेज की वैल्यू 19

हजार रुपये है जिसमें MO-003 सी0टी0 फॉर कैंसर ओवरी दवा इस्तेमाल होती है। यानी जो कीमोथेरेपी होती है उसके लिए यह दवाई उपयोग में लाई जाती है। इस बीमारी के अंतर्गत 4 मरीजों का इलाज हुआ है जिनमें एक की उम्र 37 वर्ष, एक की 25 वर्ष, एक की 71 वर्ष और एक की उम्र 12 वर्ष थी। ये सभी कैंसर के मरीज थे। इनका इलाज कैंसर अस्पताल में हुआ था। इन मरीजों का ऑपरेशन नहीं किया गया था। इनकी कीमोथेरेपी हुई थी जिसमें यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर **श्री बी0एस0द्वारा जारी**

28.03.2025/1245/बी.एस./ए.एस.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

और उसके साथ-साथ एड्स से संबंधित जो है वह सारकोमा, ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोन रिफ्रैक्ट्री प्रोस्टेट कैंसर में यह दवाई इस्तेमाल होती है और किसी ने इनको बलत जानकारी दे दी क्योंकि उस पैकेज के नाम में इस शब्द ओवरी का इस्तेमाल हुआ है इस कारण से इस पैकेज की वजह से इंप्रेशन मुख्य मंत्री को इनके एडवाइजर ने दे दिया कि आदमी की ओवरी निकाल दी गई उसका ऑपरेशन कर दिया गया। यह जिक्र उस पैकेज का है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि मुख्य मंत्री जी को बहुत जल्दबाजी रहती है, सनसनी करना। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि इनको बहुत जल्दी रहती है। अध्यक्ष महोदय जब कोई पैकेज में किसी स्पेसिफिक बीमारी का कवर नहीं मिल पा रहा है तो उसके नजदीक का कवर इस पैकेज के अंतर्गत किस प्रकार से हो जाए क्योंकि डॉक्टर की मंशा पेशेंट को मदद करने की होती है और मैं आपको कहूं कि डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है उसको बदनाम मत करिए। एक स्टेटमेंट देखकर उनको बर्बाद करना, उसको बदनाम करना, यह कतई भी उचित नहीं है।

उसी के अंतर्गत यह सारा ट्रीटमेंट है जिसके कारण यह कंफ्यूजन हुआ है। इसलिए मुख्य मंत्री जी से हमने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं अगर इसमें गलत हुआ है तो आप उसकी जांच करिए। लेकिन जब हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो गलत हुआ ही नहीं है। यह पैकेज का नाम है उस पैकेज के अंतर्गत इस प्रकार का एक इंप्रेशन मुख्य मंत्री जी को दे दिया गया है। इसमें मेजर पोर्शन जो है जिनका ट्रीटमेंट हुआ है वह

प्रोस्टेट कैंसर का है। लेकिन पैकेज के नाम की वजह से इस तरह से एक रिफ्लेक्शन चला गया और मीडिया के साथ ही उन्होंने उसको उसी तरह से छाप दिया। मैं समझता हूं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मीडिया से बहुत प्रेम है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक ही चीज को लेकर कह रहा हूं कि हम मीडिया में कोई चीज डालते हैं, हम नेताओं के कहने पर इतना भरोसा करना उचित नहीं है। हम जो बोलते हैं, ठीक है लेकिन अपना रिसर्च वर्क भी करें। अब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है और ज्यादा पोर्शन इसका एक्सप्लेन हमारे माननीय सदस्य डॉ0 जनक जी और हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय विपिन सिंह परमार जी करेंगे। वह सारी चीजों की टेक्निकल टर्म्स बताएंगे। इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ है। मीडिया के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान है।

28.03.2025/1245/बी.एस./ए.एस.-2

अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है कि हिमकेयर के ऊपर क्या आरोप लगाया जा सकता है? हमको बदनाम कैसे किया जा सकता है, पूर्व की सरकार को, पूर्व की सरकार की योजना को, पूर्व की सरकार के नेतृत्व को और पूर्व की सरकार में रहे अधिकारियों को। मैं समझता हूं यह स्वस्थ परंपरा नहीं है इसमें रुकना चाहिए। आप अच्छा करिए और अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। अगर अच्छा करेंगे तो प्रदेश आपको याद करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इससे ज्यादा बहुत चीजों का जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं और मैं आपसे एक बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं जो कट मोशन्ज हैं उनमें मेरा नाम सब जगह आ गया है तो मैं यहीं तक बोलूंगा और इसी मांग पर बोलूंगा इसके अलावा मेरे बोलने का समय मेरे बाकी के साथियों को दे दिया जाए। मैं यह निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, जब अगली मांग संख्याः आएगी तब आप थोड़ी देर के लिए सदन से अनुपस्थित रहना तो अच्छा रहेगा।

श्री जय राम ठाकुर : मैं थोड़ी देर के लिए गैर मौजूद रहूंगा जैसा आप बोलेंगे वह हम कर सकते हैं। अब यहां मैं एक खबर पढ़ रहा हूं, एक और खबर लगी है कि देहरा में सर्जन तो

तैनात हैं फिर भी ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि वहां पर ओ0टी0 नहीं है। यह भाभी जी का इलाका है और भाभी के क्षेत्र में इतना अन्याय? यह हमने कभी नहीं सोचा था। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 के बाद वहां पर सारी सुविधा होने के बावजूद भी ऑपरेशन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं वर्तमान सरकार में वहां पर जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता है,

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

28.03.2026/1250/DT/DC-1

वह वहां पर नहीं है इस कारण ओप्रेशन नहीं हो पा रह हैं। वहां से सारे ओप्रेशन के मामले टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किए जा रहे हैं। मैं दो-तीन चीजों पर बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। काम करने के लिए एक स्वस्थ सोच चाहिए। हमने नेरचौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। यह यूनिवर्सिटी अच्छे से चल रही है लेकिन अब उस यूनिवर्सिटी को बदलने की शरारत की जा रही है। मुख्य मंत्री जी स्टूडेंट पोलिटिक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्टूडेंट पोलिटिक्स में यह होता है कि जो दीवार में पोस्टर लगा हो उसे फाड़ दो। जब हम छात्र राजनीति में थे तो हमने एक जगह वॉल राइटिंग की लेकिन वह स्थल किसी दूसरे स्टूडेंट ओर्गेनाइजेशन का था। वैस वह स्पॉट पहले हमारा था लेकिन बाद में उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। हमारे मन में पीड़ा थी कि यह स्पॉट हमारा था और इसमें हम ही लिखते थे। हमने उनकी राइटिंग को चूने से मिटाकर अपनी राइटिंग कर दी। दूसरी ओर्गेनाइजेशन के लोग जब सुबह आए तो उन्होंने देखा कि यह स्पोट तो हमारा था। एस0एफ0आई0 वालों ने कहा कि यह स्पोट हमारा था इसमें ए0बी0वी0पी0 वालों ने कैसे लिख दिया। उन लड़कों ने गुस्से से नीचे पड़े गोबर को उठाकर उस राइटिंग में छाप दिया ताकि वह राइटिंग खराब हो जाए। हमारे मुख्य मंत्री जी भी ऐसा ही करते हैं। इनको भी छात्र जीवन की याद आती है। अब आप बड़े हो गए हैं इसलिए आप अच्छा सोचिए। आप उम्र और पद के हिसाब से बड़े हो गए हैं इसलिए हर जगह गोबर मत उठाइए। यह माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं लेकिन वे सदन

में उपस्थित नहीं होते। अब भाभी जी भी कितनी बातें उन तक पहुंचाएंगी। हमारा जरिया तो आप ही हैं इसलिए आप उन्हें यह बता देना कि मैं ऐसा बोल रहा हूं।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश ठाकुर जी कुछ बोलना चहा रही हैं।

श्रीमती कमलेश ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे इन बातों को अपने सर-माथे पर लगाना चाहिए क्योंकि मैं अभी सीख ही रही हूं।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए।

28.03.2026/1250/DT/DC-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती कमलेश ठाकुर जी से कहना चाहूंगा कि मेरी और माननीय मुख्य मंत्री की इस सदन में जो लड़ाई होती है वह किसी और तरह की होती है, आपकी उपस्थिति में हमने उस तरह से लड़ना अब छोड़ दिया है। यह लोकतंत्र हैं मुझे अपना कर्म करना है और माननीय मुख्य मंत्री जी को अपना कर्म निभाना है।

अध्यक्ष महोदय, कोविड माहमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग में कुछ कर्मचारी आउटसोर्स में रखे गये थे। कोविड के कारण जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया उस व्यक्ति के पास उसके परिवार का सदस्य भी नहीं जा सकता था, उसे छू नहीं सकता था। कोविड के समय जो लोग हस्पतालों में उपचार के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी डेड-बॉडी तीन-चार दिनों तक हस्पताल में ही पड़ी रहती थी लेकिन उसके अंतिम संस्कार के लिए उस व्यक्ति के परिवार के लोग भी नहीं आते थे। उस समय ऐसी स्थिति बनी। हमने उस दौरान स्वास्थ्य विभाग में वार्ड ब्यॉज,नर्सिज और फार्मासिस्ट, लगाये और उन्होंने उन व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया। वो ऐसा समय था जब परिवार का आदमी कोविड के मरीज के पास दवाई देने नहीं जा सकता था, उसको पानी पिलाने नहीं जा सकता था, खाना खिलाने नहीं जा सकता था- उस समय उन कर्मचारियों ने उन मरीजों की देखभाल की, उनकी सेवा की यानी वे लोग जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। उसमें केवल वार्ड ब्वाय नहीं नर्सिज भी थी और उसमें फार्मासिस्ट भी थे। हमारी सरकार ने एक मानवीय दृष्टिकोण से ही

सुनिश्चित किया था कि उनकी सर्विसिज को टर्मिनेट नहीं किया जायेगा। ठीक है आउटसोर्स के नियम सबके लिए एक समान है। लेकिन हम निर्णय लिया था कि उनकी सर्विसिज को टर्मिनेट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो पहले तो सरकार के द्वारा उन्हे उनकी 13-14 महिने की सैलरी ही नहीं दी गई और उसके बाद उनको हटा दिया गया और कहा गया कि अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान सरकार का यह अमानवीय दृष्टिकोण उस दृष्टि से रहा है। ..(व्यवधान) केंद्र सरकार ने सारी चीजें बंद नहीं की इनकी तन्ख्वाह स्टेट हैड से दी गई, यह बात आप गलत बोल रहे है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी..

28.03.2026/1255/डी.सी.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर..... जारी

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम हाई-एंड हेल्थ फैसिलिटीज देने के बारे में सोच रहे हैं। इसका जिक्र किया जा रहा है और मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं बार-बार कह रहा हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में जो रोबोटिक सर्जरी का जिक्र किया है, वह आप करिए, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी के लिए इतने स्थानों पर इसकी आवश्यकता है, जितने स्थानों पर आप इसकी घोषणा कर रहे हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक दो जगह लगाने की बात समझ में आती है, लेकिन पांच जगहों के लिए रोबोटिक सर्जरी के उपकरण और मशीनरी खरीद ली गई हैं। अभी हम बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि इसमें बहुत पैसा लग रहा है, खरीदने में भी और उसके बाद इसकी मेंटेनेंस में भी लग रहा है। मेंटेनेंस के साथ-साथ मरीजों से जो चार्ज लिया जाएगा, वह भी काफी ज्यादा होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में चर्चा का विषय इसलिए बन रहा कि मुख्य मंत्री जी एक चीज पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में शायद उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद भी आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा था कि आप कागज़ ले कीजिए और सदन में बताइए कि इसे कितने में

खरीदा गया है। अभी मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन हम इसकी जानकारी अवश्य प्राप्त करेंगे। जिस दिन सारी डिटेल्स आएंगी, उस दिन हम इस पर विस्तार से बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी बजट में बहुत सारे अनाउंसमैंट्स किए गए हैं। स्वास्थ्य और आयुष विभाग के अधिकारियों के लिए पैसा बढ़ाने की बात की गई। स्वास्थ्य अधिकारियों व डेंटल स्टाफ के लिए पैसा बढ़ाने की बात की गई। इसके बाद फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0, आशा कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोग्रामर, सबके लिए अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह पैसा कौन-सा है? यह पैसा कहां से आ रहा है? यह पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह एन0एच0एम0 का पैसा है, जिसके अंतर्गत यह फंड आता है और यहां पर मुख्य मंत्री जी उसकी घोषणा कर रहे हैं।...(व्यवधान) हम यह नहीं कह रहे लेकिन आप उसका जिक्र तो कर देते। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, यही तो समस्या है, अगर आप यही कह देते कि केंद्र सरकार ने हमारी

28.03.2026/1255/डी.सी.-एन.जी./2

मदद की है और उस पैसे से हम इन कैटेगरी के लोगों को लाभ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह अधिक उचित होता। लेकिन आपने उसका जिक्र करना उचित नहीं समझा। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर इसे छिपाने की क्या जरूरत है?

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार रोगी मित्र लगाने की बात कर रही है, आप लगाइए। आज मित्रों का दौर चल रहा है, तो चलाइए जितना चलता है। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने पैट स्कैन की बात की है। पैट स्कैन किसने शुरू किया था? इसकी सारी क्लीयरेंस, टेक्निकल क्लीयरेंस और एनवायरमेंटल क्लीयरेंस व अन्य सभी औपचारिकताएं हमारी सरकार के समय में पूर्ण हुई थीं। इसकी जमीन का काम हमने पूर्ण किया था और फाउंडेशन स्टोन भी हमने ही रखा था। लेकिन आज उस पर बहुत लंबा भाषण दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पैट स्कैन का काम शुरू होने के बाद it took three and a half years to

complete the building. बिल्डिंग को पूरा होने में लगभग साढ़े तीन साल लग गए और उसके बाद उस पर बहुत खुशी मनाई जा रही है। सवाल यह है कि इसे पूरा करने में इतना समय क्यों लगा? सारी क्लीयरेंस हमारे समय में हो गई थीं, टेंडर भी हमारे समय में हो गया था और पैसे का प्रावधान भी हमने कर दिया था। अभी वह ट्रायल पर है, यह अच्छी बात है लेकिन उसका श्रेय लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जो नया ट्रॉमा सेंटर है, उसके संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब उसका उद्घाटन हो चुका था, उसके बावजूद मुख्य मंत्री जी को लगा कि पुराना फट्टा लगा हुआ है लेकिन मेरा फट्टा नहीं लगा। आई0जी0एम0सी0 के ओ0पी0डी0 ब्लॉक का मैंने उद्घाटन किया था लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यहां पर एक और फट्टा लगाना है

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

28.03.2026/1300/एच0के0/ए0पी0/-01

श्री जय राम ठाकुर जारी .....

अध्यक्ष महोदय, इस नए ट्रॉमा सेंटर के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब इसका इनॉगरेशन हो गया था, उसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी को लगा की पुराना फट्टा तो लगा है लेकिन मेरे नाम का फट्टा नहीं लगा है। शिमला के आई0जी0एम0सी0 में इन्होंने अपने नाम का फट्टा लगा दिया। मैंने स्वयं ओ0पी0डी0 की इनॉगरेशन किया था। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां पर भी एक नया फट्टा लगा दिया है। जब बिल्डिंग का उद्घाटन हो चुका था, इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पलीट था और वहां काम शुरू हो चुका था तो फिर दोबारा शुभारंभ करने की क्या ज़रूरत थी? वहां पर अपना फट्टा लगाने की क्या जरूरत थी? ये छोटी-छोटी बातें हैं। अगर मैं न्यू ट्रॉमा सेंटर की बात करूं तो वहां एक आउटसोर्स एजेंसी को काम दिया गया when it was not operational and when it was not functional इसके बावजूद वहां मैनपावर को एंगेज कर दिया गया क्योंकि वह किसी बड़े नेता की एजेंसी थी। मुझे इस बारे में मालूम नहीं है लकिन हमें पता करना चाहिए। उस

एजेंसी पर करोड़ों रुपये खर्च हो गए, लेकिन जिस काम के लिए उस एजेंसी को एंगेज किया गया था, वह काम ही शुरू नहीं हुआ, क्योंकि new trauma centre was not functional. इसके बावजूद यह अपने आप में एक घोटाला है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां सुधार की गुंजाइश है उसे करन चाहिए। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं प्रदेश के लोगों को मिलें। मैंने ज़िक्र किया कि चंबा के मेडिकल कॉलेज में डेढ़ साल से टेंडर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक फर्नीचर उपलब्ध नहीं हो पाया है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी टेंडर प्रक्रिया चली लेकिन उसके बावजूद वहां भी अभी तक फर्नीचर उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद, मेडिकल कॉलेजों के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वह सारा-का-सारा पैसा केंद्र सरकार से आया है। लेकिन उसका ज़िक्र उस रूप में नहीं होता। प्रदेश को केन्द्र सरकार से पैसे खर्च करने के लिए ही दिए गए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं हम तो यही कह रहे हैं। उल्टा यह है कि जो पैसा दिया जा रहा है आदरणीय नड्डा जी द्वारा, जो हमारे केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं। वह कह रहे हैं कि

28.03.2026/1300/एच0के0/ए0पी0/-02

प्रदेश को इतना पैसा दिया जा रहा है लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा वह खर्च नहीं किया जा रहा है। उस पैसे को आप खर्च कीजिए। अगर आपको प्रदेश के लिए ओर पैसा चाहिए तो मांगिये। देश के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वे हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। जब यह पैसा खर्च किया जाए तो उसमें ज़िक्र आना चाहिए कि यह पैसा केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दिया है। अगर ऐसा ज़िक्र भी हो जाए इससे न तो आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही हमारी सेहत पर फर्क पड़ेगा। अच्छा होगा, ऐसी बातें बोल लिया करो। इसलिए, राष्ट्रपति महोदय, कट मोशन के माध्यम से जो मैंने अपनी बात कही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है। लेकिन केवल भाषणों में नहीं उसे व्यावहारिक रूप से ज़मीन पर उतारिए। जब यह ज़मीन पर उतरेगा तभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। जिस हिमकेयर योजना के माध्यम से लोगों को ज़िंदगी

मिली है उस योजना का जीवन समाप्त करने की दिशा में मत बढ़िए, यह मैं ज़रूर कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अगर आप राय हो हम माननीय सदन को 30 मिनट्स ओर चला सकते हैं। डेढ़ बजे लंच कर लें। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सार्थक चिंतन और सशक्त विचार हमारे माननीय विपक्ष, वरिष्ठ नेता और पूर्व में मुख्य मंत्री रहे श्री जय राम जी से बताएं हैं। उन्होंने जो कहा कि सुधार में बहुत गुंजाइश की आवश्यकता है, I acknowledge it. किसी भी चीज में because governments are in continuity. जो इन्होंने सुझाव दिये हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप भी तो इस तंत्र के हिस्सा हैं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

28.03.2026/1305 /AT/HK /01

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणा मंत्री जीर....

And we shall certainly see what all can be done. My only prayer and request and earnest desire is that we all as a complete House, visit Delhi and apprise them with the situation that we are confronted with. It is a very-very serious and unique problem of his times. I feel, their comes a time in the history of any nation, such a time come very rarely. God forbid that COVID should not come. When COVID came we were all defenceless. He is right. Many people used to come and weeping, particularly ladies and we tried our best to put them atleast PSA or wherever we could and even today I feel that our Cabinet will consider it. Those who saw those testing time and who were really not scared of touching or going near to a dead body. लोग तो अपने पेरेंट्स के जाने के बाद ही

पहले फेज में नहीं जाते थे। यह आपने ठीक बात कही। परंतु उन्होंने जो काम किया है, उसके बारे में विचार किया जाएगा और आपके जितने भी सुझाव हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। I normally don't get in between because I will suddenly reply to all your points. Thank you, Sir.

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक लंच ब्रेक के लिए 2:05 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

28.03.2026/1410/केएस/वाईके/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.10 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्षः अब कटौती प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल से रिवाइज्ड लिस्ट प्राप्त हुई है जिसमें 8 माननीय सदस्य ही इस कटौती प्रस्ताव पर हिस्सा लेंगे। जो प्रायोरिटी विधान सभा सचिवालय ने सुनिश्चित की थी, उसमें भी उन्होंने परिवर्तन चाहा है जिसकी मैं इजाज़त दे रहा हूं। जो प्रायोरिटी लिस्ट मुझे माननीय सुख राम चौधरी जी से प्राप्त हुई है उसके मुताबिक मैं माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी से आग्रह करुंगा कि वे कटौती प्रस्ताव पर आगे चर्चा करें।

श्री पवन काजल : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या : 9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कटौती प्रस्ताव पर बालने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका आभार। मैं प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मैडिकल कॉलेज टांडा के बारे में बात करना चाहता हूं जहां प्रतिदिन की ओ0पी0डी0 2000 से ले कर 2500 तक है और लगभग 6 जिलों के मरीज यहां पर आते हैं। इसमें सीटी स्कैन की वेटिंग 2 महीने, एम0आर0आई0 की वेटिंग 3 महीने और अल्ट्रासाउंड की वेटिंग 1 महीना रहती है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

28.03.2026/1415/av/yk/1

श्री पवन कुमार काजल ------जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि टांडा मेडिकल कॉलेज प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है और वहां पर प्रति दिन 2000 से 2500 ओ0पी0डी0 होती हैं। लेकिन उस संस्थान में केवल एक सी0टी0 स्कैन और एक एम0आर0आई0 है। इस मेडिकल कॉलेज में चम्बा, भरमौर, चुराह और जिला कांगड़ा के 15 विधान सभा क्षेत्रों से मरीज आते हैं जिसके कारण यह होस्पिटल ओवर लोडिड है। वहां पर पिछले लगभग 6 महीनों से चारों लिफ्टें खराब पड़ी हैं।

वहां पर यदि सी0टी0 स्कैन के लिए चम्बा, भरमौर, चुराह या कांगड़ा के 15 विधान सभा क्षेत्रों से कोई भी मरीज आता है तो डॉक्टर उसको बोलता है कि आप पहले सी0टी0 स्कैन करवाकर लाइए। मगर जब आप सी0टी0 स्कैन करवाने जाते हैं तो उसमें दो-दो महीने की वेटिंग होती है। मैं इस माननीय सदन में वर्ष 2012 से आ रहा हूं और मैं इस मेडिकल कॉलेज के बारे में हमेशा ही बोलता रहा हूं। वहां पर जब कोई डॉक्टर किसी मरीज को देखता है और स्थिति ऐसी होती है कि सी0टी0 स्कैन का नम्बर दो महीने बाद या एम0आर0आई0 6 महीने के बाद होगी तो आप खुद ही सोच लीजिए कि टांडा मेडिकल कॉलेज में कैसे मरीज आते हैं। वहां केवल निर्धन, गरीब और आम आदमी ही आते हैं। लेकिन 10 हजार रुपये की एम0आर0आई0 करवाने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है। मैं आपके ध्यान में एक और बात भी लाना चाहता हूं कि यदि आप छोटा-सा स्टोन का ऑपरेशन भी करवाना चाहेंगे तो उसमें भी 5-6 महीने की वेटिंग होती है। कई बार तो इस प्रकार की सूचना भी मिली है कि जो डॉक्टर टांडा में देख रहे हैं वे ही बोल देते हैं कि आप फलां-फलां होस्पिटल में जाइए। वहां पर आपका स्टोन का ऑपरेशन या कोई दूसरा ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैं मंत्री जी को एक मरीज के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे गांव का एक व्यक्ति है। एक बार वह चलते-चलते मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि आप इतने चिन्तित क्यों लग रहे हैं? उसने बताया कि मेरी धर्मपत्नी को स्टोन था।

लेकिन टांडा मेडिकल कॉलेज में वेटिंग थी और मैं दूसरे प्राइवेट होस्पिटल में चला गया। जहां पर मुझे कहा गया कि जल्दी कीजिए वरना आपकी धर्मपत्नी के साथ कुछ भी हो सकता है। यह पत्थरी गुर्दे में जा रही है। वहां पर

28.03.2026/1415/av/yk/2

उन्होंने उसके उस छोटे से ऑपरेशन का 1.25 लाख रुपया ले लिया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सारे ही होस्पिटल ऐसे नहीं हैं, कई होस्पिटल बहुत अच्छे-अच्छे भी हैं। परंतु कुछ होस्पिटल ऐसे हैं, आपमें से कोई भी नॉर्मल व्यक्ति ऐसे होस्पिटल में चला जाए तो वे तैयार रहते हैं कि स्टंट डालना पड़ेगा। इस प्रकार की शिकायतें आई हैं और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकारी होस्पिटल के डॉक्टर्ज ही निजी स्वास्थ्य संस्थानों में ऑपरेशन करते हैं। लेकिन उन्होंने फेस मास्क लगाया होता है। इसके अलावा आजकल एक और ट्रैंड चला है। कई डॉक्टर्ज निजी होस्पिटल में कैप पहन कर आते हैं। वास्तव में डॉक्टर्ज की नियुक्ति टांडा मेडिकल कॉलेज में होती हैं परंतु वे ऑपरेशन निजी होस्पिटल्ज में करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 5 नवम्बर, 2025 को पंजाब केसरी में छपी खबर पढ़ना चाह रहा हूं कि 'मरीज फर्श पर लेटने को मजबूर'।

टी सी द्वारा जारी

28.03.2025/1420/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री पवन कुमार काजल... जारी

सराय से बेखबर तीमारदार सर्दी की ठंडी रातों में फर्श पर सोने को हुए मजबूर। बसंती देवी, हमीरपुर से आई थीं, उन्होंने बताया कि उनके पति का इलाज चल रहा है और उन्हें सराय के बारे में पता नहीं था इसलिए ठंड में बरामदे में चादर बिछाकर सो गए। हमारे पास पैसे नहीं थे कि बाहर कमरा ले लें।

इसी प्रकार नूरपुर से आए एक व्यक्ति ने बताया कि उसके भाई की सर्जरी है और एक कमरे का किराया 600 रुपये है जो उनके लिए बहुत अधिक है इसलिए अस्पताल के अंदर ही फर्श पर रात गुजारनी पड़ी। शहनाज़, चंबा से अपनी ढाई वर्ष की बच्ची को लेकर टांडा आई थी। बच्ची की तबीयत खराब थी लेकिन वहां ठहरने में बहुत दिक्कत हुई। सराय दूर होने के कारण और पैसे न होने की वजह से बरामदे में ही बच्ची को चादर लेकर फर्श पर सुलाना पड़ा।

मंत्री महोदय, टांडा मेडिकल कॉलेज को स्थापित हुए कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन सराय की सुविधा दूर होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। आने वाले समय में इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार दिनांक 26 मार्च, 2026 को 'टांडा में आउटसोर्सिंग वार्डबॉय ने की हड़ताल' सरकार ने लगभग 3 माह से सैलरी का भुगतान नहीं किया। वहां आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने के कारण उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। "अनिश्चितकालीन हड़ताल पर टांडा मेडिकल कॉलेज के वॉर्डबॉय, स्वास्थ्य सेवा चरमराई", "वेतन न मिलने से उपजा क्रोध", "आई0सी0यू0 में महिलाओं की देखभाल प्रभावित" यह सभी खबरें समाचारों में प्रकाशित हुए हैं। मैं अपनी ओर से सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि स्थिति को सामने रख रहा हूं।

(सभापति श्री संजय रत्न जी पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, टांडा में पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। प्रतिदिन 2000-2500 मरीज आते हैं और उनके साथ परिजन तथा अन्य लोग भी वाहनों के साथ आते हैं लेकिन पार्किंग के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आज तक वहां बहुमंजिली पार्किंग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। कांगड़ा जिला का यह बहुत बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है, इसलिए वहां पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए।

28.03.2025/1420/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

इसी प्रकार हिमकेयर योजना की बात की जाती है कि इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह योजना पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी की देन है। यह योजना गरीब और आम आदमी के लिए संजीवनी

बूटी के समान है, इसको आप बंद कर रहे है। यदि इसमें कोई घोटाला हुआ है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए लेकिन इस योजना को बंद करना उचित नहीं क्योंकि इसमें गरीब और निर्धन परिवारों के लोगों का क्या कसूर है?

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कांगड़ा जिला अस्पताल में दो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं लेकिन वहां रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। पिछले 50 वर्षों में बना भवन जर्जर हो चुका है। इसी प्रकार वहां सर्जन और स्पेशलिस्ट मौजूद हैं लेकिन ढाई-तीन वर्षों से वहां कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। एनेस्थीसिया की सुविधा है लेकिन ओ0टी0 उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर होने के बावजूद भी जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

तियारा के कम्युनिटी हैल्थ सेंटर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा दिया गया है। वहां मेडिकल ऑफिसर के 10 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 6 भरे हुए हैं और 4 खाली हैं लेकिन एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है। जब स्पेशलिस्ट ही उपलब्ध नहीं है तो उसको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा देने का क्या मतलब? अस्पताल का भवन भी जर्जर स्थिति में है। वहां एक्स-रे मशीन उपलब्ध नहीं है जबकि वहां रेडियोग्राफर का पद है। इस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में एक्स-रे की मशीन का होना भी जरूरी है।

एन0एस0 द्वारा ..... जारी

28-3-2026/1425/एन0एस0-ए0जी0/1

श्री पवन कुमार काजल-----जारी

सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन का होना भी जरूरी है। इस बार मुख्य मंत्री जी ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को कट लगाया। मैं सोच रहा था कि तियारा संस्थान में एक्स-रे मशीन विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से दे दूंगा और वहां पर सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की मशीन देने की भी कोशिश करूंगा लेकिन हमारी विधायक निधि 2.20 करोड़ रुपये में से 1.10 करोड़ रुपये काट दिए। मैं भाबी जी से कहना चाहूंगा, मुझे यह नहीं पता कि मुख्य मंत्री जी आपकी बात मानते हैं या नहीं लेकिन इस माननीय सदन में 68 विधायक जीत कर आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में शक्ति क्या होती है? मैं जब

वर्ष 2012 में पहली बार विधायक जीत कर आया तो उस समय 50 लाख रुपये विधायक क्षेत्रीय विकास निधि मिलती थी। उसके बाद 70 लाख रुपये हुई, फिर 1 करोड़ रुपये हुई और फिर 1.25 करोड़ रुपये तथा उसके बाद 1.50 करोड़ रुपये हुई। मुख्य मंत्री जी, आप 68 विधायकों की 1.10 करोड़ रुपये निधि काट कर क्या आप 75 करोड़ रुपये से प्रदेश को चलाना चाहते हैं? क्या इन 75 करोड़ रुपये से प्रदेश की आर्थिकी मजबूत हो जाएगी? मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि यह बात ठीक है कि सत्ता पक्ष के विधायक मुख्य मंत्री जी के सामने नहीं बोल पाते हैं। दूसरा, मुख्य मंत्री जी आप सबकी बात भी नहीं सुनते हैं और वे अपनी ही मर्जी करते हैं। मैं इसलिए भाबी जी को कह रहा था कि आपने मुख्य मंत्री जी को बोलना कि जो भी विधायक जीत कर विधान सभा पहुंचता है और न जाने किन परिस्थितियों में जीत कर आते हैं तो उनको हमारे हक को स्ट्रैंथन करना चाहिए। लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। हमने कई जगहों पर डंगे लगवाने, पुलिया बनवाने की घोषणा की हुई है। इस पर सीधा कट लगाना सही नहीं है। मैं समझता हूं कि 75 करोड़ रुपये से आपकी आर्थिकी मजबूत नहीं होगी।

सभापति महोदय, पूर्व में श्री जय राम ठाकुर की सरकार थी और उस समय मैं आपके साथ था। मैं कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियों को देख कर भांप गया था जब आपने बड़ी-बड़ी गारंटियां दीं और महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की तथा एक वर्ष में 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया। आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया। आपको पता है कि आपने मुझे वर्किंग प्रेजीडैंट बना दिया था। आपने मुझे

28-3-2026/1425/एन0एस0-ए0जी0/2

बड़ा मान-सम्मान दिया था। लेकिन ये जो गारंटियां थीं, ये जो आपने फॉर्म भरवाए तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और हमेशा उनके साथ धरातल में रहता हूं। मेरे क्षेत्र की जनता बार-बार मुझे जीता कर भेजती है लेकिन जो गारंटियों की बात थी तो मैं झूठ बोलकर फॉर्म भरवाकर वोट नहीं ले सकता हूं। इसलिए मैं अपनी पुरानी पार्टी में आ गया। आप सबको पता है और सत्ता पक्ष के सभी विधायक अपने दिल पर हाथ रख कर सोच सकते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है? आप मुख्य मंत्री जी के सामने नहीं

बोल पाते हैं। मेरे क्षेत्र में श्री जय राम ठाकुर जी ने रानीताल में एक पी0एच0सी0 खोली। रानीताल के सराउंडिंग एरिया में कोई भी स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। आपने उसको बंद कर दिया। तकीपुर में पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 में अपग्रेड किया गया था और आपने उसको भी बंद कर दिया। चंगर एरिया में सब-सेंटर, गालियां को बंद कर दिया। मेरे क्षेत्र के राजल में एक टापू है जो 2 से 3 पंचायतों को फीड करता है आपने उसको भी बंद कर दिया। मेरे चंगर एरिया में नंदरूल, खरटी और बौड़कुआलू आदि शामिल हैं।

सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज, टांडा में 2000 से लेकर 2500 मरीजों की ओ0पी0डी0 प्रतिदिन होती है। मेरे क्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल या जितनी भी सी0एच0सीज0 हैं, ये छोटे-छोटे क्षेत्रों को कवर करते हैं। मेडिकल कॉलेज, टांडा एक रिसर्च सेंटर है। कांगड़ा अस्पताल में 12 पद सैंक्शन्ड हैं और वहां पर 12 डॉक्टर्ज मौजूद हैं लेकिन वहां पर सर्जरी नहीं हो सकती है, वहां पर एक्स-रे, सीटी स्कैन नहीं हो सकता है। इसी तरह और भी छोटे-छोटे अस्पताल हैं अगर हम इनको स्ट्रैंथन करेंगे तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वे अच्छा काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज, टांडा से लाखों मरीज ठीक होकर गए हैं। लेकिन जैसे-जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराना हो रहा है तो उसको भी स्ट्रैंथन करना अनिवार्य है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

28.03.2026/1430/RKS/AS-1

श्री पवन कुमार काजल जारी.....

स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। हमें इस बात को सुनते हुए डेढ़-दो साल हो गए हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? अमर उजाला में 24 फरवरी, 2026 को यह खबर छपी थी कि 'हिमाचल में बनी 71 दवाओं के सैंपल फेल हुए'। दिव्य हिमाचल में 24 मार्च, 2026 को यह खबर छपी थी कि 'हिमाचल में बनी 72 दवाएं खाने लायक नहीं'। पंजाब केसरी में 24 मार्च, 2026 को यह खबर छपी थी कि 'हिमाचल में बनी 73 दवाओं के सैंपल फेल हुए'। हिमाचल एक छोटा-सा शांतिप्रिय प्रदेश

है। यह देव-भूमि है। यहां अस्पतालों की तो पहले ही हालत खराब है लेकिन दवाइयों के सैंपल फेल होना भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हर मुख्य मंत्री साल में एक या दो बार टांडा मेडिकल कॉलेज अवश्य जाता था क्योंकि वह संस्थान प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है। यह स्वास्थ्य संस्थान जिला कांगड़ा के 15 विधान सभा क्षेत्रों के साथ अन्य 6 जिलों को सेवाएं प्रदान करता है लेकिन वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी साल में एक दौरा भी नहीं कर पाते। आपको इस बात पर विचार करना चाहिए। टांडा मेडिकल कॉलेज में निर्धन, लाचार और बेसहारा लोग अपना उपचार करवाने जाते हैं इसलिए इस अस्पताल को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आपने टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की है लेकिन इसमें यह फरमान आ गया कि रोबोटिक सर्जरी के लिए 50 या 60 हजार रुपये मरीजों को अपने खर्च करने होंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

28.03.2026/1430/RKS/AS-2

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, मैं मांग संख्याः 9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, इसका अनुमान उसके वार्षिक बजट प्लान से लगाया जा सकता है। बजट में घोषणाएं, भविष्य का विजन कुछ भी लिखा हो परंतु उन योजनाओं के लिए राशि कहां से आएगी इस बात का उल्लेख न हो तो वह बजट बेकार है। समाज में किसान-बागवान, व्यापारी, कर्मचारी, युवा और महिलाओं को कभी-न-कभी किसी-न-किसी बीमारी से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन हम इस बार का वार्षिक बजट प्लान देखें तो वह लगभग 54 हजार करोड़ रुपये के आसपास पहुंचा है जोकि गत वर्ष की तुलना में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये कम है। यदि बजट एलोकेशन की बात की जाए तो मुख्य मंत्री जी स्वास्थ्य क्षेत्र में हाई-एंड टेक्नोलॉजी लाने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या एक रोबोटिक मशीन के माध्यम से पूरा समाज बदल जाएगा? क्या PET-

स्कैन मशीन स्थापित करने से हिमाचल प्रदेश के लोगों को पूर्ण राहत मिल जाएगी? मैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखे गए बजट की ओर नजर डाल रहा था।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.03.2025/1435/बी.एस./ए.एस.-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

इसके लिए 5.83 प्रतिशत बजट रखा है, कुल मिला करके यह 2,800 करोड़ रुपये के करीब बनता है। यदि शिक्षा विभाग की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो यह लगभग 17.85 प्रतिशत बनता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऊंची उड़ान, परंतु सरकार की इस ऊंची ऊड़ान में के पखों में दम नजर नहीं आता है और यह बगैर पंखों के है। न उसमें हिम्मत है और न ही हौंसला है। आखिर जो यह सब कुछ इस माननीय सदन में 4 घंटें 7 मिनट का लंबा भाषण पढ़ा गया उसका औचित्य क्या है? अब बजट के पेज नंबर वन की बात करूं, इसमें 54,928 करोड़ रुपये दर्शाया है और राजस्व घाटा 6,577 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। यदि मैं उससे आगे बढ़कर बात करूं तो राजस्व घाटा 9,698 करोड़ रुपये है। यहां पर सुबह आदरणीय जय राम ठाकुर जी देहरा के बारे में कह रहे थे कि वहां पर मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं, सर्जन भी हैं, गायनी के डॉक्टर भी हैं और एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी हैं परंतु वहां पर अगर ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है तो इतनी फौज इकट्ठी क्यों की ? मतलब धोती है तो लंगोटी नहीं है। अगर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट नहीं है तो ऑपरेशन कहां होगा?

हम कई बार बहुत परेशान होते हैं। यहां पर एक माननीय सदस्य कह रहे थे और मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे अस्पताल में तो सारे डॉक्टर्ज हैं। मैंने कहा कि मशीनें भी होंगी। मैंने कहा टेक्निकल स्टाफ कहां है? बोलते मेरे घर में बाग -बगीचे में काम कर रहे हैं। लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट इनके बाग-बगीचे में काम कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या वह किसी के घर स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेकर से इस प्रकार का काम कर सकते हैं? प्रदेश के लिए जो यहां पर बजट के प्रावधान रखा गया है उस बजट के प्रावधान में यहां पर अस्पताल का जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वह शून्य

हो गया है। यहां पर डॉक्टर्ज की कमी है और डॉक्टर्ज की कमी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं पर इको टेस्ट होता है, इको टैस्ट तो अब पांच जगह होते हैं। तो इको टैस्ट के लिए टेक्नीशियन ही नहीं है। आदरणीय अवस्थी जी, आपका बोलने का समय आएगा कृपया सुन लीजिए। मेरे बोलने से आप इतने कॉप्लेक्स क्यों हो जाते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि यहां पर इस सदन में कहा जाता है कि अब तो शिमला में भी ओपन हार्ट सर्जरी

28.03.2025/1435/बी.एस./ए.एस.-2

हो रही है, ठीक है। यह टांडा में भी हो रही है। परंतु अखबारों में जो खबर छपती है वह बड़ी चिंतनीय होती है, दुख वाली होती है। हमारे वहां पर भी लैब टेक्नीशियन की कमी है। वहां पर भी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की कमी है। पिछले तीन-सवा तीन सालों में कोई भर्ती नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी के लिए हमारे पास बहुत अच्छे योग्य डॉक्टर्ज हैं परंतु वहां पर जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तो वहां पर परफ्यूजनिस्ट नहीं है अगर कोई छुट्टी पर चला जाता है तो ऑपरेशन नहीं होता है।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह जो टेक्निकल स्टाफ है इस बजट में घोषणा की गई है और कहा गया है कि हम लैब टेक्नीशियन रखेंगे। यहां पर कहा गया है कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट रखेंगे, फार्मासिस्ट रखेंगे। यह अच्छी बात है लेकिन आज तक इसके बारे में विचार क्यों नहीं किया गया? आपका लगभग सवा तीन साल बीत गए हैं। आपके पास रेडियोग्राफर नहीं हैं। हमारे अस्पतालों में सीटी स्कैन हैं। एक खबर आज मेरे सुलह विधान सभा क्षेत्र में छपी और पूरे जोन में बड़ी खुशी हो गई कि एक रेडियोलॉजिस्ट आ गए हैं। अंजन कालिया ने 6 महीने का कहीं डिप्लोमा किया है उनके कहीं बिलासपुर में ऑर्डर हुए थे अब थुरल में आ गए हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सीटी स्कैन की मशीन थुरल में बेकार पड़ी हुई है, भवारना में भी बेकार पड़ी हुई है। यहां पर हमारे इस पक्ष के माननीय विधायक भी दबी जवान में जिक्र कर रहे थे।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी न रेडियोग्राफर है और न ही रेडियोलॉजिस्ट है। इस सदन को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर वही बातें कहीं या रखी जाए जो बातें इस सदन के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचे ताकि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान और स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो सकें और अधिक मजबूत हो सके।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान प्रदेश के आर्थिक सर्वे की और ले जाना चाहता हूं। आर्थिक सर्वे ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में बड़ी चिंता प्रकट की है। आर्थिक सर्वे के पेज नंबर 305 में दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 835 स्वास्थ्य संस्थान हैं और 16600 बेड हैं। वहां पर हेल्थ के लिए जो टेक्निशियन होने चाहिए पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए डॉक्टर होने चाहिए, वे वहां पर नहीं हैं और मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात का बहुत खेद है। जब इसी सदन में प्रश्न पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में कितने एमबीबीएस डॉक्टर रजिस्टर्ड है तो उत्तर दिया गया कि आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, एक एम्स है और आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। मैं यहां पर उसी का जिक्र कर रहा हूं जो इकोनामिक सर्वे में छपा है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 करोड रुपए के उपकरण खरीदे गये। टांडा मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री जी को बार-बार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है और उसमें उल्लेख किया जा रहा है कि इस चिकित्सालय में 90% जो सर्जरी हैं वह एक जैसे ही उपकरण से होती है कृपया करके उन्हें रिप्लेस कर दीजिए, परंतु उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर रहा। यह प्रपोजल लगभग आज से 5 साल पहले आई थी इसलिए यह रिपोर्ट यहां पर कोट की जा रही है। सभापति महोदय यह जानकारी आपके माध्यम से मैं इस सदन को देना चाहता हूं। मैं एक हवाला और देना चाहता हूं उसकी चर्चा बहुत हो रही है और उसको सनसनी खेज तरीके से पेश भी किया जा रहा है- वह है हिमकेयर योजना। पूर्व सरकार द्वारा जो हिम केयर योजना शुरू की गई या केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना शुरू की गई तो वे योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लोगों के

लिए थी। हिमकेयर योजना के ऊपर इस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है, उस योजना के साथ पूर्व सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के मन में यह बात बैठ जाए कि हिमकेयर योजना उनके लिए उपुयक्त नहीं है- इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस जैसी नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2019 में यह योजना शुरू की गई थी और इसमें लगभग साढे पांच लाख लोग इसके माध्यम से अपना स्वास्थ्य उपचार करवाते थे। एक परिवार में एक सदस्य को 5 लाख रुपये तक का उपचार सरकार की ओर से किया जाता था और यदि किसी परिवार में अगर 5 सदस्य हो तो उस परिवार में 25 लाख रुपये का उपचार सरकार द्वारा करवाया हिमकेयर योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता था। मुझे कई लोग कहते थे कि आयुष्मान योजना के माध्यम से हमारी हार्ट सर्जरी हो गई, एंजियोग्राफी हो गई, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया। यही नहीं बल्कि मैमोग्राफी और ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का उपचार भी इस योजना से हो पाया। किडनी रिप्लेसमेंट या गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए जो सुझाव लिए जाते हैं उसमें भी इनिशियली इसी योजना से उसके ऊपर खर्च किया जाता था। इस योजना से डायलिसिस किया जाता था, ट्रांसप्लांट इसके माध्यम से होता था, न्यूरो सर्जरी इसमें होती थी और सामान्य सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी इसके माध्यम से होता था। प्रेगनेंसी और डिलीवरी भी इसमें कवर होती थी। शरीर में कई प्रकार के संक्रमण हैं, इंफेक्शन है उसका उपचार भी किया जाता था। मुझे इस बात को लेकर के भी बहुत प्रसन्नता है कि जब यह योजना वर्ष 2019 में हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान की तर्ज पर बनाई थी तो ऐसे बच्चों की सेवा करने का भी मौका मिला जो जन्म से ही मुक व बधिर थे। सरकार ने उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट प्रदेश में स्थापित किया लेकिन आज ये आज बंद है। पांच लाख रुपये की सहायता से एक छोटा सी मशीन कानों में इम्प्लांट करने के बाद के बाद जो गूंगे बहरे बच्चे है वे स्पीच थेरेपी के माध्यम से बोलना शुरू करते थे। हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह सरकार ऐसी सौगात दे रही है

श्री एन0जी0 द्वारा जारी..

28.03.2026/1445/डी.सी.-एन.जी./1

श्री विपिन सिंह परमार..... जारी

मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जड़ तक जाना चाहिए और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके नाम सामने आने चाहिएं। सभापति महोदय, यहां पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि किसी भी बीमारी से संबंधित जब मरीज अस्पताल पहुंचता है तो वहां उस विभाग के डॉक्टर सबसे पहले कोड लगाते हैं। कोड जनरेट होने के बाद एम्स की एनालॉजी के आधार पर उस बीमारी के इलाज के लिए कितना पैसा खर्च होगा, उसके पैकेज की जानकारी दी जाती है। उसके बाद आई0पी0डी0 के माध्यम से 24 घंटे के भीतर इलाज शुरू होता है। इसलिए हम सबसे पहले यह जानकारी आपके माध्यम से लेना चाहते हैं कि वह कौन-सा डॉक्टर है, जिसने किसी पुरुष के नाम पर ओवरी कैंसर का जिक्र करने के बाद जाली बिल क्रिएट कर दिए? कृपया तहकीकात में जाइए और पूरी जानकारी दीजिए। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का सनसनीखेज माहौल व वातावरण बिल्कुल मत बनाइए। मेरी जानकारी के अनुसार ओवरी कैंसर की दवा लगभग 28 दिन तक चलती है और मरीज को अस्पताल में भर्ती रखना पड़ता है तथा बीच-बीच में उसे छुट्टी भी दी जाती है। शिमला के कैंसर अस्पताल में 37 वर्ष, 50 वर्ष, 71 वर्ष और 12 वर्ष की आयु के चार मरीजों का इलाज हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि गहराई तक जाइए और सही जानकारी प्राप्त कीजिए। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कोई एक डॉक्टर आजकल जानकारियां शेयर कर रहा है। अगर जानकारी शेयर करनी है तो अच्छे काम के लिए कीजिए। यह बताइए कि टांडा मैडिकल कॉलेज कैसे और बेहतर बन सकता है तथा शेष 6 मैडिकल कॉलेज कैसे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर अपनी जगह नेताओं के दरबार में

बनाने के लिए गलत आंकड़े दिए जाएंगे, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे।

28.03.2026/1445/डी.सी.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि MO-003 CT for cancer, यह कीमोथैरेपी के माध्यम से कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। चाहे वह यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो, एड्स से संबंधित सराकोमा हो, मेल ब्रेस्ट कैंसर हो या हार्मोनल प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी आदि का उपचार इसी व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में सबसे पहले कहा गया कि 1100 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा घोटाला हो गया। उसके बाद उसमें सुधार करते हुए कहा गया कि लगभग 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। कौन-सा घोटाला? कृपया उस घोटाले की जानकारी तो सांझा कीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है, वह आयुष्मान और हिमकेयर योजना को बंद करने के लिए एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज भी हिमाचल प्रदेश में मैडिकल कॉलेज से लेकर जोनल अस्पतालों तक लगभग 400 करोड़ रुपये की देनदारियां लम्बित हैं। हर सत्र में अलग-अलग जानकारियां सामने आती हैं। टांडा मैडिकल कॉलेज को लगभग 55 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। वेंडर्स ने सामान देना बंद कर दिया है। स्टंटिंग बंद हो गई है और सारी सर्जरी भी बंद हो गई हैं। कैथ लैब से मरीजों को बाहर निकालकर यह कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके भी 19 करोड़ रुपये टांडा मैडिकल कॉलेज के जमा करवाने हैं। चम्बा में एक महिला को अपने बच्चे के इलाज के लिए कान की बालियां गिरवी रखनी पड़ती हैं। मैंने तो यह भी देखा है कि आज के हालात में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोग साहूकारों से कर्ज लेकर व जमीन गिरवी रखकर अपना इलाज करवाने को मजबूर हो रहे हैं। गारंटियों ने आपको जिताया होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के उन लोगों की सेवा करने के लिए निर्वतमान सरकार यानी

श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने भी 'नर सेवा-नारायण सेवा' के भाव से हिमाचल प्रदेश में काम किया था। जो आर्थिक सर्वे आया है, वह बहुत चौंकाने वाला है

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

28.03.2026/1450/एच0के0/ए0पी0/-01

श्री विपिन सिंह परमार जारी .....

आर्थिक सर्वे का पेज नम्बर 304 कहता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को 14.4 प्रतिशत अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। उनकी जेब हल्की हो रही है। मैं ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हैं। सभापति महोदय, इस आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि जो नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। यहां पर हमारे एक साथी ने जेनरिक दवाइयों का जिक्र किया। जेनरिक दवाइयां देश में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में तैयार होती हैं, जो देश का लगभग 40 प्रतिशत हैं। इससे हिमाचल प्रदेश को राजस्व भी प्राप्त होता है, लेकिन यह क्षेत्र बदनाम हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लगभग 1400 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आपके ड्रग कंट्रोलर वहां बैठे हैं, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर भी मौजूद हैं। प्राइम लोकेशन के लिए आपके पास आते होंगे। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, दून या सिरमौर के इलाकों से न वे कांगड़ा से आना चाहते हैं, न कुल्लू जाना चाहते हैं, न मंडी जाना चाहते हैं। ऐसी जेनरिक दवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए जो पेटेंट के बाद हमारा उद्योग तैयार कर रहा है, उसके ऊपर हमारी सरकार कोई ठोस नीति क्यों नहीं बना रही है? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) क्षेत्र से लगभग 40 प्रतिशत दवाइयों का उत्पादन आज पूरे देश में होता है, वह आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सभापति महोदय, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लैब के लिए पैसा दिया। उस लैब को स्थापित कर दिया गया। वह लैब चल रही है लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग 35 लाख रुपये चंड़ीगढ़ के उस व्यक्ति को चलाने के लिए हर महीने दें रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस लैब में पिछले एक साल में 9 टेस्ट हुए हैं। उस

व्यक्ति का कोई जानने वाला होगा। इसलिए सरकार के खजाने से यह पैसा दिया जा रहा है। मैंने मुख्य मंत्री जी के भाषण में सुना कि उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में सैपलिंग के लिए ड्रग लैब्ज को स्थापित करेंगे। जो लैब कंड़ाघाट में है, उसकी हालत तो पहले आप सुधारो? जो गवर्नमेंट सप्लाई होती है वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में टेंडर के रूप में अस्पतालों में गई, उनमें से लगभग साढ़े तीन सौ दवाइयों की रिपोर्ट आई, जबकि कई

28.03.2026/1450/एच0के0/ए0पी0/-02

दवादयों की रिपोर्ट ही नहीं आई है। आप ही बताए कि वेंडर द्वारा कैसी दवाइयां भेजी गई, उन दवाइयों की गुणवत्ता कैसी थी? कृपया करके मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ, विशेषकर उन गरीब लोगों के साथ न्याय करें। अगर गरीब व्यक्ति को मिलावटी या खराब दवाई मिलेगी, तो वह बिमार व्यक्ति अपनी मेहनत-मजदूरी और भाई से पैसा उधार लेकर अपना इलाज करवाता है। अगर दवाई असर ही नहीं करेगी तो उसका उपचार कैसे होगा? मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विशेषकर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हिमाचल प्रदेश सरकार कोई ठोस काम नहीं कर रही है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 16 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें करीब साढ़े तीन लाख लोग बी0पी0 से ग्रसित पाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 2 लाख लोग डायबिटीज के मरीज पाए गए हैं, 14,369 अन्य मामले भी आर्थिक सर्वे में दर्ज किए गए हैं। अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार हिमाचल प्रदेश को उड़ाना तो चाहती है लेकिन उसके पंखों में जान नहीं है और जब पंखों में जान नहीं होगी तो यह उड़ान कब नीचे आ जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं ...(व्यवधान) सभापति महोदय, हाई एंड टेक्नोलॉजी

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

28.03.2026/1455/AT/HK /01

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

बात कर रहे हैं यह अच्छी बात है ...(व्यवधान) लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी चिंता कर लीजिए। हमारे सिविल अस्पताल थुरल, अस्पताल भवारना और अस्पताल धीरा की स्थिति भी देख लीजिए। मुख्य मंत्री जी ने डेढ़ महीना पहले इनका उद्घाटन कर दिया लेकिन उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक नहीं बना है, जो कि बहुत जरूरी हिस्सा है। न वहां पर बेड हैं, न लैब हैं, और न ही वहां तक 108 एम्बुलेंस पहुंच सकती है। यह किस तरह की जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया?

मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा था कि हमारी सरकार ने चार जगह पी0एच0सी0 खरोट, पी0एच0सी0 भट्ठू और पी0एच0सी0 अरला थी कृपया करके उन्हें खोल दीजिए। लेकिन उन बातों को नजरअंदाज कर दिया गया।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं आप रोबोट लगाइए, किसने मना किया है? लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि अगर ई-टेंडरिंग हुई है तो उसमें कितनी कंपनियों ने भाग लिया? यह जानकारी हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने यह मामला ध्यान में आ जाए। अगर ई-टेंडरिंग हुई है तो दा विंसी कंपनी, जो एक अमेरिकी कंपनी है ने 28 करोड़ रुपये की रोबोट मशीन लगाई है। इसके अलावा मंत्रा की मशीन भी है जो आज 100 से अधिक संस्थानों में लगी हुई है। यहां जो सरकार के अधिकारी हैं क्या उन्होंने टेंडर लगाने से पहले इसकी पूरी जांच-पड़ताल की? ...(व्यवधान) एम्स में भी यह मशीन लगी है। दिल्ली के राजीव गांधी एडवांस्ड कैंसर हॉस्पिटल में मंत्रा की तीन मशीनें लगी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पूरी जानकारी दी जाए। अवस्थी जी हमारे साथ क्यों चर्चा कर रहे हैं? सभापति महोदय के माध्यम से मैं यह जानकारी इसलिए लेना चाहता हूं। राजीव गांधी रिसर्च हॉस्पिटल, दिल्ली; नोबल हॉस्पिटल, पुणे (महाराष्ट्र); ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद; सर्वोदय हॉस्पिटल, फरीदाबाद; और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू), लखनऊ इन सभी जगहों पर ये मशीनें लगी हैं। अब तो 100 से ज्यादा मशीनें दूसरे देशों में भी लग चुकी हैं।

28.03.2026/1455/AT/HK /02

मैं इस रोबोटिक मशीन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इस कर्ज में डूबी हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए 28 करोड़ रुपये खर्च करना उचित है? यानी हिमाचल प्रदेश मे सर्जरी पर कितना खर्च होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, क्या टीम ने इस पर कोई जानकारी ली है? कोई जानकारी नहीं ली गई है।

यह कह रहे है कि दो मशीने लग गई है और तीन और लगाएंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितनी कंपनियों ने इसमें भाग लिया। क्या मंत्रा ने भाग लिया या नहीं? क्या इंडिया मेड ने भाग लिया या नहीं? अगर नहीं तो एक ही कंपनी को सिंगल टेंडर क्यों दिया गया? मैं आपके माधयम से यह जानकी लेना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अगर यह काम कर रही है तो उसकी जवाबदेही भी होगी और वह जवाबदेही सरकार के माध्यम से सदन में रखी जानी चाहिए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो रोबोटिक मशीनें लग रही है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, मशीन कॉस्ट और सर्जरी कॉस्ट कितनी है? आप मेरे साथ बहस मत कीजिये। आप मेडिकल कॉलेज में जाकर पता कीजिए कि यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी या गायनेकोलॉजी की सर्जरी पर कितना खर्च आ रहा है। आप लोग तो खर्चा वहन कर सकते हैं। आप डेढ़ लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। लेकिन इस योजना में न हिमकेयर कार्ड चलता है, न आयुष्मान कार्ड और न ही बीपीएल परिवारों को इसका लाभ मिलता है।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

28.03.2026/1500/केएस/वाईके/1

श्री विपिन सिंह परमार जारी --

यह सर्जरी चंद अमीर लोगों के लिए है। मैं विरोध नहीं करता परंतु तथ्यों पर बात करने की ज़रूरत है।

सभापति महोदय, मैं यहां पर एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) सस्ती नहीं आप 28 करोड़ की जगह और महंगी लगा दें परंतु हमें टेंडर प्रक्रिया की जानकारी तो दे दो। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम जानकारी चाहते हैं कि कितनी कम्पनियों ने पार्टिसिपेट किया? ठीक है, 28 करोड़ रुपये की बढ़िया मशीन है, ड्यूरेबल है। एक सर्जरी के उसमें अढाई लाख रुपये खर्च आते हैं लेकिन मंत्रा में कितने आते हैं? सभापति महोदय, मैं डिस्कशन मांगूगा क्योंकि अगर वे मशीनें अब साथ लगते देशों में भी जा सकती हैं तो हिंदुस्तान में यहां पर क्यों काम नहीं कर सकतीं?

सभापति महोदय, मैने आपके माध्यम से दवाइयों का ज़िक्र किया। जो हमारा ड्रग का महकमा है वह बद्दी-बरोटीवाला और नालागढ़ में बैठता है। उनकी जिम्मेवारी तो तय करिए कि वे क्या करते हैं? क्या वे प्राइम लोकेशन के लिए ही प्रयास करते हैं या जो दवाइयों के लगभग 2 हजार टेंडर फेल हो गए, ऐसी दवाई बनाने वाली कम्पनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करते हैं? रिशफलिंग कीजिए या उनको कहीं और जगह भेजिए। मैं यह नहीं कहता कि जो लगे हैं वे ठीक नहीं हैं परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि सनसनी कैसे फैलाई जाती है? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर हिमकेयर कार्ड में गड़बड़ी हुई है तो सीटिंग जज से इंक्वायरी करवाइए और करवानी भी चाहिए। वह डॉक्टर कौन है जिसने मार्क करने के बाद गायनेकोलॉजी या ओ0बी0जी0 डिपार्टमैंट का जिक्र किया है और अगर यह मैन मेड है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो आजकल हैल्थ के बारे में सरकार को ज्यादा ज्ञान ना होने के कारण अपना स्थान मजबूत बनाने के लिए आधी-अधूरी जानकारी दे रहा है? मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। हमारे पास कम्पलेंट पहुंची है। यह कम्पलेट है 'Complaint regarding overcharging and unauthorized supplier by Verma Health Care.' यहां पर हमारे हैल्थ के अधिकारी भी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से और सरकार के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है, क्यों ओवर चार्जिंग हो रही है और क्यों क्वालिटी का ध्यान

28.03.2026/1500/केएस/वाईके/2

नहीं रखा जा रहा है तथा क्यों गरीब की जेब को काटा जा रहा है? सभापति महोदय, मैं ये सारे डॉक्युमेंट्स यहां पर माननीय सदन में रख दूंगा। मुझे जो विषय यहां पर रखना था, मैंने रख दिया। एन0एच0एम0 के बारे में भी कहना चाहूंगा कि 5000 करोड़ रुपये आते हैं। हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है कि आपका एन0एच0एम0 डिपार्टमैंट ठीक काम नहीं कर रहा है। मुख्य मंत्री जी ने तो घोषणा कर दी कि मैं स्टाफ नर्सिज, टैक्निशियन और आशा वर्कर की पहली अप्रैल से तनख्वाह बढ़ा दूंगा परंतु ऑडिट में यह कहा गया है कि विभाग कायदे से काम नहीं कर रहा है और हाई कोर्ट ने इंटरवीन करने के बाद भारत सरकार को यह कहा है कि इसकी जानकारी और छानबीन की जाए। यह मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और मंत्री महोदय फ्रैश रिपोर्ट मांगी जाए । आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। टांडा मैडिकल कॉलेज के बारे में हमारे साथी ने बड़े विस्तार से बात रखी है। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हालत सुधारिए। प्रिंसिपल भी एडहॉक पर हैं और यहां पर तो चीफ सैक्रेटरी और डी0जी0पी0 भी एडहॉक पर हैं। टांडा में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी व एक्सरे की मशीनें डिफंक्ट हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी --

28.03.2026/1505/av/yk/1

श्री विपिन सिंह परमार------जारी

इसलिए वहां पर फ्लोरोस्कोपिक एक्स-रे के माध्यम से मरीजों के एक्स-रे हो रहे हैं। इसलिए वहां मशीन्ज को बदला जाए। यहां पर जैसे कहा गया है कि लिफ्ट खराब है तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां एक नहीं अपितु मैक्सिमम लिफ्ट्स खराब पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय, माफ कीजिए परंतु मैंने 'अध्यक्ष' कह दिया और क्या पता यह सत्य हो जाए। ...(व्यवधान) मेरे तो पड़ोसी हैं और हम इनके शुभ-चिन्तक हैं। हमारे जैसे आप (श्री मुकेश अग्निहोत्री) विश्वविद्यालय के साथी हैं, वैसे ही सभापति महोदय भी हमारे

विश्वविद्यालय के साथ हैं। ये बहुत कर्मठ और योग्य विधायक हैं और हमेशा ही जनता की समस्याओं को उठाते रहते हैं। हम तो इनको शुभ-कामनाएं देना चाहते हैं। ...(व्यवधान) अच्छा आपके (श्री राकेश कालिया) लीडर भी ये ही हैं? ...(व्यवधान) फिर तो अच्छी बात है। ...(व्यवधान) नहीं, मुख्य मंत्री जी तो हमारे सदन के नेता है इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अभी केवल यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के तमाम स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए मैंने जो-जो सुझाव दिए, आप उन पर काम करें। आप बहुत ऊंची उड़ान भरने की बजाय धरातल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के साथ-साथ टैक्नीशियन्ज व दूसरे रिक्त पदों को भरने का काम करें। हम यहां पर प्रदेश हित में अवश्य बातें करेंगे और हिमकेयर का कुल आकार 1100 करोड़ रुपये का है। जिसमें से भाजपा ने 444 करोड़ रुपये दिए और वर्तमान सरकार ने 700 करोड़ रुपये दिए हैं। यहां पर जैसे कहा जा रहा है कि इसमें 100 करोड़ रुपये का घपला हो गया तो यह तथ्यहीन है तथा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहां पर जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इसमें ओवरी के ऑपरेशन में पुरुषों के नाम लिखे गए हैं तो इस बारे में जांच करवाइए। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2026/1505/av/yk/2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुख राम चौधरी : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या : 9 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में आए कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं यहां पर थोड़ा सिविल होस्पिटल पांवटा साहिब का वर्णन करना चाहता हूं। वर्तमान में इस होस्पिटल के माध्यम से जिला सिरमौर की आधी आबादी का उपचार होता है। वहां पर पांवटा साहिब और शिलाई विधान सभा क्षेत्र के शत-प्रतिशत, नाहन विधान सभा क्षेत्र के 35 प्रतिशत और रेणुका विधान सभा क्षेत्र के 15 प्रतिशत एरिया के लोगों का उपचार किया

जा रहा है। इस होस्पिटल में प्रतिदिन 1000 के करीब ओ0पी0डी0 होती हैं। वहां हमारे साथ उत्तराखण्ड की सीमा भी लगती है इसलिए कुछ नज़दीकी क्षेत्र के लोग भी पांवटा साहिब सिविल होस्पिटल में ही उपचार हेतु आते हैं। वहां पर हरियाणा राज्य की सीमा भी बिल्कुल साथ लगती है। अतः वहां के लोग भी वहीं पर ट्रीटमैंट के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त पांवटा साहिब एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल और स्टोन क्रशर्ज एरिया है। वहां पर हर दूसरे-चौथे दिन कोई-न-कोई दुर्घटना घटती रहती है और लोग अपना उपचार करवाने इस होस्पिटल में आते रहते हैं। आज हालत यह है कि वहां पर हमारा ऑपरेशन थियेटर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। जब किसी दुर्घटना के कारण जख्मी मरीज होस्पिटल में लाया जाता है तो उसको रैफर कर दिया दिया जाता है यानी वह सिविल होस्पिटल अब एक रैफरल होस्पिटल बन गया है।

मेरा आदरणीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से निवेदन है कि वहां पर टैक्नीशियन तथा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की मशीन नहीं है। मैं यहां पर बड़ी सुविधाओं की बात नहीं करूंगा। परंतु उस एरिया में हर तीसरे-चौथे दिन एक दुर्घटना होती है।

टी सी द्वारा जारी

28.03.2025/1510/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री सुख राम चौधरी... जारी

यदि शिलाई में कोई एक्सीडेंट होता है तो मरीज डेढ़-दो घंटे में पावंटा पहुंचता है। वहां उसे केवल फर्स्ट एड दी जाती है और फिर एम्बुलेंस के माध्यम से नाहन अस्पताल भेजा जाता है। उसके बाद नाहन से उसे रैफर करके पी0जी0आई0 भेज दिया जाता है। जब कोई मरीज गंभीर होता है तो उसकी प्राथमिकता निकटतम स्थान पर उपचार प्राप्त करने की होती है। यदि मरीज को वहीं भर्ती कर लिया जाए तो वह उसके लिए सुविधाजनक होगा लेकिन आज स्थिति यह है कि आयुष्मान कार्ड की अप्रूवल समय पर नहीं मिलती। यदि उत्तराखंड में कोई मरीज भर्ती हो जाए तो हिमाचल प्रदेश के मरीज का आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं किया जाता, हरियाणा में भी इनकार कर देते हैं। एक मरीज पावंटा से नाहन चलेगा और नाहन भी रैफरल हॉस्पिटल है। वह मेडिकल कॉलेज है लेकिन वहां पर

सुविधाओं की कमी है। उस मरीज को आई0जी0एम0सी0 शिमला आना पड़ता है या चंडीगढ़ जाना पड़ता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो आयुष्मान कार्ड के मानक पूरे करते हैं उन्हें उत्तराखंड और हरियाणा में भी मान्यता दी जाए ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।

कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमें स्वयं अस्पताल जाना पड़ता है। हाल ही में शिलाई में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लड़कों की मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए। उन्हें रात में देहरादून ले जाना पड़ा लेकिन वहां उपचार से मना कर दिया गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान के कई केस लंबित थे और उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अप्रूवल नहीं देती इसलिए हम इनकी ट्रीटमैंट उस पैसे से नहीं कर सकते । इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे मरीजों के मामलों में समयबद्ध तरीके से अप्रूवल दी जाए ताकि उन्हें सही उपचार मिल सके। पावंटा का ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा है और उसकी मरम्मत नहीं हो रही है। उस पर काफी पैसा खर्च हुआ है। जिस एजेंसी के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसकी पेमेंट नहीं हो रही है इसलिए वे उसकी रिपेयर नहीं कर रहे हैं। 15 स्टाफ नर्स के पद खाली पड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम-

से-कम एक अस्पताल तो ऐसा होना चाहिए जो जिला सिरमौर की आधी आबादी को सेवाएं दे सके। एक अस्पताल को इस स्तर तक विकसित किया जाए कि वहां पर लोगों का उपचार संभव हो सके। ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। कभी एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं होता, कभी मशीन नहीं होती और कभी टेक्नीशियन नहीं होता। मेरा निवेदन है कि वहां एनेस्थीसिया की मशीन स्थापित की जाए ताकि ऑपरेशन थिएटर वर्किंग पोजीशन में आ सके और लोगों को उपचार मिल सके। मंत्री महोदय, हम आपसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजपुरा में एक सी0एच0सी0 है, वहां एक्स-रे मशीन लगाई गई थी लेकिन आज तक वह चालू नहीं हो सकी क्योंकि वहां एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं है। वह मशीन पड़ी-पड़ी ही खराब हो गई है और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वहां एक एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाए। जहां तक हिमकेयर योजना की बात है,

एन0एस0 द्वारा ..... जारी

28-3-2026/1515/एन0एस0-ए0जी0/1

श्री सुख राम चौधरी-----जारी

हिमकेयर एक ऐसी स्कीम हिमाचल प्रदेश में चली थी जिससे गरीब लोगों को इलाज के लिए बहुत राहत मिलती थी। हिमकेयर योजना के माध्यम से 11 लाख लोगों का ट्रीटमैंट हुआ है। यह छोटी फिगर नहीं है। ठीक है, आपको लगता होगा कि इसमें घपला हुआ है। जिस भी हॉस्पिटल ने घपला किया है आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाइए। वर्तमान सरकार गरीब लोगों का शोषण क्यों कर रही है? आप बहाना बना रहे हैं कि उस अस्पताल में ट्रीटमैंट के दौरान एक्सपायरी डेट की दवाई दे दी गई। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह फॉल्ट उस इंस्टीच्यूट का है बल्कि उस स्कीम का नहीं है। 11 लाख लोगों की ट्रीटमैंट इस मद के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हो, यह बहुत बड़ी सुविधा हिमाचल प्रदेश के आम व्यक्ति व गरीब व्यक्ति को दी गई थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने यह सुविधा बंद कर दी। आपने इस स्कीम के तहत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज बंद कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में समय नहीं है। वहां मरीजों को 3-4 महीने की डेट मिलती है और तब तक मरीज ऐसे ही मर जाए जबको उसका नम्बर आना है। हरेक व्यक्ति को समय से ट्रीटमैंट मिलना चाहिए। जब मरीज ने चैक करवाया तो उसकी बीमारी का ट्रीटमैंट समय पर होना चाहिए। अब अगर अल्ट्रासाउंड की डेट 3 महीने की देंगे तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए कौन इंतजार करेगा? इसलिए यह स्कीम बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम में अगर कोई कमियां रही हैं तो उनको सरकार द्वारा दूर करके चलाने का इंतजाम करना चाहिए। परन्तु वर्तमान सरकार की नियत ठीक नहीं है और हिमाचल प्रदेश के लोगों का ट्रीटमैंट नहीं करना चाहती है। इसलिए इस स्कीम को न बंद किया और न ही चालू रखा है। पांवटा साहिब के अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति एडमिट हो जाए तो उसको हिमकेयर के तहत क्या इलाज देंगे क्योंकि वहां पर ऑपरेशन थियेटर ही नहीं है। नाहन अस्पताल में भी प्रौपर तरीके से ऑपरेशन नहीं होता है। मरीज कहां जाएगा? पी0जी0आई0, चंडीगढ़ में 6 महीने की डेट मिलती है। आई0जी0एम0सी0,

शिमला में 3 महीने बाद की डेट मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी हैल्थ व्यवस्था कहां है? छोटे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमैंट करवा लेते थे और ठीक होकर घर चले जाते थे। इसलिए यह स्कीम राजनीति की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। इस स्कीम को जन-हित में चालू रखना चाहिए। मैं सरकार से यही आग्रह व

28-3-2026/1515/एन0एस0-ए0जी0/2

निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि कहना बहुत आसान है। आज ट्रीटमैंट इतना महंगा है कि अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में एडमिट हो जाओ और अगर आई0सी0यू0 में एडमिट हों तो एक दिन का बिल 1 लाख रुपये का बनता है। गरीब व्यक्ति को अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, दुधारू पशु बेचना पड़ता है, जमीन गिरवी रखनी पड़ती है और पड़ोसी भी पैसे नहीं देते हैं तथा रिश्तेदार भी पैसे नहीं देते हैं। लोगों को इस स्कीम से आशा थी और हिमाचल प्रदेश की पूर्व सरकार ने एक महत्वकांक्षी स्कीम प्रदेश के लोगों को दी थी जिससे उनका जीवन बचता था। हिमकेयर योजना से लाखों लोगों का जीवन बचा है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप छोटी-छोटी बातों को छोड़ दीजिए। ...(व्यवधान) वह तो जब निकलेगा तब निकलेगा। कहां निकल गया? 100 करोड़ रुपये की ट्रीटमैंट हुई और आप उसमें 100 करोड़ रुपये का फ्रॉड बता रहे हैं। पूरे हिमाचल का 1100 करोड़ रुपये केवल एक हॉस्पिटल का नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में फ्रॉड बता रहे हैं। आप उनके ऊपर इन्क्वायरी कीजिए और एक्शन लें। आपका क्या काम है? आपने साढ़े तीन वर्षों में क्या किया? आपने कितने लोगों को अंदर किया और कितनी इन्क्वायरियां कीं? आपके साढ़े तीन वर्ष तो कहने में ही निकल गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार का कार्यकाल सिर्फ डेढ़ वर्ष का रह गया है। आपसे हिमाचल प्रदेश के लोग पूछेंगे। आपको हिमकेयर योजना को बंद करने का क्या फल मिलेगा उसको हिमाचल प्रदेश के लोग आपको बताएंगे? आप उस समय का इंतजार कीजिए जिस तरह की व्यवस्था आपने की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और बड़ी लंबी बात नहीं कहना चाहता। एक हॉस्पिटल एक विधान सभा क्षेत्र में अच्छा बनाइए। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कहने से नहीं बन जाता। डॉक्टर आप नहीं देते, टेक्निशियन आपके पास नहीं हैं और आपकी मशीनें धूल चाट रही हैं-------

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

28.03.2026/1520/RKS/AS-1

श्री सुख राम चौधरी जारी.....

वहां पर मशीनें 5-5, 6-6 साल से धूल चाट रही हैं। वहां से X-Ray टेक्निशियन ट्रांसफर होकर चला गया लेकिन उसके स्थान पर आजतक कोई दूसरा टेक्निशियन नहीं आया। यह आपकी सरकार की गंभीरता का परिणाम है। जब आप एक मशीन को संचालित करने के लिए X-Ray टेक्निशियन तैनात नहीं कर सकते तो फिर आप और क्या सुधार करेंगे? यह एक चिंता का विषय है। आप ऑपरेशन थिएटर में एक मशीन स्थापित नहीं कर सकते फिर आप हिमाचल प्रदेश में क्या सुधार करेंगे? आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपने अपनी गारंटियों में भी ऐसा ही किया है। आप इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना का बड़ा जिक्र करते हैं। आपने 28 लाख महिलाओं में से केवल 38 हजार महिलाओं को ही इस योजना का लाभ दिया है और फिर इसकी वाहवाही लूट रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं लोक सभा चुनाव के दौरान आपके साथ था। आप कम-से-कम पांवटा साहिब अस्पताल का एक बार तो दौरा कर दीजिए। आपको साढ़े तीन वर्षों में पांवटा साहिब जाने का समय नहीं मिल रहा है। मैंने आपको वहां जाने के लिए कई बार आग्रह किया लेकिन आप एक बार भी नहीं आए। शायद आपको समय नहीं मिल रहा होगा लेकिन आपको उस अस्पताल की सुध अवश्य लेनी चाहिए। आप इस अस्पताल को रेफरल अस्पताल मत बनाइए। आपने नाहन के अस्पताल को रेफरल अस्पताल बना दिया है...(व्यवधान) मैं सैकड़ों मरीजों के साथ वहां जाता हूं। मैं यहां जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मरीजों को चैक करने के लिए डॉक्टर को एम्बुलेंस में लाना पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि आप यहीं से मरीज को रेफर करवा दो नहीं तो आपका एक घंटा और बर्बाद हो जाएगा। आप इस तरह वास्तविकता से दूर मत जाइए। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप कम-से-कम एक बार पांवटा साहिब अस्पताल का दौरा अवश्य कीजिए ताकि आपको वास्तविक स्थिति का पता चल सके। वहां पर जो एक्स-रे मशीन स्थापित की गई है वह सौ एक्स-रे करने के बाद गर्म हो जाती है। उसके बाद मरीजों को एक्स-रे के लिए अगले दिन बुलाना पड़ता है। आप वहां पर नई

मशीन स्थापित करवाइए ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मैं न तो एम्स अस्पताल की बात कर रहा हूं न आई0जी0एम0सी0, शिमला की बात कर रहा हूं; मैं तो उन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की बात कर रहा हूं जिन्हें आपने घोषित किया है। पांवटा साहिब अस्पताल अढ़ाई

28.03.2026/1520/RKS/AS-2

विधान सभा क्षेत्रों के लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। जब इस स्वास्थ्य संस्थान की हालत ऐसी है तो जिला सिरमौर के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति क्या होगी इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। हमारे 70 प्रतिशत लोग देहरादून अस्पताल में अपना उपचार करवाने जाते हैं। वहां साथ में यमुना नगर का अस्पताल भी है। पांवटा साहिब होस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट भी खराब पड़ा है, आप उसे भी ठीक करवा दीजिए। उस प्लांट पर काफी राशि खर्च की गई है लेकिन वर्तमान में वह प्लांट धूल चाट रहा है। इसलिए वहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी तो आप सुध ले लीजिए क्योंकि नई सुविधाएं देना तो दूर की बात है।

सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्याः 9 पर बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

28.03.2026/1520/RKS/AS-3

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार : सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्याः 9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। यहां पर सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की जा रही थीं। स्वास्थ्य विभाग में क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं और आने वाले समय में क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर माननीय विधायकों ने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से काफी विस्तार से अपनी-अपनी बात रखी है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.03.2025/1525/बी.एस./ए.एस.-1

लेकिन सभापति महोदय मैं अक्सर देखता हूं कि जब भी प्रदेश के मुख्य मंत्री इस माननीय सदन से बोलते हैं और मुख्य मंत्री जी का मण्डी का जब भी प्रवास होता है तो उनकी ओर से एक बात बार-बार कहीं जाती है की मंडी के मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री रहने के बावजूद भी नेर चौक मेडिकल कॉलेज में एम0आर0आई0 की मशीन नहीं लगा पाए लेकिन मैं आपको आज हाउस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस एम0आर0आई0 का जिक्र यहां से अनेकों बार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस एम0आर0आई0 मशीन के लिए आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने ही पैसों का प्रोविजन किया था। इसका पहली बार 17 अप्रैल, 2020 को टेंडर हुआ लेकिन किन्हीं कारणों से टेंडर कैंसिल हो गया। उसके बाद यह टेंडर वर्ष 2021 में फिर से हुआ और टेंडर जब कंप्लीट हो गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेंडर की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई और जिस कंपनी को टेंडर दिया जा रहा था उसने सरकार से यह कमिट किया था कि हम लगभग नवम्बर या दिसम्बर माह तक लोगों को एम0आर0आई0 की सुविधा आपके मेडिकल कॉलेज नेर चौक में दे देंगे लेकिन आपने देखा होगा कि नई सरकार बनी, सरकार बनने के बाद यह व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार जब आई तो इसी सरकार ने उस टेंडर को रद्द कर दिया। मैं आखिरकार पूछना चाहता हूं कि अगर उस टेंडर को कैंसिल नहीं किया होता तो वर्ष 2022 में ही मेडिकल कॉलेज नेरचौक में लोगों को एम0आर0आई0 की सुविधा मिल जाती आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बताना चाहता हूं अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश में वर्तमान सरकार है जिसने उस टेंडर को उस वक्त कैंसिल किया था।

उसके साथ-साथ सभापति महोदय हमारे मेडिकल कॉलेज नेर चौक में हमें एक नहीं अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर लम्बे से तक एम0एस0 की पोस्ट नहीं भरी गई। एम0एस0 नहीं लगाया गया लेकिन वर्तमान में अभी एम0एस0 वहां पर लगाया भी गया तो मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि

28.03.2025/1525/बी.एस./ए.एस.-2

एम0एस0 लग गया परंतु एम0एस0 की जो शक्तियां है वह एम0एस0 के पास नहीं है। एम0एस0 को एडिशनल डायरेक्टर को पूछ करके ही सारे काम वहां पर करने होते हैं। वहां पर एम0एस0 की सारी शक्तियां एडिशनल डायरेक्टर को दी गई हैं। अगर मेडिकल कॉलेज में कोई भी छोटे से छोटा काम करना है, माननीय मंत्री जी तो एडिशनल डायरेक्टर को ही पूछ करके करना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जब आपने वहां पर एम0एस0 लगा दिया है तो उसको उसकी शक्तियां भी दी जाए और सबसे बड़ी बात है कि उसको स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए ताकि मेडिकल कॉलेज के वेलफेयर के लिए, मेडिकल कॉलेज के हित में जो भी निर्णय लेने हों उन्हें वे आसानी से ले सकें और एडिशनल डायरेक्टर का जो भी काम है वह उन कामों को करें और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अपने कामों को करें। यह मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा। उसके साथ-साथ जहां तक मैं मेडिकल कॉलेज नेचर की बात करूं तो सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज नेर चौक हमारा 500 बेडिड हॉस्पिटल है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 500 बेडिड जो हॉस्पिटल हमारा मेडिकल कॉलेज नेर चौक है वहां पर्याप्त डॉक्टर नहीं है..

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

28.03.2026/1530/DT/DC-1

श्री विनोद कुमार जारी...

सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज नेरचौक में हमारा 500 बेडिड हॉस्पिटल है। ये 500 बेडिड हॉस्पिटल तो है पर यहां पर पर्याप्त डाक्टर्ज नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। वहां पर अधिक ओपीडी होने के कारण, जो यह 500 बेडिड मेडिकल कॉलेज है उसे 800 बेडिड बना दिया गया है क्योंकि वहां पर उपचार करने वालों का रश बहुत ज्यादा है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब 500 बेडिड हस्पताल में ही विभाग के पास न डॉक्टर्ज और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो वहां पर जो

सीमित स्टॉफ है वह 800 रोगियों का उपचार कैसे कर पायेगा? उस मेडिकल कॉलेज का नाम तो लोगों ने अब रेफरल अस्पताल रख दिया है क्योंकि वहां पर स्टाफ की कमी और रोगियों को उचित सेवाएं नहीं मिल पाती। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जिस तरह से सरकार ने उस मेडिकल कॉलेज में बेड की क्षमता को 500 से 800 करने की अनुमति दी है, वहां पर डाक्टर्ज की संख्या भी बढ़ा दीजिए क्योंकि लोगों को वहां पर डाक्टर्ज भी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ भी चाहिए। एक बार नहीं अनेकों बार मेडिकल कॉलेज नेरचौक के प्रिंसिपल महोदय के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के साथ पत्रचार किया गया। लकिन उस पत्राचार का कोई भी उत्तर उनको नहीं दिया गया। उन्होंने अपने पत्र में सरकार से अतिरिक्त डाक्टर्ज और पैरा मेडिकल स्टॉफ की पोस्टस देने की बात कही है। क्योंकि 500 बेड वाली क्षमता के हस्पताल में 800 बेड्स का प्रवधान किया गया है, तो उन्होंने आउटसोर्स के माध्यम से भी और स्टाफ वहां पर रखने का आग्रह किया है। इसलिए सभापति महोदय आपके माध्यम से मेरा स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि वहां पर चाहे डाक्टर्ज या पैरामेडिकल के पदों को भरने या अतिरक्ति संख्या तैनात करने की बात हो या आउटसोर्स में पद भरने की बात हो, उसको सुनिश्चित करवाएं ताकि जो लोग उपचार हेतु इस हस्पताल में जाते हैं उनको वहां पर डाक्टर्ज और पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवाएं मिल सके।

सभापति महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा अपना पहला बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया था उसमें कहा था कि हम हर मेडिकल कॉलेज में PAT Scan सुविधा शुरू करेंगे। लेकिन खेद की बात है कि एक भी मेडिकल कॉलेज

में ये सुविधा शुरू नहीं की गई है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि यह सेवा कब आरम्भ होगी? सभापति महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में लैब टेक्नीशियन की कमी है। जब हस्पताल की लैब में लैब टेक्नीशियान्ज ही नहीं होंगे तो रोगियों के टेस्ट कैसे होंगे-उनको तो प्राइवेट लैब में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर 24x7 टेस्ट करवाने की सुविधा उपलब्ध हो।

इसके अतिरिक्त नेरचौक के प्रधानाचार्य की ओर से माननीय स्वास्थ मंत्री जी को एक और पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने स्टॉफ क्वाटर्ज की रिपेयर के लिए बजट उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है। लेकिन आज तक सरकार ने एक भी पैसा उन क्वाटरर्ज की रिपेयर के लिए नहीं दिया। स्वाभाविक है कि अगर सरकार एक साल पैसा नहीं देती और दूसरे साल पैसा नहीं देती, जब सरकार ने आज तक कोई पैसा नहीं दिया यही कारण है कि आज वे क्वाटर्ज गिरने की कगार में हैं। मेडिकल कॉलेज नेरचौक की ओर से सरकार को जो भी क्वाटर्ज की रिपेयर और मेंटिनेंस के लिए धनराशि की मांग की गई है उस मांग को सराकर पूरा करे, यह मेरा अनुरोध रहेगा।

जब माननीय श्री जय राम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उस वक्त वैश्विक महामारी कोरोना का एक भयंकर दौर पूरे संसार में आया जिससे हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। उस समय मेडिकल कॉलेज नेरचौक में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया था। उसके लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। कोरोना काल में उसका बहुत लाभ भी मिला है

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

28.03.2026/1535/डी.सी.-एन.जी./1

श्री विनोद कुमार..... जारी

लेकिन आज की तारीख में वह खाली है। वहां पर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, तो मेरा सरकार और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से निवेदन रहेगा कि वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी कार्य संभव हो, उसे उस एरिया के अंदर शुरू किया जाए।

सभापति महोदय, हमारे मैडिकल कॉलेज नेरचौक में कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। उसका उद्घाटन भी हमारी सरकार के समय हो गया था। लेकिन तीन साल

चार महीने बीत जाने के बावजूद भी उस हॉस्पिटल को अभी तक शुरू नहीं किया जा रहा है। लोगों को अभी भी या तो एम्स व पी0जी0आई0 के चक्कर काटने पड़ रहे हैं या फिर आई0जी0एम0सी0 शिमला जाना पड़ रहा है। मेरा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से निवेदन रहेगा कि जब वह हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और सारी व्यवस्थाएं भी वहां पर ठीक हो गई हैं, तो कृपया उस हॉस्पिटल को भी शुरू करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, इसके अलावा हमारा सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में डॉक्टरों के रेजिडेंस का काम हमारी सरकार के समय शुरू हुआ था। लगभग 70 प्रतिशत काम हमारी सरकार के समय पूरा भी हो गया था और उसके लिए श्री जय राम ठाकुर जी ने पैसे भी दे दिए थे। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार आने के बाद उसके कार्य को पूरा करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। स्थिति यह हो चुकी है कि वहां पर जो खिड़कियां-दरवाजे लगाए गए थे, वे भी अब सड़ने-गलने की कगार पर पहुंच गए हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि उसके लिए भी थोड़ा पैसा देने की कृपा करें ताकि वह कार्य पूरा हो सके।

28.03.2026/1535/डी.सी.-एन.जी./2

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पी0एच0सी0 कनैड़ है। इसमें लगभग पांच पंचायतों के लोग आते हैं और लगभग 10,000 की आबादी को यह पी0एच0सी0 फीड करती है। लेकिन इस पी0एच0सी0 में जो डॉक्टर है, वह छह दिनों में से केवल दो या तीन दिन ही वहां पर उपस्थित रहता है। क्योंकि कभी उसे किसी दूसरी जगह भेज दिया जाता है, तो कभी किसी और जगह। मेरा निवेदन रहेगा कि जब पांच पंचायतों की जनता उस एक पी0एच0सी0 पर निर्भर है, तो उस डॉक्टर को बार-बार दूसरी जगह न भेजा जाए और उसे वहीं कार्य करने दिया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हमारा सिविल हॉस्पिटल गोहर है। श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने इस सिविल हॉस्पिटल गोहर को 100 बेडिड अस्पताल घोषित किया था। इसकी नोटिफिकेशन भी हो गई थी और स्टाफ भी लगभग नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार आई, इस अस्पताल को डिनोटिफाई कर दिया गया। यह अस्पताल लगभग 50 ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य सेवाएं देता है और उस क्षेत्र की लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी इसी अस्पताल पर निर्भर रहती है। मैंने एक बार नहीं बल्कि लगातार इस अस्पताल के विषय में आपसे निवेदन किया है लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इस अस्पताल को फिर से 100 बेडिड अस्पताल के रूप में बहाल करने के लिए सहयोग किया जाए। इसके अलावा, मैंने यह भी कहा था कि सिविल हॉस्पिटल गोहर में सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था के लिए भी प्रबंध किए जाएं। यहां पर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी बैठी हैं और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूं कि यह विषय हर बार इस माननीय सदन में आता है और इस संबंध में अस्पताल की ओर से भी आपको अनेकों बार लिखा गया है।

28.03.2026/1535/डी.सी.-एन.जी./3

मुझे लगता है कि अब तो हमें इसकी मांग भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह सरकार कुछ नहीं कर सकती और यह स्थिति इसी सरकार ने बनाई है। अगर हम इस माननीय सदन के अंदर कोई बात कर रहे हैं और उसके बाद भी सरकार उस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती है, तो इसका अर्थ यही है कि सरकार उस काम को लेकर गंभीर नहीं है। इसके अलावा, सिविल हॉस्पिटल गोहर में डॉक्टरों के रेजिडेंस भवन के निर्माण के लिए भी धनराशि मांगी थी और इसके लिए आपको एस्टिमेट भी भेजा गया है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए निश्चित रूप से मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि...(व्यवधान)

उप-मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। (अपने स्थान पर बैठे-बैठे बिना अनुमति के कहा)

श्री विनोद कुमार : उप-मुख्य मंत्री जी, नड्डा जी ने जो देना होगा

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

28.03.2026/1540/एच0के0/ए0पी0/-01

श्री विनोद कुमार जारी .....

लेकिन इस सरकार से जो हम अपेक्षा करते हैं, इस व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार से जो हम उम्मीद रखते हैं, हम चाहते हैं यह सरकार वह पूरा कर दें। बाकी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्र में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य विभाग में जितना हिस्सा मिलता है, उससे भी अधिक हिस्सा माननीय नड्डा जी के आशीर्वाद से मिल रहा है, यह बात मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पी0एच0सी0 चौल थी। उसको हमने सी0एच0सी0 बनाया था। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय उस सी0एच0सी0 में स्टाफ भी आ गया था, लेकिन उस सी0एच0सी0 को भी आपकी सरकार द्वारा डीनोटिफाई कर दिया गया है। वह लगभग 32 पंचायतों की एक सी0एच0सी0 थी। मेरा निवेदन रहेगा कि आज से पहले सरकार इन सभी मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं थी लेकिन आज जब हमने यह बात फिर से कही है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार थोड़ी गंभीरता जरूर दिखाए। सभापति महोदय, हिमकेयर योजना को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में तीन बार अलग-अलग स्टेटमेंट दी। एक बार कहा कि 11,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, एक बार कहा कि 1,100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ और एक बार कहा कि 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हिमकेयर योजना के तहत अभी तक कुल खर्चा 1,100 करोड़ रुपये का हुआ है। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने इस योजना को शुरू किया था और हमारी सरकार

ने 444 करोड़ रुपये इस योजना के तहत खर्च किए हैं। जबकि वर्तमान सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपये इस योजना के तहत खर्च किए हैं। अब सरकार कह रही है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि तीन साल चार महीने तक सरकार कहां सोई थी? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन इस हिमकेयर योजना को बंद न करे, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन रहेगा। क्योंकि जब हम अस्पतालों में जाते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि इलाज कैसे करवा रहे

28.03.2026/1540/एच0के0/ए0पी0/-02

हो? कुछ लोग हिमकेयर योजना का जिक्र करते हैं और कुछ लोग आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हैं। लेकिन जब ये सभी योजनाएं नहीं चलती थीं तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग अपनी जमीन बेचकर इलाज करवाते थे। हमारी कुछ बहनें अपना मंगलसूत्र बेचकर, अपने सुहाग को बचाने का प्रयास करती थीं और जिनके पास जमीन या गहने भी नहीं होते थे वे बिना इलाज करवाए ही चले जाते थे। हमने और आपने इस तरह की परिस्थितियां भी देखी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हिमकेयर योजना को बंद न किया जाए क्योंकि यह योजना आम जन से जुड़ी हुई है। यह गरीब व्यक्ति से जुड़ी हुई योजना है। इसके अलावा, हमें अनेक फोन उन बेसहारा लोगों के आते हैं जिनका सहारा बनने का काम माननीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने किया था। मैं बताना चाहता हूं कि सहारा योजना के तहत लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। जिन लोगों ने सहारा योजना के तहत फॉर्म भरे हैं उनके फॉर्म बी0एम0ओ0 ऑफिस से आगे नहीं जा रहे हैं। उन्हें सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि आप एक तो फॉर्म ही न लें और अगर फॉर्म लिए है तो उन्हें बी0एम0ओ0 ऑफिस से आगे न भेजें। मेरा निवेदन रहेगा कि सहारा योजना के तहत जितने भी पेंडिंग फॉर्म हैं उन सभी बेसहारा लोगों की पेंशन लगनी चाहिए, ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा। इस योजना में एक दिक्कत यह भी आ रही है कि जिन लोगों को सहारा योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है। उनसे हर छह महीने के बाद लाइफ सर्टिफिकेट मांगा जाता है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

28.03.2026/1545/AT/ HK/01

श्री विनोद कुमार जारी....

उनसे हर 6 महीने के बाद एक लाइफ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जब यह लाइफ सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वे इसे पंचायत के माध्यम से भेजते हैं। कई बार उन्होंने यह लाइफ सर्टिफिकेट आशा वर्कर बहन के माध्यम से, बी0एम0ओ0 के माध्यम से और कई तो सी0एम0ओ0 के पास भी भेजा। लेकिन उसके बाद भी उनकी पेंशन शुरू नहीं हो रही है और न ही उन्हें मिल रही है। ज्यादा लंबी बात न करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, किशोरी लाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं। वर्ष 2012 से साथ ही रहे है पर बीच में एक बार उनको ब्रेक लगी थी। लेकिन इन्हें भी डॉक्टर को लेकर के दिक्कत आ रही है। और इन्होंने विधान सभा में भी प्रश्न लगाया हुआ था। अगर सरकार में ही ऐसे हाल होंगे तो काम कैसे चलेगा? मेरा निवेदन है कि किशोरी लाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, आप इन्हें जरूर न्याय दें। इन्होंने डॉक्टर से संबंधित जो बात कही है और अपनी पीड़ा यहां व्यक्त की है, उस पर आप ध्यान दें। मुझे पूरा विश्वास है कि किशोरी लाल जी को भी डॉक्टर मिलेगा और आज जिन मुद्दों को लेकर हमने आपसे बात की है उन पर भी आप अब कार्रवाई करेंगे। पहले भले कुछ न हुआ हो, लेकिन अब आप कुछ करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सभापति महोदय, आपने मुझे अपना समय दिया, आपका धन्यवाद।

28.03.2026/1545/AT/ HK/02

सभापति : अब माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 जनक राज : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-9 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात दोहराना चाहूंगा कि मैं इस सदन के माध्यम से हिमाचल के सभी लोगों और महादेव को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि जो कुछ

कहूंगा, सच कहूंगा। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि मैं सत्य पर बात करुंगा तो सब लोग ध्यान से सुने। यह आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा।

सभापति महोदय, ...(व्यवधान) माननीय कृषि मंत्री जी आप वरिष्ठ मंत्री हैं और मैं पहली बार चुनकर आया हूं, ...(व्यवधान) लेकिन यहां मुझे बार-बार कसम खानी पड़ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या बजट पेश करना केवल एक औपचारिकता है या यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है?

सभापति महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बजट पेश करना एक संवैधानिक कर्तव्य है। पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार करता है कि सरकार बजट पेश करेगी और उसमें कुछ लिखा होगा। पहले, जब मैं राजनीति में नहीं था तो मुझे लगता था कि बजट में जो लिखा जाता है,वह सच लिखा गया है। परन्तु जो बातें सरकार ने बजट में और पिछले कुछ बजटों का अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बजट पेश करना सरकार के लिए मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गया है।

सभापति महोदय, मैं बजट 2024-25 की बात करूंगा जिसमें बहुत बड़े-बड़े दावे किए गए हैं हम यह करेंगे, हम वह करेंगे। समय की कमी के कारण मैं केवल एक मुद्दे पर बात करूंगा। हिमाचल में हर साल 10 से 15 लोगों की मृत्यु स्क्रब टाइफस से हो जाती है।

28.03.2026/1545/AT/ HK/03

यह एक छोटी बीमारी है। किसान खेतों में काम करते समय संक्रमित हो जाते हैं और जान गंवा देते हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च यूनिट स्थापित की जाएगी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च यूनिट कहां है?

दूसरी बात, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और कमला नेहरू अस्पताल में लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित करने की बात कही गई थी। आज भी स्थिति यह है कि जब किसी महिला का बच्चा पैदा होने के बाद बीमार हो जाता है जैसे उस बच्चे को पीलिया हो जाता है या वह किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हो जाता है, बच्चा अस्पताल में भर्ती होता है तो मां को बिस्तर तक नहीं मिलता। बच्चे को स्तनपान करवाने के लिए भी कोई निश्चित स्थान उपलब्ध नहीं करवा पाए है। फिर ये लोग कहेंगे कि आपकी सरकार में क्या हुआ?

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

28.03.2026/1550/केएस/वाईके/1

डॉ0 जनक राज जारी ---

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सुधार निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। जब-जब हमें पूछना चाहता हूं कि आपने जब बजट में लिखा, उसके बाद आपने क्या किया? एक कमरा ही तो डेडिकेट करना था, क्यों नहीं कर पाए? ना कोई पैसा लगना था ना कुछ और खर्चा होना था। फिर अगले बजट की अगर हम बात करें, वर्ष 2024-25 में ही इन्होंने प्वाइंट नं0-71 में एक बात कही कि प्रत्येक जिले में सभी टैस्ट सुविधाओं सहित एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हैल्थ लैब की स्थापना की जाएगी लेकिन वह लैब कहां है? प्वाइंट-73 में कहा कि बद्दी-बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणू, पांवटा आदि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत्त कामगारों के लिए गैस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट आरम्भ किया जाएगा लेकिन क्या किया? अगर हां, तो उसके बारे में बताएं। ...(व्यवधान) उप-मुख्य मंत्री जी, आपके पास दूसरा विभाग है। इसके बारे में आप नहीं स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब देंगे। आप वरिष्ठ आदमी हैं, कृपया करके बीच में ना उलझाएं। ...(व्यवधान) मंत्री जी जवाब देंगे और पूछना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। ...(व्यवधान) मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं सरकार से पूछ रहा हूं। मंत्री जी जवाब दे देंगे। फिर प्वाइंट नं0- 74 पर आपने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए हिमकेयर और सहारा योजनाएं आरम्भ कीं इनका लाभ भी जन साधारण तक पहुंचा किंतु एम्पिरिकल डेटा एनालिसिस के बाद कुछ स्ट्रक्चरल

और ऑप्रेशनल समस्याएं उजागर हुईं मैं जिनके सुधार की घोषणा करता हूं और इस वर्ष कह रहे हैं कि हम उनको बंद करेंगे। वर्ष 2025-26 के बजट में आपने कहा कि 69 केंद्रों पर डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पांगी, भरमौर, आनी या करसोग में यह सुविधा दी? फिर आपने वर्ष 2025-26 के बजट में प्वाइंट नं0-11 में कहा कि घवांडल, चुवाड़ी, भोरंज, नदौन, तियारा जयसिंहपुर, पद्धर, धर्मपुर, जुन्गा, हरोली और अम्ब में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना की जाएगी। मैं सम्बन्धित विधायकों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके इन स्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट हैं? ये पिछले वर्ष की बातें हो रही हैं। सभापति महोदय, फिर इन्होंने कहा कि हमीरपुर, बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी और शिमला में 17 न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन यूनिट्स स्थापित करेंगे। बाकियों का तो मुझे मालूम नहीं लेकिन मेरे

28.03.2026/1550/केएस/वाईके/2

जिला में नहीं है। फिर इन्होने पिछले बजट में कहा था, यह लिखित है, कोई बोली हुई बात नहीं है कि अगले तीन महीने में आई0जी0एम0सी0 में पैट-स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। क्या आज भी यह सुविधा उपलब्ध हो पाई है जबकि एक साल से ज्यादा का समय हो गया है? अगर सरकार बजट में लिखी हुई बात को पूरा नहीं करेगी तो कैसे विश्वास करें? उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए 25 एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। कहां हैं? सभापति महोदय, राजनीति में एक तरीका होता है कि पहले किसी योजना की छवि खराब करो और फिर उसको बंद करो। यह सरकार की राजनीति का मॉडल है। यह मॉडल आज हिमकेयर योजना के साथ कर रहे हैं। मैं आज सदन के माध्यम से पूरे हिमाचल को बताना चाहूंगा, उस वक्त मैं तो सदन में नहीं था, मैं तो एम0बी0बी0एस0 कर रहा था परंतु 23 दिसम्बर, 2004 को इसी विधान सभा में महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी ने यहां पर एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने हैल्थ केयर पर कहा था कि 'I suggest a unique insurance model for Himachal Pradesh' यह बड़ा लम्बा पैरा है जिसको पढ़ने में समय लगेगा। वर्ष 2004 के बाद वर्ष 2018 में जब श्री जय राम जी ने हिमकेयर योजना की शुरुआत की, हमने सरकार से कहा, आज भी हम सरकार से कह रहे हैं कि क्यों केवल

आप कुछ लोगों को हिमकेयर योजना का लाभ दे रहे हैं? क्यों ना पूरे हिमाचल के प्रत्येक व्यक्ति को वह चाहे कर्मचारी है या बिजनैस मैन है, सभी को इंश्योरेंस मॉडल के अंदर कवर कर दो।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

28.03.2026/1555/av/yk/1

डॉ0 जनक राज------जारी

आप एक प्रीमियम निश्चित कर दीजिए, जो उस प्रीमियम को दे सकते हैं वे दें और जो नहीं दे सकते उनका आप मुफ्त उपचार कीजिए। प्रति वर्ष अरबों रुपये के मेडिकल रिम्बर्समैंट बिल बनते हैं और उनमें से पता नहीं कितने सच्चे या झूठे होते हैं, आज मेरे इस वक्तव्य को सुनकर इस बारे में सभी डॉक्टर्ज सोच रहे होंगे।

कल यहां पर एक बात का भ्रामक तरीके से प्रचार किया गया कि बच्चेदानी के ऑपरेशन में मर्दों के नाम लिख दिए गए। यह एक बहुत ही शर्म की बात है और एक डॉक्टर होने के नाते यह केवल मेरे लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक उस डॉक्टर और संस्थान के लिए शर्म की बात है, अगर किसी संस्थान में ऐसा हुआ है। जब मैंने इस बारे में जानकारी जुटाई तो चार मामले जिनका जिक्र मेरे से पूर्व वक्ता कर चुके हैं। सभापति महोदय, अगर आप चाहो तो मैं उस केस की पूरी डिटेल सभा पटल पर रख सकता हूं। वास्तव में होता क्या है, अब मैं प्रैक्टिकल होकर बात करने जा रहा हूं, एक डॉक्टर या राजनेता के नाते नहीं करने जा रहा। हिमकेयर योजना और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भिन्न-भिन्न बीमारियों के पैकेज बनाए गए हैं। लेकिन कौन-सा मरीज किस बीमारी के साथ आएगा, यह किसी को मालूम नहीं होता। इसके अंतर्गत 4 हजार प्रमुख बीमारियों को चिन्हित किया गया है जो कॉमन होती हैं। परंतु कई बार कोई मरीज रेयर बीमारियों के कॉम्बीनेशन के साथ भी आ जाता है। इसमें एक मरीज श्री बुद्धि सिंह, पुत्र श्री रत्न दास, गांव व डाकघर बंजार, जिला कुल्लू है। यह सन् 2016 से राइट एंटीरियर टॉंसिलर पिल्लर के कैंसर का ट्रीटमैंट ले रहा था। कोई मरीज जब किसी गम्भीर बीमारी के साथ आता है तो डॉक्टर सोचता है कि यह

तो किसी योजना के तहत फिट नहीं हो रहा है यानी इस फलां बीमारी के लिए तो कोई पैकेज एडवाइज्ड नहीं है, अब क्या किया जाए। इसकी मदद करनी चाहिए, यह एक गरीब व्यक्ति है। फिर डिस्कस होता है कि इसको कौन-सी कीमो लगनी चाहिए या मरीज किस पैकेज में फिट हो रहा तो उस बारे में विचार-विमर्श होता है कि इसको फलां-फलां पैकेज में फिट कर देते हैं। उसको इस प्रकार से किसी पैकेज में फिट करके उस मरीज को 12000 रुपये में ट्रीटमैंट दे दिया। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह भ्रष्टाचार

28.03.2026/1555/av/yk/2

है? ...(व्यवधान) मेरे पास पूरी डिटेल है और केवल एक केस की ही नहीं अपितु चारों केसिज की हैं। ...(व्यवधान) देखिए, मेरी एक बात सुनिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, कोई भी सरकार जनता को सुविधा देने के लिए कार्य करती है। कोई भी सरकार जब किसी योजना को लाँच करती है तो मैं कहना चाहता हूं क्योंकि यहां पर सभी वरिष्ठ राजनेता और अधिकारी बैठे हैं। सरकार की कोई भी योजना अगर 80 प्रतिशत टारगेट को अचीव कर लेती है तो सरकार उसको सफल मानती है और यह पॉलिसी डाक्यूमैंट है। अगर हिमकेयर योजना के तहत 11 लाख लोगों को उपचार मिला है और किसी होस्पिटल या डॉक्टर ने दो-चार मरीजों को अगर इस प्रकार की एडजस्टमैंट करके ट्रीटमैंट दिया है तो वह कोई अपराध नहीं माना जाएगा। यहां पर इस बारे में जो कल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था मैं भी उस बात का समर्थन करता हूं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि विजिलेंस तो बायस्ड है, आप थर्ड पार्टी से जांच करवाइए। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाइए। अगर यह सरकार सच्ची है या हमने भ्रष्टचार किया है, विशेष तौर पर अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो मैं पूरे हिमाचल प्रदेश को साक्षी मानकर कहता हूं कि आप मेरी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवाइए। किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हिमाचल प्रदेश प्रोक्योरमैंट सैल की स्थापना करने की पॉलिसी बनाने की दिशा में आगे बढ़ी थी। वर्तमान सरकार ने वह प्रोक्योरमैंट सैल बना दिया और उस सैल के बारे में

दिनांक 6 अगस्त, 2020 की एक नोटिफिकेशन है कि हिमाचल सरकार ने मेडिकल कॉलेज में प्रोक्योरमैंट के लिए एक पॉलिसी निर्धारित की थी जिसमें कहा गया कि इसमें क्या-क्या एस0ओ0पीज0 रहेंगे। इसमें सबसे पहले यह कहा गया है कि स्टेट रेट कॉंट्रैक्ट से दवाइयां खरीदी जाएंगी। अगर कोई दवाई स्टेट कॉंट्रैक्ट में उपलब्ध नहीं है तो वह सी0पी0एस0यू0 से खरीदी जाएगी। उसके

28.03.2026/1555/av/yk/3

पश्चात अगर वह दवाई सी0पी0एस0यू0 में भी उपलब्ध न हो तो वह ई0एस0आई0 से खरीदी जाएगी। यहां पर

टी सी द्वारा जारी

28.03.2025/1600/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

डॉ0 जनक राज... जारी

भी यदि उपलब्ध नहीं है तो वह जनऔषधि से खरीदी जाएगी और यदि वहां भी उपलब्ध नहीं है तो लोकल मार्केट से खरीदी जाएगी। मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी सिविल सप्लाई का जिक्र नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज क्यों स्टेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को दरकिनार करके सिविल सप्लाई के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेज में खरीद की जा रही है? इसके पीछे क्या कारण है? मैं एक बात कहना चाहता हूं और इसका अर्थ बहुत बड़ा निकलेगा कि क्यों सिविल सप्लाई के माध्यम से भ्रष्टाचार के दीपक की ज्योति जलाई जा रही है? आपने राजनीतिक आधार पर पूर्व की स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को गिराने का प्रयास किया है। यह स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान है। इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार अपने दिए गए वक्तव्य पर खेद प्रकट करे और अपने शब्दों को वापिस लें।

सभापति महोदय, अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित कुछ विषय रखना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में आज भी अल्ट्रासाउंड के लिए पांगी की महिलाओं को या तो जम्मू जाना पड़ता है या कुल्लू आना पड़ता है। चूड़ी अस्पताल की बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है। वर्ष

1980 में ही इसे जर्जर घोषित कर दिया गया था। एन0एच0पी0सी0 ने इसके लिए पैसा भी उपलब्ध करवाया है लेकिन उस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। हालांकि वह सी0एच0सी0 है लेकिन वहां केवल एक डॉक्टर है। डेंटिस्ट के पद 15 वर्षों से खाली हैं। हमने एन0एच0पी0सी0 से बात करके अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध करवाई और सरकार ने एक डॉक्टर को प्रशिक्षण भी दिया लेकिन उसे वहां से स्थानांतरित कर दिया गया जिससे वहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भरमौर और होली की स्थिति भी इसी प्रकार से है।

सभापति महोदय, हम विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। संविधान ने हमें विशेष अधिकार दिए हैं। मुझे स्मरण है कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था तब रोजगार

28.03.2025/1600/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

से संबंधित विज्ञापनों में पांगी और भरमौर के लिए अलग अंतिम तिथि निर्धारित होती थी। हमें संविधान ने विशेष दर्जा दिया है लेकिन आज सरकार द्वारा उन विशेष अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है। हमें न तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल रही है और न ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहां के लोग भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा हैं, वे ओल्ड हिमाचल का हिस्सा है और वे भी प्रदेश की जी0डी0पी0 में योगदान देते हैं। यदि मुझे सजा देनी है तो दे दीजिए, मेरे साथ राजनीति करनी है, करें लेकिन क्या मेरे चुनाव क्षेत्र के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। सरकार की वर्तमान कार्यशैली से भविष्य में सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे ये मैं स्पष्ट तौर पर कर रहा हूं।

सभापति महोदय, एक बात बार-बार कही जाती है कि रोबोटिक सर्जरी लाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज का केवल ऑपरेशन ही होता है? क्या बिना ऑपरेशन के इलाज संभव नहीं है? ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज दवाइयों से होता है लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज लोग कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया जैसी बीमारियां हैं जिनसे

लोग प्रभावित हैं। इस बार बजट में कहा गया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट खोली जाएगी लेकिन इसके लिए पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ उपलब्ध नहीं है।

आपने पिछले बजट में कहा था कि टांडा में 10 कैथ लैब खोली जाएंगी लेकिन टांडा की कैथ लैब में डॉक्टरों के एक बार हाल तो पूछ लीजिए कि उनके क्या हाल हैं? वहां डॉक्टरों की स्थिति बहुत खराब है और कई डॉक्टर सरकार के पास नौकरी छोड़ने के लिए आवेदन कर चुके हैं क्योंकि उनको अत्यधिक तनाव में कार्य करना पड़ रहा है। अस्पताल में केवल डॉक्टर ही पर्याप्त नहीं होते, स्वास्थ्य कर्मी भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे वह स्टाफ नर्स हो, लैबोरेटरी टेक्नीशियन हो या एक्स-रे टेक्नीशियन हो। वर्तमान में इन पदों की भारी कमी है। यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया कि अल्ट्रासाउंड और सी0टी0 स्कैन के लिए लंबी डेट मिल रही हैं। डॉक्टर का कार्य रिपोर्ट

28.03.2025/1600/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

करना होता है लेकिन एक्स-रे और सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन द्वारा किए जाते हैं। जब टेक्नीशियन के पद ही खाली हैं तो सुधार कैसे संभव होगा।

सभापति महोदय, आज प्रश्न यह नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी सही है या गलत। आज सवाल यह नहीं है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? हम किस प्राथमिकता को तय करने जा रहे है और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? रोबोटिक सर्जरी एक महंगी तकनीक है। हम इसका स्वागत करते हैं कि सरकार विश्व स्तरीय सुविधा हिमाचल प्रदेश में लाने का प्रयास कर रही है लेकिन इसे एक ही संस्थान में खोला जाए और वहां पर स्टाफ को ट्रेंड किया जाए।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-3-2026/1605/एन0एस0-ए0जी0/1

डॉ0 जनक राज -----जारी

हम बिल्डिंग की बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं। हम केवल छत्त को चमकाने का काम कर रहे हैं जोकि उचित नहीं है। सभापति महोदय, यह प्रायोरिटी मिसमैच है। बेहतर होता कि सरकार अधिकतम लोगों को बुनियादी चिकित्सा सुविधा देने पर विचार करती और फिर उन सुविधाओं पर आती। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि हम सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं और विधान सभा के कर्मचारी भी हैं, ये विधान सभा की डिस्पेंसरी में कभी-कभी इलाज करवाने जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरे दांत में दिक्कत हो गई और मैं यहां डिस्पेंसरी में दिखाने के लिए चला गया। जब मैं डैंटल चेयर पर लेटा तो मेरी टांगे ऊपर को हो गई। मैंने कहा कि ये क्या है? तब उन्होंने कहा कि यह कुर्सी ऐसी ही है। जब विधान सभा की डिस्पेंसरी का ही यह हाल है तो अन्य स्थानों की बात छोड़ें। इसको कहते हैं दीपक तले अंधेरा। जब दांत को देखने के लिए मुंह खोला गया तो ऊपर से पेंट उखड़ कर मुंह में गिर गया। मैंने उनको कहा कि यह क्या है? फिर मैंने पी0डब्ल्यू0डी0 विंग, विधान सभा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब, हम इसमें पेंट करने के लिए टेंडर लगा रहे हैं। यह तो हालात हैं और हम दूर-दूर की बातें कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। बिस्तर भी कम हैं। एक बिस्तर पर 2-3 मरीज रखे गए हैं। अस्पतालों में एंबुलैंस नहीं है। मरीजों की लंबी लाइनें लगी है। मैं यहां पर पालमपुर अस्पताल की बात करना चाहूंगा। वहां पर सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ई0एन0टी0 स्पैशलिस्ट, आई सर्जन हैं परन्तु वहां पर एनेस्थीस्ट नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले पालमपुर गया था मुझे तब मालूम पड़ा। मुझे डॉक्टर बताते रहते हैं क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से हूं। हमने फौजी खड़े कर दिए लेकिन उनके पास बंदूकें नहीं दीं। वहां पर एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है और हम सर्जन को विशेष तौर पर ऐसी जगह पर लगा रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि विशेष तौर पर सर्जन को ऐसी जगह ट्रांसफर न करें जहां पर ऑपरेशन थियेटर की सुविधा न हो, चाहे आई सर्जन हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या फिर जनरल सर्जन हो।

सभापति महोदय, इस बजट में सब लोगों की तनख्वाह बढ़ाई गई है। यह अच्छी बात है, तनख्वाह बढ़ानी चाहिए क्योंकि वे अच्छा काम कर रहे हैं। आपने एडस कंट्रोल

सोसायटी के 150 लोगों को दरकिनार कर दिया। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वर्ष 2003-04 से कार्यरत उन 150 लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए सरकार के समक्ष एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति में आने के बाद बड़े सारे राजनीतिज्ञ एक acquired psychological disorder से ग्रसित हो जाते हैं। यह रिसर्च हुई है और मैं कोई अपने से बात नहीं कर रहा हूं। यह रिसर्च है और डॉक्टर्ज इस बारे में जानते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और बाकी लोग भी ढूंढ लें Hubris Syndrome. It is a acquired personality disorder. जब हम सत्ता में होते हैं तो यह बड़े सारे पॉलिटिशयन्स में आ जाता है । उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं बस वही ठीक है और बाकी सब गलत है। इस दृष्टिकोण से सरकार काम न करे क्योंकि यह हिमाचल, यह प्रदेश और यह देश हम सब लोगों से मिलकर बनता है और हम सब लोग इसके बहुत जरूरी घटक हैं। सभापति महोदय, अंत में मुझे कबीर जी का कुछ पंक्तियां याद आई हैंः-

कबीरा कहे हिमाचल से, अजब हुआ व्यवहार,
खुद ही मैं ठीक हूं, बाकी सब बेकार।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद1

सभापति : अब श्री त्रिलोक जम्वाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, मांग संख्या : 9, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के ऊपर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम उस बजट की चर्चा कर रहे हैं, उस कटौती प्रस्ताव की चर्चा कर रहे हैं जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपये का इस बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बजट ही कम है। अगर 1000 करोड़ रुपये का बजट ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कम हो तो उसकी क्या हालत होने वाली है, आप इसका अंदाजा लगाएं। सभापति महोदय, प्रदेश की बातों को जिक्र मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने किया है लेकिन मैं कुछ बातें अपने विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर सदर की आपके समक्ष रखना चाहूंगा।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

28.03.2026/1610/RKS/AS-1

श्री त्रिलोक जम्वाल... जारी

मेरे बिलासपुर के जोनल अस्पताल में प्रतिदिन 7-8 सौ ओ0पी0डी0 रहती है। यह एक पुराना अस्पताल है और यहां प्रतिदिन 7-8 सौ ओ0पी0डी0 रहती है। बिलासपुर में गर्मी भी बहुत अधिक होती है। वहां लोगों को अपनी पर्ची बनवाने के लिए दो से अढ़ाई घंटे तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। यहां हम रोबोटिक सर्जरी और अन्य बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन जब कोई मरीज अपना उपचार करवाने के लिए जाता है तो उसे सबसे पहले पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। प्रदेश सरकार मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए खड़े होने तक की व्यवस्था नहीं कर पाती। आप बड़ी बातें करना तो छोड़ दीजिए। आपने अपने तीनों बजट भाषणों में जो कमिटमेंट की है उसमें से कितनी पूरी हुई है? यदि हम छोटी-छोटी बातें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी जब बिलासपुर के दौरे पर आए थे तो मुझे वहां नहीं बुलाया गया था। वहां शौचालयों की स्थिति बहुत खराब है। ऊपर से पानी टपक रहा है और वहां बहुत अधिक बदबू है। यदि कोई व्यक्ति वहां 5 मिनट तक बिना मास्क के खड़ा हो जाए तो वह चक्कर खाकर गिर जाए। आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये चीजें भी होनी चाहिए परंतु हम बेसिक चीजों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी वहां दौरे पर गए थे। सफाई व्यवस्था के लिए वहां लगभग 14 लाख रुपये का टेंडर आबंटित किया गया था। उस टेंडर में यह शर्त थी कि सफाई कर्मचारी 50 वर्ष की आयु से अधिक न हों। आप जिन कर्मचारियों को सामान नहीं देंगे और जिस ठेकेदार को आप पिछले 4 महीने से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, वह उन कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे क्या सामान देगा? इस स्थिति में वहां क्या सफाई होगी, यह सोचने की बात है। वहां प्रतिदिन 7-8 सौ ओ0पी0डी0 है लेकिन वहां केवल एक ही एम्बुलेंस है। यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं होता। वहां एक भी डेड वैन नहीं है। यदि कोई अप्रिय घटना हो जाए तो लोगों

को टैक्सी लेनी पड़ती है। इस तरह हम किन कल्पनाओं में खोए हुए हैं? हमें मरीजों के मूलभूत दर्द को समझना चाहिए। हमें बेसिक चीजों पर ध्यान देना होगा ताकि उनके बैठने के लिए छाया की व्यवस्था और उनकी पर्ची समय पर बन जाए। जिस एक ऑपरेटर द्वारा 800 पर्चियां बनाई जाती हैं यदि वह एक पर्ची बनाने में एक मिनट का समय लेता है तो 800 पर्चियां बनाने में 800 मिनट लगेंगे तो फिर क्या मरीज 3 घंटे

28.03.2026/1610/RKS/AS-2

तक लाइन में खड़ा रहेगा? इसलिए हमें बेसिक चीजों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें स्वास्थ्य सेवाओं की ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा। हम इस सरकार से बड़ी चीजों की अपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आप छोटी-मोटी सफाई आदि की उचित व्यवस्था तो करवा दीजिए। माननीय मंत्री जी जब बिलासपुर में आए थे तो इन्होंने केवल सी0एच0सी0, पंजगाईं का ही दौरा किया था। पंजगाईं से 2-3 किलोमीटर दूर बरमाणा है जहां कभी एशिया की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन हुआ करती थी। वहां सीमेंट फैक्टरी भी है। वहां जो पी0एच0सी0 खोली गई थी उसे इस सरकार ने बंद कर दिया है। वह एक एक्सिडेंट-प्रोन एरिया है। माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी है कि पंजगाईं में 3 डॉक्टर तैनात थे। जब मंत्री जी वहां आए थे, उस समय वे तीनों डॉक्टर सी0एच0सी0, पंजगाईं में तैनात थे लेकिन 15 दिनों के बाद वे तीनों डॉक्टर वहां से ट्रांसफर हो गए। प्रश्न में पूछा गया था कि 'सी0एच0सी0 में कितने डॉक्टर नियुक्त हैं'। इसके उत्तर में लिखा गया है कि '3 डॉक्टर तैनात हैं'। यह भी लिखा गया है कि उस सी0एच0सी0 में 'तीन स्वीकृत पद हैं और तीन डॉक्टर कार्यरत हैं' जबकि वर्तमान में वहां डॉक्टरों की संख्या शून्य है। बाघा अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्टरी

श्री बी0एस0द्वारा जारी

28.03.2025/1615/बी.एस./ए.एस.-1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

जो है, सारा ट्रैफिक वहां से आता है। दूसरी तरफ बरमाणा है। आप इसका मतलब इस सी0एच0सी0 को बंद करना चाह रहे हैं, क्यों? मेरे बिलासपुर के लोगों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? एक भी डॉक्टर जिस सी0एच0सी0 में न हो, वह सी0एस0सी0 कितने दिन चलेगी? यह प्रश्न के उत्तर में दिया है। मंत्री जी के रेफरेंस के लिए मैं कहूंगा कि यह प्रश्न संख्याः 3913 है और इसमें लिखा है कि सी0एस0सी0 पंजगांईं में कितने डॉक्टर्ज और कितनी सैंक्शन पोस्टे हैं, 3, कितने पोस्टिड हैं,जीरो। खाली पद, तीन। मैंने कहा सी0एच0सी0 बरमाणा जहां एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है और जो पंजगांईं हैं वहां 8 पंचायतें हैं। चाहे मेरी सोलगुजरासी है, चाहे द्रौबड़ है, चाहे धार की पंचायत है, मेरी धौनकोठी है, बरमाणा की उरले वाली बेरी पंचायत है, पंजगांईं पंचायत है और दयोली है। सारी पंचायतों के लोग उसी एक सी0एस0सी0 में आते हैं। आपने उसको भी बंद कर दिया।

इसको बंद ही नहीं किया, मंत्री जी आप वहां आए थे। दूसरे प्रश्न के जवाब में आपने दिया है कि वहां हमारी सरकार ने भवन निर्माण करने के लिए 3.86 करोड़ रुपये दिए थे और यह 3 साल पहले दिये थे। जब आप जनवरी 2025 में आए थे, आपके आने के बाद जो पहली किस्त जारी हुई थी वह 3.66 करोड़ रुपये दिए थे। उसमें से 86 लाख रुपये रिलीज हो गए थे लेकिन आपने जवाब दिया है, प्रश्न संख्याः 4010 में, जिसमें आपने कहा है कि हमने सी0एच0सी0 पंजगांईं का पैसा है यह सारा डायवर्ट कर दिया है, क्यों? मेरे बिलासपुर के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? आप एक सी0एच0सी0 में गए आपने तीनों डॉक्टर बदल दिए। आपने जो भवन बनाने के लिए पैसा दिया था उसको भी सारे को ट्रांसफर कर दिया। यह मेरे प्रश्न का उत्तर है।

दूसरी, सी0एच0सी0 मेरी कुठेड़ा है। उस कुठेड़ा की सी0एच0सी0 का पैसा भी डायवर्ट कर दिया गया। देना तो दूर की बात, आपने प्रश्न के जवाब में दिया है कि 3.66 करोड़ रुपये 3 वर्ष पहले सैंक्शन हुआ था और मेरी सी0एच0सी0 कुठेड़ा जो दूसरी सी0एच0सी0 है उसका भी आपने 86 लाख रुपये किसी दूसरे जिले में भेज दिया, क्यों? क्या बिलासपुर में लोग नहीं रहते? और जिन्होंने जो दो सी0एच0सीज0 के लिए पैसा सैंक्शन किया था, क्या उन्होंने गलत किया था?

28.03.2025/1615/बी.एस./ए.एस.-2

मैं तो आदरणीय सुख राम चौधरी जी की बात पर थोड़ा मुस्कुरा रहा था। वह कह रहे थे कि मंत्री जी एक बार पांवटा साहिब भी आ जाएं। मैंने कहा मेरे यहां एक ही बार आए हैं तो तीन डॉक्टर ट्रांसफर हो गए जहां बैठे थे और 7 करोड़ रुपये के आसपास पैसा ले गए। मैंने कहा, दोबारा तो नहीं चाहिए। हम चला लेंगे, गुजारा कर लेंगे। आदरणीय सुख राम चौधरी जी को शायद इस बात का भी पता नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या हो सकता है? जहां सरकार विंडिक्टिव एटीट्यूड से काम कर रही है। मंत्री जी ने भाषण बहुत दिया था और वहां कहा था कि काम 2 दिन में शुरू हो जाएगा। काम शुरू तो दूर की बात साढ़े तीन सालों में काम शुरू नहीं कर पाए लेकिन मेरी पंजगांईं और कुठेहड़ा दोनों सी0एच0सी0 का पैसा यह सरकार ले गई और अपने चेहतों को देने के लिए ले गई। क्या बिलासपुर में गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है? क्या गरीब की आवाज रखने वाला कोई आदमी नहीं है? यह सारा प्रश्नों के जवाब में दिया है।

सभापति महोदय, जहां मैंने कहा, एशिया की जो एक टाइम में सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन थी पहले वहां पी0एच0सी0 बंद की। उसके 2 किलोमीटर पर सी0एच0सी0 थी उसके तीनों डॉक्टर बदल दिए। भवन का पैसा लेकर चले गये, 8 पंचायतों के लोगों का जो इलाज करती थी और साथ में जो अल्ट्राटेक से जुड़े लोग हैं वे वहां पर आते थे। उन सबका इलाज भी प्रभावित कर दिया। आप करना क्या चाहते हैं? उनको किस बात की सजा दी जा रही है? क्या उन्होंने भाजपा का विधायक जिताया, इसलिए। मैंने कहा था कि सरकार को अपना आईना देखना चाहिए। हम स्वास्थ्य की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। जो आपने मुझे जवाब दिया है मंत्री जी, प्रश्न संख्याः 3913 में उसी के जवाब में मेरे ढयारा में, मैंने कहा था कि सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन छोटा सा काम भी कर सकती।

मेरे ढयारा में, इसमें लिखा है कि आपके पास सफाई कर्मचारी, कोई नहीं है। मेरी रोडा की पी0एच0सी0 है डेंटल डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बड़ी ओ0पी0डी0 है। लेकिन एक्स-रे मशीन नहीं है। अब वह क्या करेगा? जब एक्स-रे नहीं होगा तो डॉक्टर क्या करेगा? मैंने पूछा कि सफाई कर्मचारी कितने हैं? सैंक्शन पोस्ट कितनी है, एक। क्लास फोर की पोस्ट कितनी हैं, एक और भरी कितनी है? जीरो।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

28.03.2026/1620/DT/DC-1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

मैंने पूछा की सफाई कर्मचारियों की सैंक्शन्ड पोस्टस कितनी है तो उत्तर दिया कि केवल एक पद सैंक्शन्ड है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का केवल एक पद है। इनमें से कितने पद भरे हैं तो उत्तर है कोई नहीं। क्या अब हस्पताल में डाक्टर या फार्मासिस्ट झाड़ू लगायेगा? जब आप हस्पतालों में बेसिक चीजे ही प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे तो आप क्या करेंगे? भूल जाइए एम0डी0 डाक्टर, भूल जाइए एम0बी0बी0ए0 डाक्टर्ज। हस्पतालों में सफाई की उचित व्यवस्था हो इतना तो सरकार इंशयोर कर ले। मेरे विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थान कुंभजाड़ में सफाई कर्मचारी का पद शून्य। यह संस्थान पी0एच0सी0 है, यहां पर सफाई व्यवस्था कौन देखेगा-उसका कोई पता नहीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान तल्याणां हैं उस स्वास्थ्य संस्थान में पानी टपकता रहता है और सफाई कर्मचारी वहां पर भी नहीं है। जिस कक्ष में इंजैक्शन्ज लगाये जाते है और जिस बैड में लेटाकर इंजैशन लगाया जाता है वह बेड भी उपलब्ध नहीं और एक बेंच में बिठाकर पेशेंट को इंजैक्शन लगाया जाता है लेकिन कहने को वह आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। सरकार के द्वारा बड़ी-बड़ी बातें इस सदन में कही जाती है पर वास्तव में स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति क्या है? अगर प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दें तो गरीब को उसका लाभ होगा। सरकार कह रही है कि हिमकेयर में 100 करोड़ रुपये का फ्रॉड हुआ है। इस बात को कहते-कहते सरकार को साढ़े तीन साल हो गये और हम पहले दिन से ही सुन रहे हैं कि हिमकेयर में फ्रॉड हो गया। अगर हुआ था तो सरकार ने इन साढ़े तीन सालों में क्या किया? बस एक काम किया कि विजिलेंस को आर0टी0आई0 के दायरे से बाहर किया।

मेरे विधान सभा के स्वास्थ्य संस्थान,मल्यावर में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्स में लगी है लेकिन उसे पांच महिने से वेतन नहीं दिया गया है। सरकार किस प्रकार की व्यवस्था की बात कर रही है? मेरे विधान सभा के बागीसुंगल में सफाई कर्मचारी नहीं है, मैं

इस सदन में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक ही विषय पर बोल रहा हूं, वहां एक पद स्वीकृत है लेकिन वे पद रिक्त है। मेरे विधान सभा के स्वास्थ्य संस्थान मंडी मांणुआ में और हरलोग मो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसके ऊपर सरकार की नजर नहीं पड़ी नहीं शायद अभी तक यह संस्थान भी बंद हो जाता,

28.03.2026/1620/DT/DC-2

इसमें सेवारत डाक्टर भी कहीं और भेज दिए जाते। हरलोग में सफाई कर्मचारी का एक पद स्वीकृत है लेकिन वह भी रिक्त है। बाकि सारी बातें छोड़ दें। कुठेड़ा का वृतांत तो मैंने कर ही दिया है। मोरसिंगी में एक पी0एच0सी0 का कार्य पिछले साढ़े तीन सालों में 90-95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। माननीय मंत्री जी ने मुझे पिछली बार भी आश्वस्त किया था कि अगले 10 दिनों में शेष कार्य शुरू हो जाएगा लेकिन वह स्ट्रक्चर वहीं खड़ा है। मैंने पंजगाईं सी0एच0सी0 का भी आपके समक्ष जिक्र किया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि आप जिन संस्थानों को बंद कर रहे हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद न करें। आप पहले वहां से डॉक्टर्ज को हटाते हैं जब डॉक्टर्ज न हो तो वहां लोग अपना उपचार करवाने के लिए नहीं जाते। फिर आप कहते हैं कि वहां ओ0पी0डी0 नहीं है इसलिए हमें इस संस्थान को बंद करना पड़ा। आप सीधा कह दीजिए कि आपसे यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आपने जैसे एक लाइन का ऑर्डर 12 दिसम्बर, 2022 को किया था कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार के अंतिम एक वर्ष में जितने भी संस्थान खोले गए हैं उन्हें डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। आप इस तरह सिम्पल ऑर्डर कर दें लेकिन गरीब आदमी को सताना ठीक बात नहीं है। गरीब आदमी अपना उपचार करवाने के लिए सी0एच0सी0 में जाता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो वे हमें गालियां देते हैं। सभापित महोदय, गरीब की हाय बहुत बूरी होती है। वह इसके बारे में किसी को नहीं बोल सकता परंतु वह मर जाएगा। हम लोगों का जमीर कहां चला गया जब हम एक ऑर्डर से तीन-तीन डॉक्टरों को बदल रहे हैं। जबलयाणा में लोगों की सेवा के लिए एक हैल्थ सेंटर खोला गया था लेकिन इस सरकार ने उसे भी बंद कर दिया है। फिर हम इस हाउस में किस चीज की चर्चा करेंगे। हैल्थ सैक्टर सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए होस्पिटल जाना पड़ता है लेकिन प्रदेश सरकार का

ध्यान इस ओर नहीं है। हम कल चिट्टे पर चर्चा कर रहे थे। कल सरकार की ओर से यह कहा गया कि हम रिहैब्लिटेशन सैंटर खोल रहे हैं। हम इस बात को साढ़े तीन वर्षों से सुन रहे हैं। मैंने एक प्रश्न के माध्यम से यह पूछा था कि क्या बिलासपुर में रिहैब्लिशन सैंटर खोलने का विचार है। इसके उत्तर में कहा गया है कि 'कोई विचार नहीं है।' यहां पर चर्चा के ऊपर चर्चा हो रही है लेकिन इस पर एक्शन जीरो है। अगर

28.03.2026/1620/DT/DC-3

कोई चिट्टे में पकड़ा जाता है या इसकी जद में आ जाता है तो हम उसे कहां ले जाएंगे? सरकार भाषण तो बड़े-बड़े दे रही है कि हमने

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

28.03.2026/1625/डी.सी.-एन.जी./1

श्री त्रिलोक जम्वाल..... जारी

PITNDPS शुरू कर दिया लेकिन बेसिक सुविधाएं कहां हैं? स्वास्थ्य एक बेसिक सब्जैक्ट है और प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से दोनों हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोगों व कुछ छुटभैया नेताओं के कहने पर प्रदेश सरकार काम कर रही है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है और यह गरीबों के हित में नहीं है। अगर आप गरीब को तरसाओगे तो उसकी हाय बहुत दूर तक जाती है। वह कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन उसकी हाय जरूर लगती है। इसलिए मैं केवल इतनी मांग करना चाहता हूं कि जैसे कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे में मैमोग्राफी टेस्ट बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि हम इसकी जल्द व्यवस्था करने वाले हैं। यह एक छोटा सा एक्स-रे जैसा टेस्ट होता है, लेकिन हम उसे भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बड़े-बड़े टेस्ट तो दूर की बात है अगर प्रदेश सरकार इस तरह की छोटी-छोटी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा देगी तो कैंसर के मरीजों को पहले ही

बीमारी का पता चल सकता है और हमारी माताओं-बहनों को इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यह बहुत छोटा और सरल टेस्ट है। हम जब भी मैडिकल कैंप लगाते हैं, जैसे मैं 5 तारीख को भी एक कैंप लगाने जा रहा हूं तो उसमें हमने एक एन0जी0ओ0 से कहा तो उन्होंने कहा कि हम अपनी वैन उपलब्ध करवा देंगे और आप टेस्ट करवाइए। लेकिन प्रदेश सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है, जबकि यह एक छोटा-सा मैमोग्राफी टेस्ट है, जोकि बहुत सरलता से कराया जा सकता है, उसको भी नहीं करवा पा रही है। अगर सरकार चाहे तो इसे आसानी से करवा सकती है ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2026/1625/डी.सी.-एन.जी./2

सभापति : अब कटौती प्रस्ताव की चर्चा में माननीय सदस्य, श्री पूर्ण चन्द ठाकुर भाग लेंगे।

श्री पूर्ण चन्द ठाकुर : सभापति महोदय, मांग संख्या - 9 : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कट मोशन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं जोनल हॉस्पिटल मंडी की बात करना चाहता हूं। जोनल हॉस्पिटल मंडी बहुत पुराना अस्पताल है, जोकि राजाओं के समय का है। मुझे लगता है कि वहां पर स्टाफ भी लगभग पूरा है। लेकिन एक बात का मुझे अफसोस है कि जब कोई भी मरीज रात या दिन में वहां पर जाता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है। पहले उसे मैडिकल कॉलेज भेजा जाता है, उसके बाद वहां से आई0जी0एम0सी0, शिमला और फिर आगे पी0जी0आई0 चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता है।

सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे डॉक्टरों को इस संबंध में कोई निर्देश जारी करें कि गरीब मरीज जोकि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं, उनका यथासंभव इलाज वहीं पर किया जाए। यदि किसी विशेषज्ञ की कमी है तो वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी नियुक्ति की जाए। मैं खासकर अपने दरंग चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरा दरंग चुनाव क्षेत्र तीन हिस्सों में बंटा हुआ है। यह एक पिछड़ा चुनाव क्षेत्र है, जहां पर हमारी लगभग 71 पंचायतें हैं। इन 71 पंचायतों में से लगभग 50 पंचायतें ओ0बी0सी0 व बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आती हैं। लेकिन वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर यदि नजर डालें, तो हमारे क्षेत्र में दो सिविल हॉस्पिटल, दो सी0एच0सी0 और आठ पी0एच0सी0 हैं। इन पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 और सी0एच0 में कुल मिलाकर लगभग 231 पद स्वीकृत हैं, लेकिन खेद की बात है कि उनमें से लगभग 85 पद खाली पड़े हुए हैं।

28.03.2026/1625/डी.सी.-एन.जी./3

यह बहुत ही अफसोस की बात है। मेरे दरंग चुनाव क्षेत्र में 43 हेल्थ सब-सेंटर्स हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, यदि आप देखेंगे तो 43 हेल्थ सब-सेंटरों में मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर की कुल 86 पोस्टें स्वीकृत हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन 86 में से 43 मेल हेल्थ वर्कर की पोस्टें हैं और उनमें से मात्र एक मेल हेल्थ वर्कर ही कार्यरत है और बाकी सभी 42 पद खाली पड़े हुए हैं। जो एक कर्मचारी है, वह भी न जाने किस प्रकार से बचा हुआ है। फीमेल हेल्थ वर्कर के भी 43 पद

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

28.03.2026/1630/एच0के0/ए0पी0/-01

श्री पूर्ण चन्द ठाकुर जारी .....

है। इन 43 पोस्टों में 20 पोस्टों को भरा गया है लेकिन अभी 23 पोस्टें खाली हैं। अगर में मेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर की बात करूं तो मेरे विधान सभा में 86 पोस्टों में से 65 पोस्टें खाली चल रही हैं। अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा हाल होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के गरीब लोग रहते हैं। जब हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं होगा, हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर नहीं होंगे तो गरीब मरीज कहां जाएगा? (भगवान करे कि बड़ी बीमारी किसी को न हो) लेकिन अगर हो जाए तो वह कहां जाएगा? यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे दरंग विधान सभा क्षेत्र में सभी कैटेगरी की कुल 317 पोस्टें स्वीकृत हैं और उन 317 पोस्टों में 150-से-167 पोस्टें खाली हैं। मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जहां स्टाफ नहीं होगा, वहां की जनता का क्या हाल होगा? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारा सी0एच0सी0 पधर जोकि दरंग विधान सभा क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। इसके अंतर्गत लगभग 40 पंचायतें आती हैं। इन 40 पंचायतों में सभी पंचायतें पिछड़ी हुई हैं। वहां पर जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वह बहुत पुरानी हो चुकी है। वह बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रही है। वहां हर दिन सैकड़ों मरीज आते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वहां जल्द-से-जल्द नई अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाई जाए या उस पुरानी मशीन को ठीक किया जाए। दूसरा, हमारा सी0एच0सी0 बरोट है। बरोट में कुल हमारी 20 पोस्टें हैं, जिनमें से 8 पोस्टें खाली हैं। यह चोहार घाटी का अंतिम पंचायत क्षेत्र है। इसके आगे बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र आता है। अगर एक पिछड़े क्षेत्र में यह हाल है तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर आप बजट का उचित प्रावधान करें। पिछड़े क्षेत्रों में बिल्डिंग्ज की भी सुविधा नहीं है। बरोट में भी सी0एच0सी0 की अपनी बिल्डिंग नहीं है। वहां पर 30 बेड का अस्पताल है लेकिन 30 बेड में से सिर्फ 6 बेड ही लगे हुए हैं। इसलिए वहां भवन निर्माण की व्यवस्था की जाए। तब जाके हमारी चोहार घाटी का सुधार होगा। पधर सिविल अस्पताल से बरोट लगभग 40 किलोमीटर दूर

28.03.2026/1630/एच0के0/ए0पी0/-02

है और सुधार भी 40 किलोमीटर दूर है। वहां 10 पोस्टों में से 6 पोस्टें खाली हैं। इन पदों को भी जल्द-से-जल्द भरा जाए। इसी तरह पी0एच0सी0 पाली भी सड़क के किनारे ही है। वहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, लेकिन वहां भी 7 पोस्टों में से 3 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी आपने चोहार घाटी, बरोट, टिक्कन के सुधार के लिए तीन डॉक्टरों के ऑर्डर किए थे मगर उन ऑर्डरों को अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि आज अधिकारी मुख्य मंत्री जी के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। अगर मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का नोट अप्रूव हुआ है और उस आदेश पर भी डॉक्टरों को नहीं लगाया गया तो यह अच्छी बात नहीं है। उन ऑर्डरों को लागू होना चाहिए था मगर किस कारण वे ऑर्डर लागू नहीं हुए, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। इसी तरह पी0एच0सी0 बड़ीधार दुंदा क्षेत्र में आती है। वहां की सभी पंचायतें पिछड़े क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। वहां 7 पोस्टों में से 4 पोस्टें खाली चली हुई हैं। इसी तरह बड़ीधार में भी 7 पोस्टों में से 4 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। चुक्कू में 2 पोस्टें इस समय खाली हैं। इसी तरह हमारे सी0एच0सी0 कटोला है वहां पर कुल 34 पोस्टें स्वीकृत हैं, जिनमें से 15 पोस्टें इस समय खाली हैं। इनमें 3 मेडिकल ऑफिसर के पद भी खाली हैं। यह हमारे उत्तरशाल क्षेत्र का केंद्र बिंदु है और यह एक इंटीरियर इलाका है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

28.03.2026/1635/AT/HK/01

श्री पूर्ण चन्द ठाकुर जारी...

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी विधान सभा क्षेत्र का एक दिन का दौरा करें। मैं आपको रोड हेड तक ले जाऊंगा और बरोट, सुधार, नगवाईं और कटौला जैसे स्थानों पर भी लेकर जाऊंगा, ताकि आप वहां के लोगों के हालात स्वयं देख सकें।

हमारे सिविल हॉस्पिटल नगवाईं में 17 पद खाली हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत खराब है। मुझे लगता है कि दरंग क्षेत्र के साथ यह भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? मैं आपसे बस इतना ही कहुंगा कि आप यह भेदभाव हमारे साथ न करें। और इस तरह शिवाबदार वाला क्षेत्र भी एक पिछड़ा इलाका है, जहां 6 पोस्ट में से केवल 2 पोस्टें भरी हुए हैं और 4 पोस्टें अभी खाली हैं। यह चिंता का विषय है। इसी तरह पी0एच0सी0 बथेरी में भी 6 पोस्टें में से 3 पोस्टें अभी खाली चल रही हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं अपने क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति बहुत खराब है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा हेल्थ सब सेंटर, कटौला लगभग 15 किलोमीटर दूर है लेकिन वहां पर उस स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं है। भवन के लिए पैसा मंजूर हो चुका है और टेंडर भी हो चुका है लेकिन अभी तक वहां काम शुरू नहीं हुआ। कृपया विभाग से इसकी जानकारी लें।

इसी तरह ग्राम पंचायत उरला में हेल्थ सब सेंटर है जो गैल गांव में है और गांव वहां से काफी दूर है। इस स्वास्थ्य संस्थान में लोगों को पैदल जाना पड़ता है। वहां भी टेंडर हो चुका है लेकिन अभी तक वह किराये के भवन में चल रहा है। इसके बारे में भी मंडी के सीएमओ और संबंधित अधिकारियों से पूछा जाए कि काम क्यों नहीं हो रहा है। इसी तरह पीएचसी पदवान, जो दुंदा क्षेत्र में आता है, वहां भी पैसे की कमी है। कृपया वहां के लिए भी धन उपलब्ध करवाया जाए। इसी तरह आयुर्वेदिक भवन बागी में है जहां वर्ष- 2023 और वर्ष-2025 में त्रासदी हुई थी वहां की डिस्पेंसरी अभी तक नहीं बनी है। वर्ष-

28.03.2026/1635/AT/HK/02

2023 में मंत्री जी वहां आए थे और एक महीने में काम शुरू करने का आश्वासन दिया था लेकिन तीन साल बाद भी कोई काम नहीं हुआ। इसी प्रकार सोलंग और बंबोला में हेल्थ सेंटर के टेंडर सात साल पहले हो चुके हैं और यह काम मैकेनिकल को गया है लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन कामों को जल्द शुरू

करवाया जाए। इसी तरह प्राइमरी हेल्थ सेंटर जवालापुर जो सनोर क्षेत्र में है उसकी ओपनिंग 10 साल पहले हुई थी लेकिन वह आज भी किराये के भवन में चल रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि वहां पर भी भवन बनाने की कृपा करें क्योंकि वहां से लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड मशीनों का मैंने पहले भी जिक्र किया है उन्हें भी ठीक किया जाए। क्योंकि स्नोर क्षेत्र की 21 पंचायतों के लिए केवल एक ही सिविल हॉस्पिटल है जहां रोज सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय मंत्री महोदय इसका ... (व्यवधान) नहीं, अब बोलना ठीक है,

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

28.03.2026/1640/केएस/वाईके/1

अध्यक्ष जारी ---

हंस राज जी, इसमें आपका नाम ही नहीं है। मुख्य लिस्ट में तो ठीक है परंतु इन्होंने लिस्ट रिवाइज़ कर दी थी। आप तो डिप्टी स्पीकर रहे हैं। चलो, वैसे मैं आपको अनुमति दे सकता हूं परंतु जबरदस्ती की बात नहीं है। 5 से 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें क्योंकि अभी मंत्री जी ने भी जवाब देना है ।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या : 9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। मेरे से पूर्व साथियों ने पूरे स्टेट की स्वास्थ्य से जुड़ी सारी बातें कही हैं मैं तो सिर्फ चम्बा मैडिकल कॉलेज की बात करना चाहता हूं। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी सही तरीके से, सटीक तरीके से मैडिकल कॉलेज चम्बा को चला देंगे तो पूरे जिला को उसका लाभ मिलेगा और

हमें उस तरफ जाना चाहिए। आपने कहा कि हम पूरे प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। चम्बा भी इसी प्रदेश में आता है इसलिए आप उसकी तरफ भी ध्यान दें।

दूसरा, मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारी सी0एच0सी0 तीसा प्रतिदिन 250 से 300 तक की ओ0पी0डी0 जनरेट करती है लेकिन पिछली बार श्री जय राम ठाकुर जी के समय में हमारी सरकार ने इस सी0एच0सी0 को 50 बैड से 100 बैड किया था और यह भी तय किया था कि इसकी बाकायदा बिल्डिंग बनेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह 53 पंचायतों को फीड करती है। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की आपने बात की है। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि अभी लगभग पूरे प्रदेश की सी0एच0सीज़0 में डायलिसिस सैंटर शुरू होंगे और इसमें तीसा का भी नाम आया है। भटियात की कुछेक सी0एच0सीज़0 का नाम भी है। उनसे हमारे दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है, हमारी दो महत्वपूर्ण सी0एच0सीज़0 डीनोटिफाई की थी। जो हमने बैरागढ़ की सी0एच0सी0 खोली थी वह 10 पंचायतों को फीड करती और कोहाल की लगभग 7 पंचायतों को फीड करती अगर उनको डीनोटिफाई नहीं किया होता। हमारी पुखरी की पी0एच0सी0 बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन है। वहां पर पहले हमारी सरकार के समय चार-चार, पांच-पांच डॉक्टर्ज़ होतजे थे। तीसा में भी 17-17 डॉक्टर थे लेकिन

28.03.2026/1640/केएस/वाईके/2

अभी 3 से 4 डॉक्टर ही रह गए हैं। मेरा इस मांग के माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि हमारा राजनगर, मसरूंड, कलेहल के जो मेन पी0एच0सीज़0 के जंक्शन हैं, वहां पर पैरा मैडिकल और मैडिकल स्टाफ होना बहुत जरूरी है। दूसरा नकरोड़ और तुंगाला में जो हमारी पी0एच0सी0 है, उसको भी और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसी तरह से झजा की पी0एच0सी0 को भी स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने इस मांग के माध्यम से मुझे बोलने का समय दिया, मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी, कृपया अटैंशन दें। जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की आप बात कर रहे हैं सी0एच0सी0 तीसा बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके साथ-साथ पुखरी और और राजनगर की

पी0एच0सीज़0, वैसे तो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन वहां पर पर्याप्त सिरिंज तक नहीं मिल रही थीं और पीछे तो दवाइयों के भी हालात खराब थे। मुझे इतना ही कहना था, आपने समय दिया, धन्यवाद।

28.03.2026/1640/केएस/वाईके/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव माननीय विपक्ष के साथियों ने लाया है जिसमें सर्वश्री जय राम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, डॉ0 जनक राज आदि कई माननीय सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले साढ़े तीन सालों से हमने मैडिकल एजुकेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। पिछली सरकार ऐसी व्यवस्था छोड़कर चली गई थी जहां मैडिकल एजुकेशन की ओर कुछ समय तक ध्यान दिया गया और उसके बाद इसको अचेत अवस्था में छोड़ दिया गया। मेरे पास मैडिकल एजुकेशन का डिपार्टमैंट होने के नाते और वित्त मंत्री होने के नाते

श्रीमती अव द्वारा जारी ---

28.03.2026/1645/av/yk/1

मुख्य मंत्री------जारी

मैंने उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं। वे परिवर्तन ग्रास रूट स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक किए गए। यहां पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बातों को रखा है, मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं।

ठीक है, आप राजनीतिक रूप से भाषण देते हैं। श्री जय राम ठाकुर जी पिछली सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं और ये वित्त के संदर्भ में सब कुछ जानते हैं। परंतु ये अपनी बात को हमेशा तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं और हमारे बारे में टिप्पणी करते रहते हैं। ये हमारे जोश को विद्यार्थी जीवन का जोश बताते हैं। परंतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे

जोश को एक युवा जोश से जोड़ा और तभी स्वास्थ्य क्षेत्र में कई क्रान्तिकारी परिवर्तन हो पाए।

अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार फैसला नहीं कर पाती थी। इनकी सरकार शाम को एक फैसला लेती थी और दूसरे दिन उस फैसले को बदल देती थी। लेकिन हम फैसला भी करते हैं और उसको अमलीजामा भी पहनाते हैं। इनकी सरकार ने चम्बा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजिज को किस हालत में छोड़ा, मैं उसके बारे में सदन के अंदर बताना चाहता हूं। चम्बा मेडिकल कॉलेज के लिए 172.19 करोड़ रुपये की राशि हमारी सरकार द्वारा दी गई और उसके फेज़-i के कार्य को पूरा किया गया। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी और श्री जय राम ठाकुर जी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जबकि वह हमें श्री गुलाम नबी आज़ाद जी द्वारा दिया गया था। मैं यह बात बार-बार इसलिए कहता हूं कि उसका डॉ0 राधा कृष्णन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी स्वीकृति केवल मेरे द्वारा करवाई गई थी। उस समय श्री कौल सिंह ठाकुर जी स्वास्थ्य मंत्री और श्री विनीत चौधरी सचिव (स्वास्थ्य) थे। रात के 12.00 बजे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर उन्होंने बोला कि आपका जिला एडवांस है, इसलिए मैं आपके लिए यह मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाता हूं। मुझे आज भी याद है कि तीनों मेडिकल कॉलेजिज के लिए 179 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। उस राशि से ये कॉलेजिज नहीं बनने थे। हमने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए 389.95 करोड़ रुपया खर्च किया। आप जिस न्यू ओ0पी0डी0 ट्रॉमा ब्लॉक

28.03.2026/1645/av/yk/2

की बात कर रहे हैं उसके ऊपर तो एन0जी0टी0 ने स्टे लगाया हुआ था। आपने तो उद्घाटन कर दिया परंतु हमने एन0जी0टी0 से परमिशन लेकर उसकी शुरुआत करवाई। चमियाणा सुपर स्पेशलिटी होस्पिटल फंक्शनल नहीं था, उसको भी हमारी सरकार ने फंक्शनल किया और ये सारे सुधार पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं। ...(व्यवधान) यह होस्पिटल माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित है। ये उसके बारे में मुझे बार-बार कहते रहे और हमने उसको पूरी

तरह से शुरू किया। उसके बाद 5 एम0आर0आई0 मशीन्ज ऑर्डर कीं, परंतु जब भी कहीं कुछ पर्चेज किया जाता है तो इनकी भावना पता नहीं किस प्रकार की होती है? मैं बताना चाहता हूं कि हमने कोई भी मशीन अपने आप नहीं खरीदी, हमने उनको भारत सरकार की एजेंसी द्वारा खरीदने के ऑर्डर दिए। ...(व्यवधान) अभी 2 एम0आर0आई0 मशीन्ज आ चुकी हैं और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। उसमें से एक का मैं आई0जी0एम0सी0 में उद्घाटन कर चुका हूं और टांडा व नेरचौक मेडिकल कॉलेजिज के लिए एक-एक मशीन आ चुकी है तथा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है। ये पांचों मशीन्ज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के उपक्रम द्वारा रिकॉमेंड करने के उपरांत खरीदी गई हैं। ...(व्यवधान) कई लोग आपके पास आते होंगे और जिनको नहीं मिलती होगी वे इस तरह की बातें करते होंगे। उसमें सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सम्मिलित नहीं है। वे ऑर्डर देते हैं और हम उसको इंस्टॉल करते हैं। उनको भी इस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं कि जिस प्रकार की मशीन्ज एम्ज में खरीदी जाती हैं उसी प्रकार की मशीन्ज यहां के मेडिकल कॉलेजिज के लिए खरीदी जाएं। अब मैं पैट स्कैन की बात करना चाहूंगा। मैं उस समय विधायक हुआ करता था और आप भी अपने समय में पैट स्कैन लगाना चाहते थे। आप चाहते थे कि पैट स्कैन लगे और मैं आपको बार-बार कहता था कि टांडा और आई0जी0एम0सी0 में पैट स्कैन की मशीन्ज लगाई जाएं। परंतु आपके समय में पैट स्कैन नहीं लगी। लेकिन हमारी एक पैट स्कैन की मशीन आई0जी0एम0सी0 में लग गई है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे-बैठे बोलते हैं। अब तो मुझे लगता है कि ए0बी0वी0पी0 का जोश आपमें

28.03.2026/1645/av/yk/3

आ गया है। परंतु यह कोई फैसला लेने के लिए नहीं आया है अपितु हमारा विरोध करने के लिए आया है। मैं कह रहा था कि हम एक पैट स्कैन की मशीन लगा चुके हैं तथा एक टांडा में भी लगाने जा रहे हैं।

टी सी द्वारा जारी

28.03.2026/1650/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

मुख्य मंत्री... जारी

अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहली बार हुआ है, जब इतिहास के पन्ने पलट कर देखे जाएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि आपने कुछ नहीं किया और जो कार्य किया वह हमने किया। हमने 125 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सृजित किए हैं और 212 फैकल्टी के पद भरे हैं। यह इसलिए किया गया क्योंकि जिस स्थिति में आप मेडिकल हैल्थ व्यवस्था को छोड़कर गए थे, हमने उसे सुधारने का प्रयास किया। मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या थी, इसका यदि गहराई से परीक्षण किया जाए तो स्पष्ट होगा। श्री विपिन सिंह परमार जी मंत्री रहे हैं इन्हें इसकी पूरी जानकारी है और इन्होंने भी सुधार करने का प्रयास किया था। जब इन्होंने सुधार करना शुरू किया तो इन्हें यहां से हटाकर अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर बैठा दिया गया। भविष्य में क्या होगा, यह किसी को ज्ञात नहीं है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, यह कोई नहीं जानता है।

अध्यक्ष महोदय, पहले मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टोरेट ऑफ हैल्थ सर्विसिज का एक ही कैडर होता था और पर्याप्त स्टाफ नहीं होता था। कोई नर्स पी0एच0सी0 में लगी होती थी, राजनीतिक दबाव के कारण, विधायकों के अनुरोध पर उसको मेडिकल कॉलेज में ले आते थे और जब वहां कार्य का दबाव बढ़ता था तो उन्हें ट्रांसफर करके पी0एच0सी0 में भेज दिया जाता था। ओ0टी0ए0, स्टाफ नर्स या एनेस्थीसिया कोर्स करने वाले कर्मचारियों को भी इसी प्रकार ट्रांसफर किया जाता था। मेडिकल कॉलेज की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वहां केवल डॉक्टर ही रह गए थे और सामान्य परिवार का व्यक्ति ही उनके पास उपचार के लिए आता था। आई0जी0एम0सी0 में 1000 लोगों की ओ0पी0डी0 होती थी और उन्हें देखने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता था।

टेक्नोलॉजी की स्थिति भी खराब थी। मैं आपको दोष नहीं देता। जिस एम0आर0आई0 मशीन की बात की जा रही है, वह 19 वर्ष पुरानी थी। उसकी मेंटेनेंस पर इतना खर्च हो रहा था जितना नई मशीन खरीदने पर नहीं आता। 19 वर्ष पुरानी मशीन से

लोगों से 3000 रुपये लिए जाते थे और वह मशीन चलने पर भारी आवाज करती थी। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हमने सबसे पहले कैडर को अलग किया। इसके विरोध में हड़ताल हुई, लोगों ने कहा कि सरकार गलत तरीके से चल रही है। डॉक्टरों ने पेन डाउन

स्ट्राइक की। आपकी ओर से भी बयान आते रहे। आप (नेता प्रतिपक्ष) डॉक्टरों के शुभचिंतक हैं और होना भी चाहिए लेकिन उस समय आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा। यदि उस समय आपने ध्यान दिया होता तो आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति अलग होती। हमने पैरामेडिकल स्टाफ को अलग किया और हड़ताल के बावजूद अपने निर्णय को नहीं बदला। पहले स्थिति यह थी कि तीसरे दिन या कई बार उसी शाम को निर्णय बदल दिए जाते थे। अब स्थिति यह है कि मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी ऑप्शन दे दी है। अब जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वे जनरल अस्पताल, सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 में हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमने मेडिकल कॉलेज की सभी पोस्ट का आकलन किया। मैंने कहा है कि एक वर्ष और दीजिए। हमने अनेक पद सृजित किए हैं। कई बार श्री मुकेश अग्निहोत्री जी कहते हैं कि सभी पद हैल्थ के लिए सृजित किए जा रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि 176 पद ओ0टी0ए0 के लिए सृजित किए गए हैं जो डी0एच0एस0 के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा 500 पद डी0एच0एस0 में सृजित किए गए हैं। स्टाफ नर्स के पद सृजित किए जा रहे हैं और असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 900 पद विशेष रूप से डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के लिए सृजित किए गए हैं। इनके परिणाम भी आने वाले हैं। कुछ मामले न्यायालय में लंबित हैं और न्यायालय में केस होने के कारण यह प्रक्रिया प्रभावित हो रही है लेकिन हमने न्यायालय को भी बताया है कि इससे मेडिकल हैल्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, परिवर्तन हमेशा होता रहता है और यदि यह सोच-समझकर किया जाए तो प्रदेश के हित में होता है। आई0सी0यू0 में सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए हमने प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 40 बेड स्वीकृत किए हैं।

प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर आपने कभी अध्ययन

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-3-2026/1655/एन0एस0- ए0जी0 /1

मुख्य मंत्री -----जारी

नहीं करवाया लेकिन हमने अध्ययन करवाया है। हमने स्टेट में कैंसर इंस्टीच्यूट बनवाया जिसमें हमने टॉप के कैंसर डॉक्टर को उस पैनल में शामिल किया और अध्ययन करवाया। हमें उनकी स्टडी से पता चला कि हमारी जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट के बाद हम दूसरे नम्बर पर कैंसर की वॉल व कैंसर के मरीज बनते जा रहे हैं। हमने इस बारे में सोचा। हमने सोचा कि क्या ऐसी ही व्यवस्था चली रहनी चाहिए? हमारे साथ लोगों ने मांग नहीं की लेकिन हमने खुद सोचा और जो लोगों की समस्याओं के बारे में सोच-समझ कर उनका समाधान ढूंढते हैं उसको ही व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं और हमने 470 पोस्टें कैंसर अस्पताल के लिए स्वीकृत की।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एंबुलैंस की बात की जा रही थी। हमने एडवांस लाइफ स्पॉर्ट सिस्टम की 25 एंबुलैंसिस स्वीकृत की हैं। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि हमें एक वर्ष का समय चाहिए। पहली बार ही एक वर्ष के भीतर एम्स, दिल्ली में जो टेक्नोलॉजी है उस तरह की टेक्नोलॉजी को हम हिमाचल प्रदेश में लाने जा रहे हैं। मैं पी0जी0आई, चंडीगढ़ या एम्स, बिलासपुर की बात नहीं कर रहा हूं। यहां एडवांस ऑटोमेटिड लैब बनेगी। अभी हमारे टैस्ट क्रस्ना लैब से ही हो रहे हैं या किसी और लैब से ब्लड टैस्ट हो रहे हैं। इनमें जो हमारे टैस्ट होते थे उनको कम कर दिया गया। मैंने आर्थिक मंदी के बावजूद भी 25-25 करोड़ रुपये तीन मेडिकल कॉलेजों की लैब रेनोवेशन के लिए दिया है जिसमें आई0जी0एम0सी0, शिमला, सुपर स्पैशियलिटी अस्पताल, चमियाणा और मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर शामिल हैं। इस सुविधा को हम शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज, टांडा और नेर चौक में भी शुरू करने जा रहे हैं। हम इसलिए शुरू करने जा रहे हैं कि जब मरीज का ब्लड सैंपल लिया जाए तो उसमें सब पता चले कि आपको ब्लड प्रैशर है या कोई और बीमारी होने जा रही है। अभी तो ह्यूमैन टैस्ट करते हैं लेकिन ये टैस्ट कंप्यूटराइज्ड होगा और पूरा

पता लगेगा। जब हमें पूरा पता लगेगा कि हमारे में क्या कमी है तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। यहां पर क्रस्ना लैब से जो भी टैस्ट लिया जाता है उसमें कोई-न-कोई बीमारी नज़र आ जाती है। स्वस्थ आदमी को भी ऐसे लगता है कि उसे कुछ-न-कुछ बीमारी है। इसके अतिरिक्त हमने पेथोलॉजी डिपार्टमैंट को मजबूत करने के लिए कुछ विभाग चिन्हित किए हैं। सबसे

28-3-2026/1655/एन0एस0- ए0जी0 /2

पहले मरीज को क्या होता है? वह डॉक्टर के पास जाता है और फिर उसका डायग्नोज शुरू होता है जिसमें देखा जाता है कि उसमें कौन-सी बीमारी है? डायग्नोज के लिए हमें रेडियोलॉजी डिपार्टमैंट और रेडियोथैरेपी डिपार्टमैंट चाहिए और हम उसको विकसित कर रहे हैं। उसके बाद पेथोलॉजी डिपार्टमैंट में सारे ब्लड टैस्ट होते हैं और फिर पता लगता है कि आपको यह बीमारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन हमारे किसी भी मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। हम पहली बार हिमाचल के इतिहास में इसको करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप एक मिनट बैठें। आज के 5.00 बज चुके हैं और मैं सदन की राय ले लेता हूं। वैसे तो रूल्ज में यह प्रोवीजन नहीं है। There is no provision in the Rules; however, the House has the power. Therefore, I am just putting it before the House. If the House agrees, I can extend the House for some time, and this Demand can be disposed of. आपकी सहमति नहीं है। अब मुख्य मंत्री जी आपका जवाब कंटीन्यू रहेगा।

अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, 30 मार्च, 2026 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांकः 28 मार्च, 2026 **सचिव।**